

विकसित भारत समाचार

राष्ट्र निर्माण में प्रयत्नशील

वर्ष : 12 | अंक : 230 | गुवाहाटी | गुरुवार, 26 मार्च, 2026 | मूल्य : 10 रुपए | पृष्ठ : 8 | VIKSIT BHARAT SAMACHAR | Regd. RNI No. ASSHIN/2014/56526

एकात्म मानव दर्शन आज भी प्रासंगिक : उपराष्ट्रपति

पेज 2

कांग्रेस के पास स्वदेशी समुदायों को आश्वस्त करने के लिए कोई स्पष्ट...

पेज 3

औद्योगिक पार्क प्रोत्साहन नीति-2026 राजस्थान बनेगा निवेश का ...

पेज 5

लैक्रास टीमों से लास एंजेलिस ओलंपिक के लिए क्वालिफाई कर इतिहास...

पेज 7

साजिश नहीं, आकस्मिक डूबने से हुई जुबीन की मौत

सिंगापुर कोर्ट का अंतिम फैसला

सिंगापुर। सिंगापुर की कोरोनर अदालत ने फैसला सुनाया है कि असम की सांस्कृतिक हस्ती जुबीन गर्ग की मौत आकस्मिक डूबने के कारण हुई थी, और पुलिस कोस्ट गार्ड (पीसीजी) के इस निष्कर्ष की पुष्टि की है कि इसमें किसी प्रकार की साजिश शामिल नहीं थी। सिंगापुर स्थित समाचार पोर्टल की एक रिपोर्ट के अनुसार, राज्य के कोरोनर एडम नखोदा ने बुधवार को फैसला सुनाते हुए इस घटना को केवल एक दुर्भाग्यपूर्ण और दुर्घटित आकस्मिक डूबने की घटना बताया। ऐसी परिस्थितियों में जहां पुलिस ने यह साबित कर दिया है कि इसमें कोई गड़बड़ी नहीं है, और लोक अभियोजक ने भी इस निष्कर्ष से सहमत जताई है, तो कोरोनर के लिए यह निष्कर्ष निकालना अनुचित होगा कि आपराधिक अपराध किए गए थे, नखोदा ने कहा। अदालत ने इस बात पर जोर दिया कि ऐसा कोई सबूत नहीं है जिससे यह पता चले कि किसी ने गायक को पानी में धकेलने, दबाव डालने या जबरदस्ती करने का काम किया हो। अदालत ने यह भी कहा कि किसी भी व्यक्ति पर आरोप नहीं लगाया गया है, और इस बात का कोई आधार नहीं



मिला कि वहां मौजूद तैराकों ने जानबूझकर गर्ग को पानी के नीचे दबाए रखा था। उनकी पत्नी गरिमा सैकिया गर्ग द्वारा उठाए गए सवाल का जवाब देते हुए, कोरोनर ने कहा कि पीसीजी ने व्यापक और गहन जांच की थी। उन्होंने स्पष्ट किया कि आपराधिक दायित्व का निर्धारण कोरोनर के अधिकार क्षेत्र से बाहर है और यह अभियोजन अधिकारियों के अधिकार क्षेत्र में आता है। रिप्रेजेंटेशन ऑफ़ द पीपल एक्ट, 1951 को धारा 126ए के तहत जारी अधिसूचना के अनुसार, 9 अप्रैल, 2026 को सुबह 7:00 बजे से 29 अप्रैल 2026 को शाम 6:30 बजे तक एग्जिट पोल के आयोजन, प्रकाशन या प्रसारण पर रोक रहेगी। इस अवधि के दौरान प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया या किसी भी अन्य माध्यम

-शेष पृष्ठ दो पर

पश्चिम एशिया संकट पर सर्वदलीय बैठक सरकार को मिला विपक्ष का साथ

नई दिल्ली। पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव के बीच केंद्र सरकार ने सर्वदलीय बैठक कर स्थिति पर गहन चर्चा की। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में करीब 1 घंटे 45 मिनट तक चली। इस बैठक में सरकार ने साफ संदेश दिया कि देश में हालात पूरी तरह नियंत्रण में हैं और किसी भी तरह से घबराने की जरूरत नहीं है। बैठक का मकसद विपक्ष को मौजूदा स्थिति से अवगत कराना और राष्ट्रीय स्तर पर एकजुटता दिखाना था। बैठक में सुरक्षा मामलों की कैबिनेट समिति से जुड़े मंत्री मौजूद रहे, जिनमें अमित शाह, एस जयशंकर और निर्मला सीतारमण शामिल हैं। इसके अलावा जेपी नड्डा और किरन रिजजू



भी बैठक में शामिल हुए। विदेश सचिव विक्रम मिश्री ने वैश्विक हालात और पश्चिम एशिया के संकट पर विस्तार से जानकारी दी। कांग्रेस

के तारिक अनवर और मुकुल वासनिक समाजवादी पार्टी के धर्मेन्द्र यादव और बीजद के समित पात्रा भी बैठक में मौजूद रहे।

संसदीय कार्य मंत्री किरन रिजजू ने कहा कि बैठक में सभी दलों ने हिस्सा लिया और सरकार के साथ खड़े होने का भरोसा दिया। उन्होंने बताया कि विपक्ष के सभी सवालों का जवाब दिया गया और मौजूदा स्थिति पर विस्तार से जानकारी साझा की गई। रिजजू ने सभी दलों का धन्यवाद करते हुए कहा कि देशहित के मुद्दे पर राजनीतिक दलों ने एकजुटता दिखाई है और हालात के अनुसार सरकार जो भी कदम उठाएगी, उसमें पूरा सहयोग मिलेगा। मंत्री ने आगे बताया कि सरकार की ओर से सभी सवालों और जो भी भ्रम थे, उन्हें पूरी तरह स्पष्ट कर दिया गया है। बैठक के

-शेष पृष्ठ दो पर

असम विस चुनाव के दौरान एग्जिट पोल पर प्रतिबंध

गुवाहाटी (हि.स.)। चुनाव आयोग ने असम विधानसभा चुनाव 2026 के मद्देनजर एग्जिट पोल के संचालन और प्रसारण पर प्रतिबंध लगा दिया है। रिप्रेजेंटेशन ऑफ़ द पीपल एक्ट, 1951



को धारा 126ए के तहत जारी अधिसूचना के अनुसार, 9 अप्रैल, 2026 को सुबह 7:00 बजे से 29 अप्रैल 2026 को शाम 6:30 बजे तक एग्जिट पोल के आयोजन, प्रकाशन या प्रसारण पर रोक रहेगी। इस अवधि के दौरान प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया या किसी भी अन्य माध्यम

-शेष पृष्ठ दो पर

आपत्तियों के बावजूद ईसी ने भाजपा नेता अशोक सिंघल और कांग्रेस उम्मीदवार बटाश ओरांग का नामांकन किया मंजूर

शोणितपुर (हि.स.)। चुनाव आयोग ने डेकियाजुली विधानसभा क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) उम्मीदवार और मंत्री अशोक सिंघल का नामांकन स्वीकार कर लिया है। इसके साथ ही, अनिश्चितता और राजनीतिक खींचतान से भरे एक दिन के बाद आज अब स्थिति साफ हो गई है। चुनाव आयोग की आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध जानकारी के अनुसार, सिंघल द्वारा दाखिल किए गए चारों नामांकन पत्रों को वैध घोषित कर दिया गया है। इसका मतलब है



तर्ह की गड़बड़ियां हैं। शिकायत में पहचान से जुड़ी जानकारी का न होना, कुछ पन्नों के साथ कथित तौर पर छेड़छाड़ किया जाना और जमा

कि अब वह इस बेहद अहम चुनावी मुकामले में उतरने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। यह फैसला इसलिए भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह कांग्रेस उम्मीदवार बटाश ओरांग द्वारा उठाई गई औपचारिक आपत्तियों के बाद आया है। ओरांग ने आरोप लगाया था कि सिंघल के नामांकन दस्तावेजों में कई त्रुटियां हैं। शिकायत में पहचान से जुड़ी जानकारी का न होना, कुछ पन्नों के साथ कथित तौर पर छेड़छाड़ किया जाना और जमा

-शेष पृष्ठ दो पर

राज्य में विपक्ष की कोई मौजूदगी नहीं भाजपा को भारी जनादेश मिलेगा : सीएम

नागांव। मुख्यमंत्री हिमंत विश्व शर्मा ने बुधवार को आगामी असम विधानसभा चुनावों में भाजपा को व्यापक जीत का विश्वास जताया और कहा कि पार्टी राज्य भर में कमजोर विपक्ष की मौजूदगी के बावजूद भारी बहुमत हासिल कर सकती है। नागांव में एक चुनावी रैली को संबोधित करते हुए, शर्मा ने दावा किया कि पिछले पांच वर्षों में भाजपा के लिए जनसमर्थन में काफी मजबूती आई है, और कहा कि मतदाता पार्टी को निर्णायक रूप से



मोडिया के माध्यम से विपक्षी गतिविधियों के बारे में पता चलता है, लेकिन चुनाव प्रचार यात्राओं के दौरान उन्हें उनकी उपस्थिति का सामना शायद

-शेष पृष्ठ दो पर

अब पांचवीं के विद्यार्थियों को भी मिलेगी साइकिल : मुख्यमंत्री

होजाई (हि.स.)। होजाई जिलांतर्गत लंका में मुख्यमंत्री डॉ. हिमंत विश्व शर्मा ने बुधवार को असम विधानसभा चुनाव 2026 के मद्देनजर चुनाव प्रचार चलाया। उन्होंने कहा कि राज्य में भाजपा की सरकार बनने पर असम में दो लाख नौकरियों दी जाएंगी, निजतु बाबू, निजतु मोइना योजना का धन बढ़ाए जाने का एलान किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि अब साइकिल आठवीं कक्षा के बच्चा पांचवीं कक्षा में पढ़ने वाले विद्यार्थियों को दी जाएगी। साथ ही कहा कि सभी छात्र-छात्राओं के शिक्षा पर जोर दिया जाएगा। व्यवसाय करने की चाहत रखने वाले 10 लाख युवाओं को दो लाख रुपए दिए जाएंगे। इस दौरान उन्होंने विपक्षी पार्टी कांग्रेस पर जमकर हमला



बोला। लामाईंगा निर्वाचन क्षेत्र के भाजपा उम्मीदवार शिवू मिश्रा के लिए लंका क्रीड़ा संस्था के खेल मैदान में आयोजित विजय संकल्प सभा में भाग लिया। चुनावी सभा में मुख्यमंत्री डॉ. शर्मा ने अपने संबोधन में भाजपा सरकार को असम में बनाने के

लिए सभी लोगों से प्रचार चलाने की अपील की। उन्होंने कहा कि आगामी 5 या 6 अप्रैल को प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी हजाई में चुनावी प्रचार करेंगे। मुख्यमंत्री ने स्वच्छ तरीके से मिली नौकरी, विभिन्न सरकारी योजनाओं के जरिए असम के युवाओं, युवतियों और महिलाओं को स्वावलंबी बनाने की बात का अपनी सरकार की उपलब्धियों के रूप में प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि दस हजार रुपए पाने वाली महिलाओं को 25 हजार रुपए दिए जाने की भी घोषणा की। मुख्यमंत्री ने कहा कि कांग्रेस इन योजनाओं को नहीं चला सकती, कांग्रेस केवल लुंगी और मच्छरदानी दे सकती है। कटाक्ष करते हुए कहा कि कांग्रेस का

-शेष पृष्ठ दो पर

असम विस चुनाव : बदरपुर में कार से करीब आठ लाख नकद बरामद

श्रीभूमि (हि.स.)। असम विधानसभा चुनाव 2026 के मद्देनजर श्रीभूमि जिला के बदरपुर में फ्लाइंग स्कॉड और बदरपुर पुलिस की कार्रवाई में बड़ी मात्रा में नकद जब्त करने की घटना प्रकाश में आई है। पुलिस सूत्रों ने बुधवार को बताया है कि बदरपुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत बदरपुर पेट्रोल पंप के सामने चलाने गए इस अभियान में एक कार (एएस-10बी-0441) से लगभग 7,99,500 रुपए बरामद किए गए। सूत्रों ने बताया कि फ्लाइंग स्कॉड की टीम ने बदरपुर पुलिस के सहयोग से इलाके में नियमित रूप से छापेमारी और तस्कर पर नजर रखना शुरू किया है। निर्वाचन नियमों के अनुसार सख्त वाहनों पर विशेष ध्यान दिया जा



शहरों में 25 दिन और ग्रामीण क्षेत्रों में 45 दिन में ही मिलेगा घरेलू रसोई गैस सिलेंडर

शहरों में 25 दिन और ग्रामीण क्षेत्रों में 45 दिन में ही मिलेगा घरेलू रसोई गैस सिलेंडर

नई दिल्ली (हि.स.)। घरेलू रसोई गैस (एलपीजी) सिलेंडर की बुकिंग समय-समय में बदलाव को लेकर सोशल मीडिया में फैल रही खबरों को केंद्र सरकार ने पूरी तरह खारिज कर दिया है। पेट्रोलियम मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि एलपीजी के बुकिंग नियमों में कोई बदलाव नहीं किया गया है। शहरों में 25 दिन और ग्रामीण क्षेत्रों में 45 दिन में ही एलपीजी सिलेंडर मिलेगा। पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने बुधवार को जारी एक



बयान में कहा कि सरकार के संज्ञान में आया है कि कुछ समाचार रिपोर्ट और सोशल मीडिया पोस्ट में एलपीजी रिफिल बुकिंग की संशोधित समय-सीमा का दावा किया जा रहा है। इनमें प्रधानमंत्री योजना

नई दिल्ली। एनजीओ द्वारा विदेशी अनुदान का दुरुपयोग रोकने के लिए सरकार ने शिकंजा और कस दिया है। इसके लिए सरकार की ओर से लोकसभा में विदेशी अनुदान नियमकानून (एफसीआइए) में संशोधन का विधेयक पेश किया गया है। विधेयक में एफसीआइए लाइसेंस रद्द होने या समाप्त होने की स्थिति में विदेशी अनुदान से बनाई गई संपत्तियों जब्त करने और उनकी देख-रेख के लिए केंद्र और राज्य के स्तर पर नई अर्थांटी बनाने का प्रावधान है। विधेयक को खतरनाक बताकर पेश करने का विरोध का जवाब देते हुए गृह राज्यमंत्री नित्यानंद राय ने कहा कि यह वास्तव में



संशोधन का विधेयक पेश किया गया है। विधेयक में एफसीआइए लाइसेंस रद्द होने या समाप्त होने की स्थिति में विदेशी अनुदान से बनाई गई संपत्तियों जब्त करने और उनकी देख-रेख के लिए केंद्र और राज्य के स्तर पर नई अर्थांटी बनाने का प्रावधान है। विधेयक को खतरनाक बताकर पेश करने का विरोध का जवाब देते हुए गृह राज्यमंत्री नित्यानंद राय ने कहा कि यह वास्तव में

-शेष पृष्ठ दो पर

गुजरात विस में यूसीसी विधेयक पारित, देश का दूसरा राज्य बना

गांधीनगर (हि.स.)। गुजरात विधानसभा में समान नागरिक संहिता (यूसीसी) विधेयक आज बहुमत से पारित हो गया है। इसके साथ ही उत्तराखंड के बाद गुजरात यूसीसी लागू करने वाला देश का दूसरा राज्य बन गया है। बिल पारित होने के बाद सदन में सत्तापक्ष के सदस्यों ने समर्थन जताते हुए जय श्री राम के नारे लगाए और मेज थपथपाकर स्वागत किया। सदन में बिल के विरोध में विपक्षी सदस्यों ने सवाल उठाए। वहीं सत्तापक्ष के सदस्यों ने इस बिल को समानता, न्याय और राष्ट्रीय एकता को मजबूत करने वाला बताया। गुरुवार को

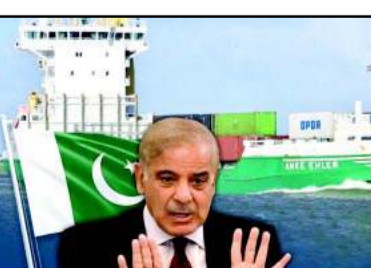


दौरान हलाला प्रथा, शाह बानो केस, अभिनेता धर्मेन्द्र के दूसरे विवाह और श्रद्धा वाकर जैसे मामलों का भी उल्लेख किया गया। मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने विधेयक पेश करते हुए कहा कि यह कानून समानता, न्याय और राष्ट्रीय एकता को मजबूत करेगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि माइनिस्ट्री कम्प्यूनिटी में पुरखों से शादी एक परंपरा है, लेकिन इस बिल का कानून माइनिस्ट्री कम्प्यूनिटी पर लागू नहीं होगा। हम बराबरी, न्याय और एकता के राष्ट्रीय संकल्प को मजबूत करेंगे। हमारे देश की संस्कृति हमें परिवार की भावना सिखाती है। उन्होंने कहा कि सरकार

इरान ने अमेरिका के बिचौलिया को किया बेइज्जत, होर्मुज से पाकिस्तानी जहाज लौटाया

इरान ने अमेरिका के बिचौलिया को किया बेइज्जत, होर्मुज से पाकिस्तानी जहाज लौटाया

तेहरान। अमेरिका के इशारे पर मिडिल ईस्ट में समझौते की स्क्रिप्ट लिख रहे पाकिस्तान को इरान ने बड़ा झटका दिया है। इरान ने खाड़ी से कराची की तरफ आ रहे जहाज सेलन को होर्मुज में रोक दिया है, जिसके कारण जहाज सेलन को वापस खाड़ी में जाना पड़ा है। इरान के आधिकारियों का कहना था कि जहाज को होर्मुज से गुजरने की परमिशन नहीं दी गई थी। इसी कारण उसे वापस भेज दिया गया है। रिपोर्ट के मुताबिक यह जहाज संयुक्त अरब अमीरात से पाकिस्तान के कराची की तरफ जा रहा था। पाकिस्तान



संयुक्त, इस इरान की सरकार ने इस जहाज को होर्मुज से गुजरने की परमिशन नहीं दी थी। इक्विसि को मानें तो यह छोटा फीडर कंटेनर जहाज है, जो 2000 में बनाया गया था। इसमें लगभग 6850 टन तक सामान ले जाया जा सकता है। रिपोर्ट के मुताबिक

सरकार ने इस पर चुप्पी साध ली है। यूएई ने भी कोई टिप्पणी नहीं की है। काबुल स्थित इरान दूतावास के एक बयान के मुताबिक इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड के नेवी ने पाकिस्तान जा रहे शिप को वापस यूएई भेज दिया।

-शेष पृष्ठ दो पर

न्यूज गैलरी
सोनिया गांधी
अस्पताल में भर्ती
हालत स्थिर

नई दिल्ली (हि.स.)। कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी को मंगलवार रात पेट में इन्फेक्शन की शिकायत के बाद दिल्ली के सर गंगा राम अस्पताल में भर्ती कराया गया। डॉक्टरों के मुताबिक, फिलहाल उनकी हालत स्थिर है। बुधवार को अस्पताल द्वारा जारी बुलेटिन के अनुसार, सोनिया गांधी को

कांग्रेस और भारतीय युवा कांग्रेस को कार्यालय खाली करने का नोटिस

नई दिल्ली (हि.स.)। केंद्र सरकार ने कांग्रेस के राष्ट्रीय मुख्यालय 24 अकबर रोड का बंगला और भारतीय युवा कांग्रेस के कार्यालय 5 रायसीना रोड को खाली करने का नोटिस दिया है। नोटिस में पार्टी को 28 मार्च तक खाली करने का समय दिया गया है। सूत्रों के अनुसार, यह नोटिस एग्जिट विभाग की ओर से जारी किया गया है। कांग्रेस ने पिछले वर्ष अपने

-शेष पृष्ठ दो पर

CLASSIFIED
For all kinds of classified advertisements please contact
97070-14771
86382-00107

लखीमपुर में तूफान का कहर, पंडाल गिरने से कई घायल

लखीमपुर (हिंस)। लखीमपुर जिले के विभिन्न क्षेत्रों में आए तेज तूफान ने भारी तबाही मचाई है। पथालिपहाड़ क्षेत्र में बीती रात स्थिति काफी भयावह हो गई। तूफान उस समय आया जब एक भाओना (नाट्य प्रस्तुति) समारोह चल रहा था। तेज हवाओं के कारण पंडाल अचानक गिर गया, जिससे कई लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों को तुरंत नजदीकी अस्पतालों में भर्ती कराया गया है। इसी बीच बंगालमारा क्षेत्र से भी नुकसान की खबरें सामने आई हैं, जहां तूफान को चपेट में आकर कई घरों को क्षति पहुंची है। प्रशासन द्वारा नुकसान का आकलन किया जा रहा है।

पाकिस्तान के बयान को भारत ने किया खारिज, आतंकवाद पर घेरा

नई दिल्ली (हि.स.)। भारत ने प्रतिबंधित आतंकवादी संगठन से जुड़े न्यायिक मामलों पर पाकिस्तान के बयान को सख्ती से खारिज किया है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने बुधवार को मीडिया के सवालों पर कहा कि भारत पाकिस्तान द्वारा जारी इस बयान को पूरी तरह अस्वीकार करता है, जिसमें एक प्रतिबंधित आतंकवादी संगठन और उसके सदस्यों का समर्थन किया गया है। उन्होंने कहा कि भारत के आंतरिक मामलों या न्यायिक प्रक्रियाओं पर टिप्पणी करने का पाकिस्तान को कोई अधिकार नहीं है। यह आश्चर्य की बात नहीं है कि एक ऐसा देश, जो लंबे समय से आतंकवाद को बढ़ावा देता रहा है, इस तरह का बयान दे रहा है, जो हिंसा और निर्दोष लोगों की हत्या को उचित द्हरता है। प्रवक्ता ने पाकिस्तान को नसीहत देते हुए कहा कि झूठ और भ्रामक बयानजायी करने के बजाय उसे अपने यहां हो रहे गंभीर और व्यवस्थित मानवाधिकार उल्लंघनों पर आत्ममंथन करना चाहिए।

एकात्म मानव दर्शन आज भी प्रासंगिक : उपराष्ट्रपति

नई दिल्ली (हि.स.)। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने कहा कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय का *एकात्म मानव दर्शन* आज भी अत्यंत प्रासंगिक है और वर्तमान वैश्विक चुनौतियों के बीच संतुलित और समन्वित जीवन का मार्ग दिखाता है। उपराष्ट्रपति ने बुधवार को कर्नाटक राज्य मुक्त विश्वविद्यालय, मैसूरू में *एकात्म मानव दर्शन – भारत का विश्वदृष्टिकोण* विषय पर आयोजित अंतर्राष्ट्रीय शैक्षणिक सम्मेलन का वरचुंअल उद्घाटन किया। यह सम्मेलन 25 से 27 मार्च तक आयोजित किया जा रहा है। उन्होंने इस सम्मेलन के आयोजन के लिए कर्नाटक स्टेट ओपन यूनिवर्सिटी, प्रज्ञा प्रवाह और डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी रिसर्च

फाउंडेशन की सराहना की। उपराष्ट्रपति ने कहा कि एकात्म मानव दर्शन व्यक्ति, समाज, प्रकृति और ब्रह्मंड के बीच गहरे संबंध पर आधारित है। आज के समय में जब दुनिया विभाजन, तनाव और अविश्वास जैसी समस्याओं से जूझ रही है, यह दर्शन धर्म, कर्तव्य और मूल्यों के माध्यम से समरसता का मार्ग प्रस्तुत करता है। वास्तविक विकास वही है जो शरीर, मन, बुद्धि और आत्मा के समग्र विकास के साथ-साथ प्रकृति के साथ संतुलन बनाए रखे। उन्होंने सार्वजनिक जीवन में कर्तव्य और सेवा के महत्व को रेखांकित करते हुए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के *सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास* के मंत्र

का उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि वर्ष 2047 तक विकसित भारत का लक्ष्य समावेशी और सतत विकास पर आधारित है, जो *वसुधैव कुटुंबकम* की भावना से जुड़ा है। तेजी से बढ़ती तकनीकी प्रगति के संदर्भ में उन्होंने कहा कि तकनीक का उपयोग मानव कल्याण के लिए होना चाहिए और इसे नैतिक मूल्यों द्वारा संचालित किया जाना आवश्यक है। उपराष्ट्रपति ने एकात्म मानव दर्शन के सिद्धांतों को नीति और व्यवहार में अपनाने का आह्वान किया, ताकि एक संतुलित और सामंजस्यपूर्ण विश्व का निर्माण किया जा सके। उन्होंने सम्मेलन को सफलता के लिए शुभकामनाएं भी दीं।

कोकराझाड़ में वीसीडीसी स्तर पर एसवीईईपी अभियान तेज

कोकराझाड़ (हिंस)। जिले में जमीनी स्तर पर मतदाता जागरूकता को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से विभिन्न विकास खंडों में एसवीईईपी (सिस्टेमेटिक वोटर्स एजुकेशन एंड इलेक्टोरल पार्टिसिपेशन) कार्यक्रमों की श्रृंखला आयोजित की जा रही है। इसी कड़ी में बुधवार को कचुगांव विकास खंड, डोटमा विकास खंड के बिनाचारा वीसीडीसी, बोरामगारी वीसीडीसी कार्यालय तथा शक्तियाश्रम वीसीडीसी सहित विभिन्न स्थानों पर जागरूकता गतिविधियों का आयोजन किया गया। जिसमें स्थानीय मतदाताओं और समुदाय के लोगों ने सक्रिय भागीदारी निभाई। प्रत्येक वीसीडीसी के अंतर्गत आयोजित बैठकों

में मतदाताओं को अपने मताधिकार का प्रयोग करने के महत्व पर विशेष जोर दिया गया। साथ ही मतदान के दिन समय पर मतदान करने के लिए प्रेरित किया गया। नागरिकों को लोकतंत्र को सशक्त बनाने में उनकी भूमिका के प्रति जागरूक किया गया। कार्यक्रम के दौरान जिले के एसवीईईपी शुभंकर *सिखिरी* और *ड्रिगलु* से युक्त पंपलेट वितरित किए गए, ताकि संदेश को सरल, रोचक और प्रभावी तरीके से आमजन तक पहुंचाया जा सके। इन प्रयासों के माध्यम से जिले में मतदाता सहभागिता बढ़ाने और लोकतांत्रिक मूल्यों को मजबूत करने की दिशा में सकारात्मक माहौल तैयार किया जा रहा है।

पाकिस्तान के बयान को भारत ने किया खारिज, आतंकवाद पर घेरा

नई दिल्ली (हि.स.)। भारत ने प्रतिबंधित आतंकवादी संगठन से जुड़े न्यायिक मामलों पर पाकिस्तान के बयान को सख्ती से खारिज किया है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने बुधवार को मीडिया के सवालों पर कहा कि भारत पाकिस्तान द्वारा जारी इस बयान को पूरी तरह अस्वीकार करता है, जिसमें एक प्रतिबंधित आतंकवादी संगठन और उसके सदस्यों का समर्थन किया गया है। उन्होंने कहा कि भारत के आंतरिक मामलों या न्यायिक प्रक्रियाओं पर टिप्पणी करने का कोई अधिकार नहीं है। यह आश्चर्य की बात नहीं है कि एक ऐसा देश, जो लंबे समय से आतंकवाद को बढ़ावा देता रहा है, इस तरह का बयान दे रहा है, जो हिंसा और निर्दोष लोगों की हत्या को उचित द्हरता है। प्रवक्ता ने पाकिस्तान को नसीहत देते हुए कहा कि झूठ और भ्रामक बयानजायी करने के बजाय उसे अपने यहां हो रहे गंभीर और व्यवस्थित मानवाधिकार उल्लंघनों पर आत्ममंथन करना चाहिए।

साजिश नहीं, आकस्मिक...

से पहले शराब का सेवन किया था और उस समय वह नशे में थे, जिससे संभवतः उनके निर्णय लेने की क्षमता प्रभावित हुई। नखोदाने ने कहा कि गर्म नशे में थे, और संभवतः इसी वजह से उनके निर्णय लेने की क्षमता प्रभावित हुई, जिसमें लाइफ जैकेट न पहनने का उनका फैसला भी शामिल है। अदालत ने गर्म के चिकित्सीय इतिहास पर ध्यान दिया, जिसमें उच्च रक्तचाप और मिर्गी शामिल हैं, और मिर्गी का उनका आखिरी दौरा 2024 में दर्ज किया गया था। हालांकि अदालत ने डूबने से पहले दौरे की संभावना से इनकार नहीं किया, लेकिन उसने कहा कि इसे निर्णायक रूप से साबित करने के लिए पर्याप्त सबूत नहीं हैं। इसके अतिरिक्त, जांचकर्ता ने गर्म को सिंगापूर यात्रा के लिए दिए गए निमंत्रण में *कुछ भी अनुचित या दुष्प्रचारपूर्ण* नहीं पाया, और यह भी पाया कि असम एसोसिएशन सिंगापु्र के सदस्यों ने उनकी यात्रा को सुविधाजनक बनाने के लिए वास्तविक प्रयास किए थे। यह फैसला गर्म के परिवार द्वारा उनकी मृत्यु से संबंधित परिस्थितियों के बारे में पहले उठाई गई मुक़ाबले का मंच आया है, जिसमें यह सवाल भी शामिल है कि क्या वह स्वेच्छा से पानी में उतरे थे। इस बीच, असम में अलग से कानूनी कार्यवाही चल रही है, जहां गुवाहाटी उच्च न्यायालय ने मामले को सुनवाई के लिए एक त्वरित अदालत का गठन किया है। न्यायाधीश शर्मिला भुइयां को उन व्यक्तियों से संबंधित कार्यवाही की अध्यक्षता करने के लिए नामित किया गया है जो घटना के समय नौका पर मौजूद थे।

सरकार को मिला ...

अंत में विपक्षी दलों ने कहा कि वे सरकार द्वारा इस सर्वदलीय बैठक बुलाने के लिए आभार व्यक्त करते हैं। उन्होंने यह भी कहा कि ऐसे कठिन और चुनौतीपूर्ण समय में सभी को एकजुट होकर खड़ा होना होगा। प्रधानमंत्री मोदी ने भी संसद के माध्यम से अपील की है कि किसी भी चुनौतीपूर्ण स्थिति में भारतीय संसद को एक साथ खड़ा होना चाहिए। मुझे लगता है कि विपक्ष ने परिपक्वता दिखाते हुए कहा कि वे सरकार द्वारा उठाए गए हर कदम के साथ खड़े रहेंगे। कई सदस्यों ने होमिुज जलडमरूमध्य से गैस और पेट्रोलियम सप्लाई के बारे में जानकारी मांगी थी और वे इस बात से संतुष्ट हैं कि भारत ने पहले ही चार जहाज सुरक्षित कर लिए हैं। रिजिजू ने आगे कहा कि सभी ने अपनी-अपनी पार्टियों को ईंग से जानकारी साझा की और चिंताएं व्यक्त कीं। विपक्ष के सदस्यों ने ईरान, इस्त्राएल और अमेरिका के बीच चल रहे संघर्ष का भारत पर ब्या असर पड़ेगा और सरकार ने भारतीय नागरिकों के लिए क्या कदम उठाए हैं, इस पर कई सवाल पूछे। सरकार ने इन सभी सवालों के व्यापक और स्पष्ट जवाब दिए। मैं यह कहकर संतुष्ट हूं कि सरकार ने विपक्ष के हर सवाल का जवाब दिया है। अंत में सभी विपक्षी साथियों ने कहा कि इस संकट की घड़ी में सरकार जो भी फैसला लेगी, उसमें वे एकजुट होकर समर्थन देंगे। विपक्ष की जो मांग थी कि उन्हें पूरी जानकारी दी जाए, वह सरकार ने आज दे दी है। सरकार ने स्पष्ट किया कि देश में ऊर्जा संसाधनों की कोई कमी नहीं है। तेल की सप्लाई पूरी तरह सामान्य है और पर्याप्त स्टॉक मौजूद है। सरकार ने बताया कि चार और जहाज भारत की ओर आ रहे हैं और कुछ अन्य जहाज जल्द ही होमिुज क्षेत्र से निकलेंगे। इससे साफ है कि सप्लाई चेन को लेकर कोई बड़ा खतरा नहीं है। बैठक में सरकार ने विपक्ष को मौजूदा हालात की पूरी जानकारी दी और उनके सवालों का जवाब भी दिया। विपक्ष ने सुरक्षा, तेल आपूर्ति और विदेश नीति को लेकर सवाल उठाए, जिन पर सरकार ने भरोसा दिलाया कि सभी पहलुओं पर नजर रखी जा रही है। सरकार ने कहा कि हर कदम सोच-समझकर उठाया जा रहा है। सरकार ने साफ कहा कि वैश्विक हालात पर लगातार नजर रखी जा रही है और जरूरत पड़ने पर तुरंत कदम उठाए जाएंगे। साथ ही आम लोगों से अपील की गई कि वे किसी तरह की अफवाह पर ध्यान न दें और घबराएं नहीं। सरकार का कहना है कि देश पूरी तरह तैयार है और किसी भी स्थिति से निपटने की क्षमता रखता है।

असम विस चुनाव के ...

से एग्जिट पोल का प्रचार-प्रसार नहीं किया जा सकेगा। आयोग ने यह भी स्पष्ट किया है कि अधिनियम की धारा 126(1)(बी) के तहत मतदान समाप्त होने से 48 घंटे पहले तक इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में किसी भी प्रकार की

गुवाहाटी (हिंस)। शिवसागर के भाजपा उम्मीदवार कुशल दुवरी का नामांकन पत्र आखिरकार वैध घोषित कर दिया गया है, जिससे उनकी उम्मीदवारी को लेकर जारी अनिश्चितता समाप्त हो गई है। रड़जर दल के अध्यक्ष अखिल गोगोई ने दुवरी के नामांकन को चुनौती देते हुए चुनाव आयोग में शिकायत दर्ज कराई थी। इस शिकायत के बाद यह अटकलें तेज हो गई थीं कि उनका नामांकन स्वीकार किया जाएगा या नहीं। काफी समय तक चुनाव आयोग की वेबसाइट पर केवल आवेदन की स्थिति ही दिखाई दे रही थी, जिससे भी की स्थिति बनी हुई थी। हालांकि, बीती देर रात आयोग की वेबसाइट पर भाजपाकी अपडेट करते हुए दुवरी का नामांकन वैध और स्वीकृत बताया गया है। वहीं, डेकियानुजुली सीट से भाजपा और कांग्रेस उम्मीदवारों के नामांकन को लेकर अब तक कोई अंतिम निर्णय नहीं लिया गया है, जिससे उस क्षेत्र में स्थिति अभी भी स्पष्ट नहीं हो पाई है।

गुवाहाटी (हिंस)। यात्रियों को ट्रेन में सुविधा और आरामदायक यात्रा को उन्नत करने की दिशा में पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे (पूसीरे) ने एक उल्लेखनीय कदम उठाया है। लंबी दूरी की अपनी दो प्रीमियम ट्रेनों, अग्रतला-आनंद विहार टर्मिनल तेजस एक्सप्रेस और डिब्रूगढ़-नई दिल्ली राजधानी एक्सप्रेस में बेहतर लिनेन सेवाएं शुरू की हैं। रेलवे को इस पहल से यात्रियों को अधिक स्वच्छ, आरामदायक और बेहतर यात्रा अनुभव प्रदान करने में उसकी प्रतिबद्धता को दोहराती है। पूसीरे के सीपीआरओ कर्पिंजल किशोर शर्मा ने बुधवार को बताया है कि अग्रतला- आनंद विहार टर्मिनल तेजस एक्सप्रेस में 23 मार्च से अपग्रेडेड बेडरोल की सुविधा शुरू की गई है, जिसमें खास तौर पर

डिजाइन किए गए, बेहतरीन क्वालिटी के लिनेन शामिल हैं। इस अहम अपग्रेड का उद्देश्य बेहतर सफाई और स्वच्छता सुनिश्चित करना है। साथ ही, यह प्रीमियम सेवाओं का लाभ उठाने वाले यात्रियों के लिए ज्यादा आरामदायक और ताजगी भरी यात्रा भी प्रदान करता है। डिब्रूगढ़- नई दिल्ली राजधानी एक्सप्रेस के एसी कोचों में भी 24 मार्च से बेहतर बेडरोल की सुविधा शुरू की गई है, जिसमें फर्स्ट एसी और सेकेंड एसी, दोनों क्लास शामिल हैं। यात्रियों को मानकीकृत, उच्च गुणवत्ता वाले बेडरोल उपलब्ध कराए जा रहे हैं, जिसे विशेष रूप से बेहतर आराम और गुणवत्ता के लिए डिजाइन किया गया है। पूसीरे ने इस बात पर जोर दिया कि एसी पहलें यात्रियों के आराम और सेवा मानकों

पृष्ठ एक का शेष

चुनावी सामग्री, जिसमें ओपिनियन पोल या अन्य सर्वेक्षण के परिणाम शामिल हैं, का प्रदर्शन प्रतिबंधित रहेगा। असम के मुख्य निर्वाचन अधिकारी अनुराग गोयल ने सभी मीडिया संस्थानों, एजेंसियों और संबंधित पक्षों से इन प्रावधानों का सख्ती से पालन करने की अपील की है, ताकि राज्य में स्वतंत्र, निष्पक्ष और आदर्शी चुनाव सुनिश्चित किया जा सके।

आपत्तियों के बावजूद ईसी ...

किए गए फॉर्म में अधूरी जानकारी होना, जैसे मुद्दों का चि्त्र किया गया था। इन मुद्दों की वजह से भाजपा नेता की उम्मीदवारी पर कुछ समय के लिए संदेह के बादल मंडराने लगे थे। इन आपत्तियों के बावजूद, चुनाव आयोग के साथ विचार-विमर्श और बैठक के बाद सिंघल का नामांकन अंततः मंजूर कर लिया गया। यह इस बात का संकेत है कि चुनाव आयोग उनके दस्तावेजों और नियमों के पालन से पूरी तरह संतुष्ट है। इसी क्रम में, चुनाव आयोग ने कांग्रेस उम्मीदवार बदाश ओरांग के नामांकन को भी वैध पाया है। इसके साथ ही, डेकियानुजुली में इन दोनों प्रमुख उम्मीदवारों के बीच सीधे चुनावी मुक़ाबले का मंच तैयार हो गया है। अब चुनाव आयोग की वेबसाइट पर इन दोनों उम्मीदवारों के नामांकन की वैधता की स्थिति साफ तौर पर देखी जा सकती है। ज्ञात हो कि नामांकन पत्रों की जांच का अंतिम दिन 24 मार्च निर्धारित था। देर शाम तक चुनाव आयोग की ओर से जारी सूचना के अनुसार राध्ण की 126 सीटों में 124 विधानसभा के उम्मीदवारों के नामांकन को वैध घोषित किया गया था। वहीं, डेकियानुजुली विधानसभा में भाजपा और कांग्रेस के उम्मीदवारों के नामांकन की जांच पूरी नहीं होने के चलते 25 मार्च को पुनः जांच करने संबंधी सूचना जारी की गयी थी। इसी लंका में आज फिर से नामांकन पत्रों की जांच के बाद आधिकारिक रूप से दोनों पार्टियों के उम्मीदवारों के नामांकन को वैध घोषित किया गया।

राज्य में विपक्ष की कोई ...

ही कभी करना पड़ता है। मुझे विपक्ष के अस्तित्व के बारे में तभी पता चलता है जब मैं पत्रकारों से बात करता हूं। अन्यथा, अपनी यात्राओं के दौरान, मुझे उनकी ओर से शायद ही कोई गतिविधि दिखाई देती है, शर्मा ने टिप्पणी की। मुख्यमंत्री ने आगे कहा कि पिछले कुछ वर्षों में मतदाता अधिक मुखर और राजनीतिक रूप से जागरूक हो गए हैं, और आगामी चुनावों में वे *पूरी निष्ठा* से मतदान करेंगे। उन्होंने कहा कि पिछले पांच वर्षों में असम के लोग अधिक सशक्त और जागरूक हुए हैं। इस बार वे पूरे विश्वास के साथ अपना वोट डालेंगे। अवैध घुसपैठ के मुद्दे पर बात करते हुए, शर्मा ने दावा किया कि ऐसे तत्वों से जुड़ी *गुंडागर्दी* की घटनाएं कम हो गई हैं, और भविष्य में कड़ी कार्रवाई करने के लिए अपनी सरकार की प्रतिबद्धता को दोहराया। उन्होंने कहा कि आगामी पांच वर्षों में, हम अवैध घुसपैठ और संबंधित मुद्दों से निपटने के लिए और भी कड़े कदम उठाएंगे। स्थिति में पहले से सुधार हुआ है, और हम कानून और व्यवस्था बनाए रखने के लिए दृढ़ता से कार्रवाई करना जारी रखेंगे। उन्होंने असम की सांस्कृतिक और ऐतिहासिक विरासत में निहित पहचान के पुनर्निर्माण के अपने दृष्टिकोण के बारे में भी बात की, जिसमें उन्होंने श्रीमंत शंकरदेव और अहोम सेनापति सुकाफा जैसी हस्तियों का चि्त्र किया। हम अपनी सांस्कृतिक विरासत और मूल्यों पर आधारित एक महान असम का निर्माण करना चाहते हैं, शर्मा ने आगे कहा।

अब पांचवीं के विद्यार्थियों को ...

प्रतीक चिह्न लुंगी ही होना चाहिए। इस बीच अरुणोदय योजना के तहत 18 हजार रुपए महिलाओं को दिए जाने की घोषणा की। वहीं राज्य में 15 लाख सरकारी घर दिए जाने का भी एलान किया। सभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि असम की शांति के लिए राज्य में फिर से भाजपा की सरकार लानी पड़ेगी। उन्होंने लंका महाविद्यालय में विज्ञान शाखा का शुभारंभ किया, लंका में ऑडिटोरियम बनवाने, काकी और लंका में दो स्टेडियम बनवाने, लंका-काकी में जिन लोगों को भूमि का पट्टा नहीं मिला है उन्हें भी भूमि का पट्टा दिये जाने की भी घोषणा किया। मुख्यमंत्री ने एक अन्य चुनावी सभा में हिस्सा लेते हुए होजाई विधानसभा क्षेत्र के भाजपा उम्मीदवार के समर्थन में भारी संख्या में उपस्थित लोगों को संबोधित किया। होजाई में आयोजित विजय संकल्प सभा में आम जनता के अभूतपूर्व उत्साह और समर्थन के देखकर मुख्यमंत्री ने कहा कि मैं अभिभूत हूं। उन्होंने कहा कि

को बेहतर बनाने के प्रति उसकी प्रतिबद्धता को दर्शाती हैं। अपग्रेडेड बेडरोल में बेहतर एकरूपता, टिकाऊपन और स्वच्छता मिलती है, जिससे विशेष रूप से लंबी दूरी की रात्रिकालीन यात्रा करने वाले यात्रियों को फायदा होता है। यात्रियों ने इस पहल पर अपनी अपार प्रसन्नता व्यक्त की है और पूसीरे द्वारा किए गए ऐसे विचारशील और यात्री-केंद्रित सुधारों की हार्दिक सराहना की है।अपग्रेडेड बेडरोल सेवा की शुरुआत, भारतीय रेलवे के सुरक्षित, स्वच्छ और यात्री-अनुकूल यात्रा वातावरण सुनिश्चित करने के विजन के अनुरूप है। पूसीरे निरंतर प्रगतिशील पहलों को शुरू कर रहा है, जिससे सेवा उत्कृष्टता और ग्राहक संतुष्टि पर इसका जोर एक पुनः साबित हुआ है।

असम विस चुनाव : बदरपुर...

रहा है। इसी कड़ी में बदरपुर की ओर जा रही एक कार को रोका और तलाशी ली गई। तलाशी के दौरान कार के अंदर से लगभग 7,99,500 नकद बरामद किया है। घटना स्थल पर उपस्थित फ्लॉइंग स्क्वाड के जिम्मेदार अधिकारी ने बताया कि जब ग्यालू में मौजूद लोगों से पूछताछ की गई, तो उन्होंने दावा किया कि यह धन कछार जिले के चौरंगी ब्राह्मणी मेला से श्रीभूमि ले जाया जा रहा था। लेकिन वे इतनी बड़े मात्रा में नकद धन ले जाने के लिए किसी वैध दस्तावेज या प्रमाण को नहीं दिखा सके, इसलिए चुनाव आयोग के निर्देशों के अनुसार पूरे धन को जब्त कर लिया गया। ज्ञात हो कि जिम्मेदार अधिकारी ने उल्लेख किया कि फ्लॉइंग स्क्वाड और श्रीभूमि पुलिस प्रशासन की संयुक्त पहल में स्वच्छ और शांतिपूर्ण तरीके से चुनाव कराने के लिए आने वाले दिनों में भी ऐसे अभियान जारी रहेंगे।

शहरों में 25 दिन और...

कहा कि एलपीजी रीफिल बुकिंग को मौजूदा समयसीमा पहले की तरह ही लागू रहेगी। बयान में स्पष्ट किया गया है कि ऐसा कोई बदलाव नहीं किया गया है। रिफिल बुकिंग की मौजूदा समय-सीमा में कोई बदलाव नहीं हुआ है। सरकार ने नागरिकों से अपील की है कि वे ऐसी भ्रामक सूचनाओं और अफवाहों बचें तथा विश्वास न करें और न ही उन्हें आगे फैलाएं। साथ ही अनावश्यक या घबराहट में एलपीजी बुकिंग करने से बचने की सलाह दी गई है। मंत्रालय ने यह भी भरोसा दिलाया कि देश में एलपीजी का पर्याप्त भंडार उपलब्ध है और किसी तरह की कमी की कोई आशंका नहीं है, इसलिए उपभोक्ताओं को चिंता करने की जरूरत नहीं है।

एनजीओ अब विदेशों ...

उन लोगों के लिए खतरनाक है जो विदेशी योगदान का इस्तेमाल जबरन धर्मांतरण के लिए या व्यक्तिगत लाभ करते हैं। दरअसल देश में कुल 16 हजार एनजीओ को एफसीआरए लाइसेंस मिला हुआ है और उन्हें हर साल लगभग 22 हजार करोड़ रुपए की विदेशी सहायता मिलती है। नित्यानंद राय ने कहा कि 2010 के एफसीआरए कानून के कई प्रविधानों में अस्पष्टता होने के कारण उनका उल्लंघन करने वाले एनजीओ के खिलाफ कार्रवाई नहीं हो पाती थी। प्रस्तावित संसोधन में इन नियमों को स्पष्ट कर दिया गया है। इसमें और निगदण के लिए एक व्यापक कानूनी ढांचा प्रस्तावित है। इसके तहत पूर्व अनुमति के तहत विदेशी अनुदान प्राप्ति और उपयोग के लिए समय-सीमा तय की जाएगी। यदि एफसीआरए के तहत दिया गया प्रमाणपत्र अपनी वैधता अवधि समाप्त होने पर नवीनीकरण के लिए समय पर आवेदन नहीं किया जाता, या आवेदन अस्वीकार हो जाता है, या समय से पहले नवीनीकृत नहीं किया जाता, तो प्रमाणपत्र स्वतः समाप्त माना जाएगा। जिस व्यक्ति का प्रमाणपत्र समाप्त हो गया है, वह प्रमाणपत्र के नवीनीकृत होने तक विदेशी योगदान न तो प्राप्त कर सकेगा और न ही उसका उपयोग कर सकेगा। विधेयक को पेश करते हुए नित्यानंद राय ने कहा कि मोदी सरकार विदेशी फंडिंग के किसी भी दुरुपयोग को बर्दाश्त नहीं करेगी और ऐसे तत्वों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करेगी। वहीं, प्रस्तावित विधेयक में सजा को भी कम किया गया है। एफसीआरए के प्रविधानों का उल्लंघन कर विदेशी योगदान प्राप्त करने वाले व्यक्ति के लिए पहले पांच वर्ष की सजा का प्रविधान था, जिसे घटाकर एक वर्ष कर दिया गया है।

गुजरात विस में यूसीसी ...

इस बात के लिए सतर्क है कि जातिगत भेदभाव न हो। शायदी का जरूरी रजिस्ट्रेशन, तलाक के एक जैसे नियम, पेनल्टी समेत कुछ जरूरी प्राविवन होंगे। शायदी का रजिस्ट्रेशन न कराने वालों को सजा देने का प्राविवन है। उन्होंने कहा कि राज्य के सभी नागरिकों के लिए एक जैसा कानून होगा। जो लोग अपनी शायदी रजिस्टर नहीं करवाएंगे, उन पर दस हजार रुपए का जुर्माना लगेगा और एक से ज्यादा बार शायदी करने वालों को चार साल की जेल

बरपेटा में कांग्रेस

प्रत्याशी महानंद सरकार

का नामांकन रह

गुवाहाटी (हिंस)। बरपेटा से कांग्रेस प्रत्याशी महानंद सरकार का नामांकन चुनाव अधिकारियों द्वारा जांच के बाद रद्द कर दिया गया है। अधिकारियों के अनुसार, उम्मीदवार द्वारा प्रस्तुत फॉर्म–ए में विसंगतियां पाई गईं। विशेष रूप से, मूल दस्तावेज के स्थान पर स्कैन किए गए हस्ताक्षर वाली जेबैक्स प्रति जमा करने का मामला सामने आया। यह मामला तब उजागर हुआ जब असम गण परिषद (अगप) की बरपेटा जिला समिति ने दस्तावेज की वैधता को लेकर आपत्ति दर्ज कराई। शिकायत पर सुनवाई के बाद जिला निर्वाचन अधिकारी ने महानंद सरकार का नामांकन रद्द करने की घोषणा की।

असम विस चुनाव : सभी सीटों पर नामांकन पत्रों की जांच पूरी

गुवाहाटी (हिंस)। असम विधानसभा के सामान्य चुनाव 2026 के लिए सभी 126 विधानसभा क्षेत्रों में नामांकन पत्रों की जांच प्रक्रिया सफलतापूर्वक पूरी कर ली गई है। नामांकन पत्रों की जांच प्रक्रिया मुख्य रूप से 24 मार्च को संपन्न हुई थी। हालांकि, 24 नंबर बरपेटा (एससी) और 65 नंबर डेकियानुजुली विधानसभा क्षेत्रों के लिए जांच को स्थगित कर 25 मार्च को सुबह 11 बजे तक के लिए बढ़ाया गया था। अब इन दोनों निर्वाचन क्षेत्रों में भी जांच प्रक्रिया पूरी कर ली गई है। 65 नंबर डेकियानुजुली विधानसभा क्षेत्र में सभी 10 नामांकन पत्र वैध पाए गए। वहीं, 24 नंबर बरपेटा (एससी) में जांचे गए नामांकन पत्रों में से एक नामांकन को अवैध घोषित किया गया, जबकि तीन नामांकन पत्र वैध पाए गए। कुल मिलाकर 126 विधानसभा क्षेत्रों में 815 उम्मीदवारों ने 1,389 नामांकन पत्र दाखिल किए थे। जांच प्रक्रिया पूरी होने के बाद 789 उम्मीदवारों को चुनाव लड़ने के लिए वैध घोषित किया गया है। निर्वाचन आयोग ने उम्मीदवारों के नाम वापस लेने की अंतिम तिथि 26 मार्च को अपराहन 3 बजे तक निर्धारित की है।

ढकुआखाना में लोगों ने चोर को पकड़कर किया पुलिस के हवाले

धेमाजी (हिंस)। असम के ढकुआखाना क्षेत्र में एक चोर को स्थानीय लोगों ने पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। घटना मदारगुरी गांव की है, जहां रात करीब 12–30 बजे एक दुकान में चोरी की वारदात हुई। जानकारी के अनुसार, छोटे व्यापारी अरुण ज्योति बरुवा की दुकान में घुसकर चोरों ने सामान और लगभग 10 हजार रुपए नकद लेकर भागने की कोशिश की। इस दौरान दुकान मालिक ने एक आरोपी का पीछा किया, लेकिन उस पर धारदार हथियार से हमला किया गया। घायल होने के बावजूद स्थानीय लोगों की मदद से एक आरोपी संतोष ताय को पकड़ लिया गया। बाद में ग्रामीणों ने आरोपी को बांधकर पुलिस को सूचना दी। पुलिस मौके पर पहुंचकर उसे हिरासत में ले गई। पूछताछ के दौरान आरोपी ने अपना जुर्म कबूल करते हुए दो अन्य साथियों के नाम भी बताए। हालांकि, स्थानीय लोगों ने आरोप लगाया है कि घटना के कई घंटे बाद ही पुलिस ने अन्य आरोपियों को पकड़ने के लिए कोई ठोस कार्रवाई नहीं की है। क्षेत्र में बढ़ती चोरी की घटनाओं को लेकर लोगों में नाराजगी है और उन्होंने जिला पुलिस अधीक्षक से हस्तक्षेप की मांग की है।

बिनाकांदाी में बदरुहीन अजमल की सभा में तनावपूर्ण स्थिति

हेलाकांदाी (हिंस)। बदरुहीन अजमल की सभा के दौरान बुधवार को उस समय तनावपूर्ण स्थिति उत्पन्न हो गई जब स्थानीय लोगों ने लंबे समय से लांबित एक नागरिक समस्या को लेकर नाराजगी जताई। जानकारी के अनुसार, क्षेत्र में एक स्ट्रीट लाइट लंबे समय से खराब पड़ी है, जिससे स्थानीय लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इस समस्या के समाधान में देरी को लेकर लोगों में असंतोष व्याप्त था। सभा के दौरान स्थानीय निवासियों ने इस मुद्दे पर अजमल से सीधे जवाब-तलब किया, जिससे कुछ समय के लिए माहौल गरम हो गया। हालांकि बाद में स्थिति को नियंत्रित कर लिया गया।

होगी। कोर्ट के बाहर तलाक अमान्य होगा और यह सजा के दायरे में आएगा। लिब-इन रिलेशनशिप के लिए 3 महीने के अंदर रजिस्ट्रेशन जरूरी है। सदन में चर्चा के दौरान डिटी चीफ मिनिस्टर सचें संघवी ने एक गंभीर मुद्दा उठाया। संघवी ने कहा कि कुछ मामलों में लड़के गलत नाम रखकर लड़कियों को फंसाते हैं। नकली शादियां होती हैं और फिर जब उनकी असली पहचान सामने आती है, तो लड़कियां ऐसे अपराधों का शिकार हो जाती हैं। इसे रोकने के लिए सख्त पुलिस कार्रवाई ही एकमात्र उपाय है। कोर्ट के फैसले का चि्त्र करके *हलाला* प्रथा पर चर्चा करते हुए संघवी ने बताया कि तलाक के बाद अपने पति से दोबारा शादी करने के लिए एक महिला को दूसरे व्यक्ति से शादी करने की प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है। हालांकि, कांग्रेस सदस्य इमरान खेड़वाला ने इस मुद्दे का विरोध किया और कहा कि हलाला को लेकर गलत मैसेज फैलाए जा रहे हैं। यह दावा कि इस प्रथा में शारीरिक संबंध जरूरी है, सही नहीं है। सदन में एक और चर्चा के दौरान कांग्रेस विधायक शैलेश परमार ने सरकार और सभाधारी पार्टी की कड़ी आलोचना की। उन्होंने कहा कि जब बजट की मांग जैसे जनहित के मुद्दों पर चर्चा हो रही थी, तो सदस्य सदन में मौजूद नहीं रहे। आज यूसीसी का मुद्दा सदन में दोगुनी ताकत से देखा जा रहा है। इस स्थिति से ऐसा लगता है कि चुनाव पास आने के साथ राजनीतिक दिलचस्पी बढ़ गई है। परमार ने कहा कि सरकार को कानून बनाने का अधिकार है, लेकिन उसे कानून लागू करने और उसके असर का अधिकार भी है। उन्होंने सवाल उठाया कि क्या गुजरात सरकार का यूसीसी कानून राज्य के नागरिकों तक ही सीमित रहेगा या नहीं? क्या इसका असर दूसरे लोगों पर भी पड़ेगा? इस बयान के साथ उन्होंने सरकार की पॉलिसी और उसके असर पर गंभीर सवाल उठाए। इससे पहले, सदन की कार्यवाही प्रश्नकाल से शुरू हुई। प्रश्नकाल के बाद कांग्रेस के अतिम चावड़ा ने राज्य में पेट्रोल, डीजल और गैस की कमी का मुद्दा उठाया। इस पर सदन में भारी हंगामा हुआ और सदस्यों के बीच तीखी बहस हुई।

ईरान ने अमेरिका का ...

इस कटेनर जहाज में शारराह के पास सामान भरा गया था, जो ओमान के रास्ते होर्मुज से गुजर रहा था, लेकिन जैसे ही आईआरजीसी ने कटेनर जहाज को चेतावनी भेजी, उसने अपना रास्ता बदल लिया। इस जहाज में किस तरह के सामान लदे थे, इसकी जानकारी अभी तक सामने नहीं आई है। होर्मुज से अब तक पाकिस्तान के कई जहाजों को ईरान ने गुजरने दिया है। कम से कम एक कटेनर की जानकारी आधिकारिक रूप से है, लेकिन अब अचानक से सेलन जहाज जहाज को वापस कर दिया है। यह ऐसे वक्त में हुआ है, जब इस्लामाबाद में अमेरिका और ईरान के बीच शांति समझौते को लेकर बैठक प्रस्तावित है। पाकिस्तान के हुसमराओं ने पिछले 24 घंटे में ईरान के बड़े नेताओं से कम से कम 3 बार बात की है। खुद पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने राष्ट्रपति मशूज पंजेशकियन से बात की। इसके बावजूद ईरान के जहाजों को इस्लामिक रिवाोल्यूशनरी गार्ड ने रोक दिया। ऐसे में कहा जा रहा है कि पाकिस्तान ईरान को सही तरीके से साथ नहीं पाया है।

सोनिया गांधी अस्पताल ...

मंगलवार रात 10:22 बजे सर गंगा राय अस्पताल में भर्ती कराया गया। अस्पताल के चेयरमैन डॉ अजय स्वरूप ने वज्रिप्त जारी कर बताया कि डॉक्टर उनकी स्थिति पर लगातार नजर बनाए हुए हैं। डॉक्टरों द्वारा उनकी विस्तृत जांच की जा रही है, जिसमें पेट और यूरिनरी ट्रैक में संभावित संक्रमण की जांच भी शामिल है। इलाज के तहत उन्हें एंटीबायोटिक्स दी जा रही हैं। अस्पताल की एक विशेषज्ञ टीम उनकी निगरानी कर रही है और आवश्यक चिकित्सा देखभाल प्रदान की जा रही है।

कांग्रेस और भारतीय ...

नाए मुख्यालय *इंदिरा भवन* का उद्घाटन कर दिया था, लेकिन इसके बावजूद पार्टी की गतिविधियां 24 अकबर रोड वाले पुराने कार्यालय से पहले की तरह ही चल रही थीं। अब विभाग ने इस पर नोटिस दिया है। उल्लेखनीय है कि साल 1978 से 24 अकबर रोड का बंगला कांग्रेस मुख्यालय के रूप में कार्य करता रहा है। पूरे 48 वर्षों तक वहीं पार्टी का दफ्तर चला और तमाम रणनीतियां तय हुईं। पिछले साल कांग्रेस ने कोर्टदामा माल स्थित इंदिरा भवन में अपना नया मुख्यालय बनाया, लेकिन अकबर रोड वाले बंगले से अभी भी पार्टी की गतिविधियों का संचालन किया जा रहा है।



इस बार कांग्रेस को वोट नहीं देगी जनता : मुख्यमंत्री

गुवाहाटी (हिस)। असम के मुख्यमंत्री डॉ. हिमंत विश्व शर्मा ने कहा है कि इस बार जनता कांग्रेस को वोट देने के मूड में नहीं है और राज्य में जनमत में स्पष्ट बदलाव देखा जा रहा है। कृष्णगुरु आश्रम में उपस्थित होने के दौरान बीती रात मीडिया से बातचीत में मुख्यमंत्री ने कहा कि उन्होंने लोगों के साथ सीधे संवाद किया है और उनकी राय जानी है। उनके अनुसार, जनता अब राजनीतिक बयानबाजी से ज्यादा रोजगार और विकास जैसे मुद्दों पर ध्यान दे रही है। उन्होंने कहा कि लोग यह जानना चाहते हैं कि कितनी नौकरियां दी जाएंगी और कितना विकास किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने यह भी दावा किया कि अब जनता कांग्रेस की बातें सुनने में रुचि नहीं रखती। राज्य में आगामी चुनावों को लेकर राजनीतिक गतिविधियां तेज हो गई हैं और विभिन्न दलों के नेता जनसंपर्क अभियान में जुटे हुए हैं।

असम में बदलाव चाहती है जनता, कांग्रेस की जीत का दावा : भूपेश बघेल

गुवाहाटी (हिस)। छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री और असम कांग्रेस के चुनावी पर्यवेक्षक भूपेश बघेल ने बुधवार को गुवाहाटी पहुंचकर दावा किया कि असम की जनता इस बार बदलाव चाहती है और कांग्रेस राज्य में मजबूती से जीत हासिल करेगी। मीडिया से बातचीत में बघेल ने कहा कि जिन पांच राज्यों में चुनाव हो रहे हैं, उनमें से कम से कम चार राज्यों-असम, तमिलनाडु, केरल और पुडुचेरी में कांग्रेस बेहतर प्रदर्शन करेगी। उन्होंने कहा कि जनता के रुझान से साफ संकेत मिल रहे हैं कि इस बार सत्ता परिवर्तन संभव है। असम के मुख्यमंत्री डॉ. हिमंत विश्व शर्मा द्वारा कांग्रेस के खराब प्रदर्शन के दावे पर प्रतिक्रिया देते हुए बघेल ने कहा कि शर्मा का लगातार चुनाव प्रचार में व्यस्त रहना उनकी चिंता को दर्शाता है। उन्होंने कहा कि यदि भाजपा को अपनी जीत पर भरोसा होता तो इतनी भागदौड़ की जरूरत नहीं पड़ती। बघेल ने आरोप लगाया कि भाजपा सरकार ने छह समुदायों को जनजाति का दर्जा देने सहित कई वादे पूरे नहीं किए। उन्होंने कहा कि 10 वर्षों तक सत्ता में रहने के बावजूद इन समुदायों को सिर्फ टांग गया है और इस बार वे भाजपा को समर्थन नहीं देंगे। मुख्यमंत्री पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाते हुए बघेल ने कहा कि राज्य के संसोधर्मा जैसे- जमीन,

कोयला और बालू का बड़े पैमाने पर दुरुपयोग हुआ है। उन्होंने डॉ. शर्मा को देश के सबसे भ्रष्ट मुख्यमंत्रियों में से एक बताया। अरुणोदय योजना को लेकर भी बघेल ने आरोप लगाया कि महिलाओं को दी जाने वाली आर्थिक सहायता का इस्तेमाल राजनीतिक दबाव बनाने के लिए किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि लाभार्थियों को यह संदेश दिया जा रहा है कि सहायता भाजपा के समर्थन पर निर्भर है। प्रसिद्ध असमिया गायक नृगमि गंगा का जिक्र करते हुए बघेल ने कहा कि राज्य के लोग उनके लिए न्याय चाहते हैं और वर्तमान सरकार में यह संभव नहीं है। बघेल ने कहा कि कांग्रेस राज्य के *जालि, माटी और भेटी* को रक्षा करेगी और आदिवासी व स्वदेशी लोगों को जमीन को बड़े कॉरपोरेट समूहों से बचाएगी। उन्होंने कहा कि असम में असली मुकाबला भाजपा से नहीं बल्कि *असली कांग्रेस* और *नकली कांग्रेस* के बीच है, जिसमें गौव गोगोई असली कांग्रेस का नेतृत्व कर रहे हैं। भाजपा की हैटिक जीत के दावे को खारिज करते हुए बघेल ने कहा कि राज्य में असल एक राजनीतिक सिंडिकेट की सरकार चल रही है। अबैध घुसपैठ के मुद्दे पर उन्होंने केंद्र सरकार, खासकर गृह मंत्री अमित शाह और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भूमिका पर भी सवाल उठाए।

असम के राज्यपाल केकेएचएसओयू के 8वें दीक्षांत समारोह में शामिल

गुवाहाटी। असम के राज्यपाल अशोक कृष्णकांत हैंडिक मुक्त विश्वविद्यालय (केकेएचएसओ) के कुलाधिपति श्री लक्ष्मण प्रसाद आचार्य आज यहां विश्वविद्यालय के 8वें दीक्षांत समारोह में शामिल हुए। इस अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में बोलते हुए, राज्यपाल श्री आचार्य ने कहा कि विश्वविद्यालय नई शिक्षा नीति 2020 के उद्देश्यों को आगे बढ़ाने में, विशेष रूप से 2035 तक उच्च शिक्षा में 50 प्रतिशत सकल नामांकन अनुपात का लक्ष्य प्राप्त करने की दिशा में प्रयास करने में, एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। राज्यपाल ने इस दीक्षांत समारोह को छात्रों के जीवन में एक निर्णायक मील का पत्थर बताया। उन्होंने कहा कि यह अवसर वर्षों की लगन, समर्पण और उपलब्धि को दर्शाता है। उन्होंने इस बात पर संतोष व्यक्त किया कि 50 प्रतिशत छात्र ग्रामीण पृष्ठभूमि से आते हैं, जिनमें से लगभग 60 प्रतिशत महिलाएं हैं; यह संस्था की समावेशी पहुंच और



सामाजिक प्रतिबद्धता को उजागर करता है। इस अवसर पर प्रख्यात शिक्षाविद कृष्णकांत हैंडिक को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए राज्यपाल ने कहा कि उनका जीवन शिक्षा के सच्चे उद्देश्य का एक आदर्श उदाहरण है- जो केवल ज्ञान प्राप्त करना ही नहीं, बल्कि चरित्र और मूल्यों का निर्माण करता भी है। राज्यपाल ने कहा कि वर्तमान युग में, मुक्त और दूरस्थ शिक्षा प्रणाली ने बहुत अधिक महत्व प्राप्त कर लिया है। उन्होंने कहा

कि शिक्षा का यह माध्यम उन असंख्य व्यक्तियों के लिए एक महत्वपूर्ण मार्ग के रूप में उभरा है जो विभिन्न बाधाओं के कारण औपचारिक शिक्षा प्राप्त करने में असमर्थ हैं। राज्यपाल ने कहा कि लचीलापन ही मुक्त और दूरस्थ शिक्षा प्रणाली की मुख्य शक्ति है, जो शिक्षार्थियों को अपनी परिस्थितियों के अनुकूल तरीके से शिक्षा प्राप्त करने में सक्षम बनाती है। शिक्षा के बदलते परिदृश्य का उल्लेख करते हुए

राज्यपाल ने कहा कि आज शिक्षा केवल ज्ञान प्राप्त करने की पारंपरिक सीमाओं से कहीं आगे निकल गई है; इसे शिक्षार्थियों को आज की दुनिया की मांगों को पूरा करने के लिए आवश्यक कौशल, अनुकूलन क्षमता और जिम्मेदारी की भावना से सुसज्जित करना चाहिए। इससे पहले, राज्यपाल ने चिकित्सा और सामुदायिक स्वास्थ्य के क्षेत्र में उनके योगदान की मान्यता स्वरूप, प्रख्यात न्यूरोलॉजिस्ट डॉ. नोमल चंद्र बोराह को *डॉक्टर ऑफ साइंस* की मानद उपाधि प्रदान की। यह उल्लेखनीय है कि इस अवसर पर 22 छात्रों को *ब्लड*, 12,500 छात्रों को स्नातकोत्तर और 4,237 छात्रों को स्नातक की उपाधियां प्रदान की गईं। इससे पूर्व, केकेएचएसओयू के कुलपति प्रो. राजेंद्र प्रसाद दास ने स्वागत भाषण दिया। इस अवसर पर स्वागत-व्यवस्था चक्रवाग महाराष्ट्र मुक्त विश्वविद्यालय के कुलपति प्रो. संजीव अर्जुनराव सोनावणे सम्मानित अतिथि के रूप में उपस्थित थे।

रंगिया : हनुमान जन्मोत्सव की तैयारियां जोरों पर

रंगिया (विभास)। प्रतिवर्ष की तरह इस बार भी रंगिया के श्री श्री राधाकृष्ण मंदिर प्रांगण में श्री हनुमान जन्मोत्सव बड़े उत्साह के साथ मनाया जाएगा। आगामी 1 और 2 अप्रैल को होने वाले इस दो दिवसीय महोत्सव की तैयारियां जोर-शोर से चल रही हैं। आयोजन समिति के अध्यक्ष पवन कुमार जायोरिया, सचिव जितेंद्र जाजोरिया और कोषाध्यक्ष मनोज अग्रवाल ने बताया कि सभी कार्यभार वितरित कर दिए गए हैं। कार्यक्रम के अंतर्गत पहले दिन (1 अप्रैल, बुधवार): सुबह 8-11 बजे मंदिर संचालन समिति के अध्यक्ष महेश सीकरिया ध्वजारोहण करेंगे। 8-31 बजे से अखंड रामायण पूजन-पठन शुरू होगा। अपराह्न 4-01 बजे पुष्पाभिषेक और संध्या 6-11 बजे 108 दीप प्रज्वलन (मंदिर संचालन समिति के महासचिव प्रमोद अग्रवाल द्वारा) होगा। रात्रि 9-11 बजे स्थानीय बजरंग भजन मंडली द्वारा कीर्तन किया जाएगा। दूसरे दिन (2 अप्रैल, बृहस्पतिवार): सुबह 10-11 बजे अखंड रामायण पाठ का समापन और आरती होगी। 11-11 बजे बाबा का भव्य श्रावण दर्शन, अखंड ज्योति प्रज्वलन, महाआरती, पुष्पांजलि व प्रसाद वितरण के बाद महाप्रसाद अमृत भंडारा शुरू होगा। उसके बाद बाबा को विशाल शोभायात्रा सुंदर झांकियों संग नगर भ्रमण कर मंदिर लौटेंगी। संध्या में महाआरती के बाद छपन भोग लगेगा। रात्रि 9 बजे लोकाकता से आमंत्रित गायक कलाकार राहुल शर्मा द्वारा भजन संध्या होगी। आयोजकों द्वारा कार्यक्रम में सभी भक्तों की उपस्थिति एवं सहयोगिता की कामना की गई है।

चुनाव से पहले सामागुड़ी में गांजा के खिलाफ अभियान एक तस्कर गिरफ्तार

नगांव (हिस)। आगामी चुनावों के मद्देनजर सामागुड़ी पुलिस ने गांजा तस्करों के खिलाफ एक विशेष अभियान चलाते हुए एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। पुलिस प्रवक्ता ने बुधवार को बताया कि यह अभियान गुप्त सूचना के आधार पर सामागुड़ी के बरमा क्षेत्र में चलाया गया। सूचना मिलते ही पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए इलाके में तलाशी अभियान चलाया और सकिंदर तस्कर को हिरासत में लिया। गिरफ्तार तस्कर की पहचान कुमुद अली के रूप में हुई है। पुलिस के अनुसार वह गांजा तस्करों से जुड़े होने के संदेह में पकड़ा गया है। फिलहाल पुलिस गिरफ्तार कुमुद अली से पूछताछ जारी रखे हुए है ताकि इस अवैध कारोबार से जुड़े अन्य लोगों और नेटवर्क के बारे में जानकारी हासिल की जा सके।

कांग्रेस के पास स्वदेशी समुदायों को आश्वस्त करने के लिए कोई स्पष्ट एजेंडा नहीं : असम भाजपा

ऐसा प्रतीत होता है कि उनका प्राथमिक उद्देश्य केवल भाजपा के नेतृत्व वाले गठबंधन का विरोध करने तक ही सीमित है। इसके विपरीत, मुख्यमंत्री डॉ. हिमंत विश्व शर्मा प्रतिदिन तीन से चार विधानसभा क्षेत्रों में एक व्यापक और जोरदार चुनावी अभियान का सक्रिय रूप से नेतृत्व कर रहे हैं, जिसमें उन्हें जनता की भारी भागीदारी मिल रही है। अपने पिछले कार्यकाल की उपलब्धियों को उजागर करते हुए, मुख्यमंत्री सीधे नागरिकों से जुड़ रहे हैं और उन्हें जनता का जबरदस्त समर्थन मिल रहा है। यह अभियान अब *विजय संकल्प सभा* के शुभारंभ के साथ एक नए चरण में प्रवेश कर गया है, जिसके माध्यम से मुख्यमंत्री असम के विकास के लिए एक भविष्योन्मुखी रूपरेखा प्रस्तुत कर रहे हैं। उन्होंने कई महत्वपूर्ण घोषणाएं की हैं, जिनमें अतिक्रमण से अतिरिक्त सरकारी जमीन वापस लेना शामिल है; पहले ही वापस ली गई 1.5 लाख बीघा जमीन के अलावा, भविष्य में 5 लाख बीघा जमीन को अतिक्रमण मुक्त कराने का लक्ष्य रखा गया है। सरकार ने रोजगार और आत्मनिर्भरता पर भी अपना विशेष जोर दिया है।

उन्होंने कहा कि लगभग 2 लाख युवाओं को पहले ही योग्यता-आधारित, पारदर्शी और भ्रष्टाचार-मुक्त सरकारी रोजगार प्रदान करने के बाद, सरकार ने 2 लाख और युवाओं के लिए रोजगार के अवसर सृजित करने की योजना की घोषणा की है। इसके अतिरिक्त, लगभग 2 लाख युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने के बाद, सरकार का लक्ष्य है कि यदि वह दोबारा सत्ता में आती है, तो इस पहल का विस्तार करके 10 लाख तक युवाओं को इसका लाभ पहुंचाया जाए। इस बीच, भाजपा ने असम प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष गौरव गोगोई के सीमित जनसंपर्क पर सवाल उठाते हुए कहा है कि उनका चुनाव प्रचार ज्यादातर जोरदार निर्वाचन क्षेत्र तक ही सीमित रहा है। पार्टी ने कांग्रेस के स्टाफ प्रचारकों की सूची पर भी संदेह जताया और कहा कि पार्टी के कुछ वरिष्ठ नेताओं के पुराने बयान शायद असम की जनता को रास न आए। भाजपा ने दोहराया कि मतदाता स्पष्टता, स्थिरता और विकास-उन्मुख एक मजबूत दृष्टिकोण चाहते हैं, जो उसके अनुसार, इस समय मुख्यमंत्री के चुनाव प्रचार और शासन के तरीके में साफ तौर पर दिखाई दे रहा है।

नगांव में मुख्यमंत्री की चुनावी जनसभा आयोजित



नगांव में आयोजित एक चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री एवं भाजपा के स्टाफ प्रचारक डॉ. हिमंत विश्व शर्मा ने कई अहम घोषणाएं कीं। नगांव शहर के समीप भोटाइगांव के भोटाइडैका खेल मैदान में आयोजित इस सभा में मुख्यमंत्री ने 60 नंबर नगांव-बटरदा विधानसभा क्षेत्र से भाजपा-अगम गठबंधन के उम्मीदवार रूपक शर्मा के समर्थन में प्रचार किया। अपने संबोधन में उन्होंने कहा कि यदि राज्य में फिर से भाजपा की सरकार बनी है तो लगभग दो लाख युवाओं को रोजगार के अवसर प्रदान किए जाएंगे। मुख्यमंत्री ने यह भी घोषणा की कि आगामी दिनों में पांच लाख बीघा अतिक्रमित भूमि को मुक्त करया जाएगा। उन्होंने कहा कि राज्य की 15 लाख महिलाओं को नई तरह से अरुणोदय योजना में शामिल किया जाएगा, जबकि नगांव जिले में 10 हजार महिलाओं को इसका लाभ मिलेगा। इसके अलावा प्रत्येक महिला को 25 हजार रूपए की सहायता देने और छात्रों को मुफ्त शिक्षा प्रदान करने का भी आश्वासन दिया गया। अपने भाषण के दौरान मुख्यमंत्री ने गुवाहाटी-नगांव एक्सप्रेस हाईवे के निर्माण की भी घोषणा की। इस चुनावी सभा में उम्मीदवार रूपक शर्मा के अलावा बड़ी संख्या में पार्टी के नेता, कार्यकर्ता और समर्थक उपस्थित रहे।

नगांव (हिस)। आसम असम विधानसभा चुनाव के मद्देनजर नगांव जिले की सभी सात विधानसभा सीटों पर राजनीतिक गतिविधियां तेज हो गई हैं। इसी क्रम में बुधवार को नगांव में आयोजित एक चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री एवं भाजपा के स्टाफ प्रचारक डॉ. हिमंत विश्व शर्मा ने कई अहम घोषणाएं कीं। नगांव शहर के समीप भोटाइगांव के भोटाइडैका खेल मैदान में आयोजित इस सभा में मुख्यमंत्री ने 60 नंबर नगांव-बटरदा विधानसभा क्षेत्र से भाजपा-अगम गठबंधन के उम्मीदवार रूपक शर्मा के समर्थन में प्रचार किया। अपने संबोधन में उन्होंने कहा कि यदि राज्य में फिर से भाजपा की सरकार बनी है तो लगभग दो लाख युवाओं को रोजगार के अवसर प्रदान किए जाएंगे। मुख्यमंत्री ने यह भी घोषणा की कि आगामी दिनों में पांच लाख बीघा अतिक्रमित भूमि को मुक्त करया जाएगा। उन्होंने कहा कि राज्य की 15 लाख महिलाओं को नई तरह से अरुणोदय योजना में शामिल किया जाएगा, जबकि नगांव जिले में 10 हजार महिलाओं को इसका लाभ मिलेगा। इसके अलावा प्रत्येक महिला को 25 हजार रूपए की सहायता देने और छात्रों को मुफ्त शिक्षा प्रदान करने का भी आश्वासन दिया गया। अपने भाषण के दौरान मुख्यमंत्री ने गुवाहाटी-नगांव एक्सप्रेस हाईवे के निर्माण की भी घोषणा की। इस चुनावी सभा में उम्मीदवार रूपक शर्मा के अलावा बड़ी संख्या में पार्टी के नेता, कार्यकर्ता और समर्थक उपस्थित रहे।

नगांव कांग्रेस में इस्तीफों की आंधी, सैकड़ों नेता व कार्यकर्ताओं ने छोड़ा दल

नगांव (हिस)। नगांव जिला कांग्रेस में इस्तीफों की आंधी चल पड़ी है, जिससे पार्टी का संगठनात्मक ढांचा कमजोर होने की आशंका जताई जा रही है। आंतरिक असंतोष और नेतृत्व को लेकर मतभेदों के बीच बड़ी संख्या में नेताओं और कार्यकर्ताओं ने पार्टी से किनारा कर लिया है। युवा कांग्रेस के उपाध्यक्ष पल्लवज्योति नाथ के नेतृत्व में सी से अधिक नेता-कार्यकर्ताओं ने सामूहिक रूप से इस्तीफा दिया। इस्तीफा देने वाले नेताओं ने स्पष्ट रूप से कहा कि वे रिक्रुल हुसैन के निर्देशों और कार्यशैली के अनुसार काम करने में सक्षम नहीं हैं। सूत्रों के अनुसार, इस सामूहिक इस्तीफे से नगांव में कांग्रेस की जमीनी पकड़ कमजोर पड़ सकती है। पार्टी के भीतर बहते असंतोष को देखते हुए आगामी राजनीतिक परिस्थितियों में इसका व्यापक असर पड़ने की संभावना जताई जा रही है।

कार्बी आंग्लांग में 60 पोलिंग स्टेशनों का प्रबंधन महिलाएं करेंगी

सोहन प्रसाद महतो डिफू। चुनावी प्रक्रिया में महिलाओं की भागीदारी को मजबूत करने के उद्देश्य से एक प्रगतिशील पहल के तहत, कार्बी आंगलों के जिला प्रशासन ने आगामी विधानसभा चुनाव, 2026 के दौरान तीन विधानसभा क्षेत्रों में 60 पोलिंग स्टेशनों की पहचान की है, जिनका प्रबंधन विशेष रूप से महिला अधिकारियों द्वारा किया जाएगा। यह पहल भारत निर्वाचन आयोग के दिशानिर्देशों के अनुसार की गई है। पहचाने गए पोलिंग स्टेशन 108-बोकाजान (एसटी) एलएसी, 109-होराघाट (एसटी) एलएसी, और 110-दीफू (एसटी) एलएसी में वितरित हैं, जिसमें प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र में 20 पोलिंग स्टेशन निर्धारित किए गए हैं। 108-बोकाजान (एसटी) एलएसी में 143 हेमफू महिला पोलिंग स्टेशन थे हैं: 143 हेमफू लोखिमोन इंग्लिश एमई स्कूल (आर/डब्ल्यू), 144 हेमफू लोखिमोन इंग्लिश एमई स्कूल (एल/डब्ल्यू), 148 बोकाजान एचएस स्कूल, 150 बोरजान हाई स्कूल, 151 सुखानी

इंग्लिश एलपी स्कूल (आर/डब्ल्यू), 152 सुखानी इंग्लिश एलपी स्कूल (एल/डब्ल्यू), 153 बोकाजान कॉलेज, 154 जिनबाबा हिंदी हाई स्कूल (आर/डब्ल्यू), 155 जिनबाबा हिंदी हाई स्कूल (एल/डब्ल्यू), 156 जिनबाबा हिंदी हाई स्कूल (एम/डब्ल्यू), 157 आरजी हाई स्कूल, 158 जगत बरुआ एमई स्कूल, 159 विवेकानंद एचएस स्कूल (आर/डब्ल्यू), 160 विवेकानंद एचएस स्कूल (एल/डब्ल्यू), 161 विवेकानंद एमई स्कूल (एल/डब्ल्यू), 162 विवेकानंद एमई स्कूल (आर/डब्ल्यू), 167 सीसीआई एलपी स्कूल, 168 सुखनंजन एमई स्कूल (आर/डब्ल्यू), 169 सुखनंजन आदर्श हिंदी एमई स्कूल, और 170 सुखनंजन एमई स्कूल (एल/डब्ल्यू)। 109-होराघाट (एसटी) एलएसी के तहत, पहचाने गए मतदान केंद्र हैं: 29 देगांव हाई स्कूल (एल/डब्ल्यू), 31 देगांव हाई स्कूल (आर/डब्ल्यू), 66 दोकमोका हायर सेकेंडरी स्कूल (एल/डब्ल्यू), 67 दोकमोका हायर सेकेंडरी स्कूल (आर/डब्ल्यू), 107 उत्तर

बोरबिल एलपी स्कूल, 108 उत्तर बोरबिल ब्लॉक नंबर 2 एलपी स्कूल, 159 होराघाट हायर सेकेंडरी स्कूल (एल/डब्ल्यू), 160 होराघाट हायर सेकेंडरी स्कूल (आर/डब्ल्यू), 162 जमुगुरी एलपी स्कूल (एल/डब्ल्यू), 163 होराघाट सरकारी एमई स्कूल ((एल/डब्ल्यू)), 164 होराघाट सरकारी एमई स्कूल (एल/डब्ल्यू), 197 लांघिन सरकारी एमई स्कूल (आर/डब्ल्यू), 198 लांघिन सरकारी एमई स्कूल (मध्य), 199 लांघिन सरकारी एमई स्कूल (एल/डब्ल्यू), 200 बहबारी एलपी स्कूल, 201 जमुगुरी एलपी स्कूल (आर/डब्ल्यू), 202 जमुगुरी एलपी स्कूल (एल/डब्ल्यू), 203 गोरोइमारी एलपी स्कूल, और 304 लांघिन पाम गांव हाई स्कूल (आर/डब्ल्यू)। 110-दीफू (एसटी) एलएसी के तहत, पहचाने गए मतदान केंद्र हैं: 124 अमोलपट्टी एलपी स्कूल (एल/डब्ल्यू), 125 अमोलपट्टी एलपी स्कूल (एल/डब्ल्यू), 129 डिफू सरकारी गलर्स हाई स्कूल (आर/डब्ल्यू), 133 डिफू सरकारी। बांयज एचएस स्कूल (दक्षिण), 134 डिफू सरकारी गलर्स हाई स्कूल (बायां विंग), 135 डिफू सरकारी

बांयज एचएस स्कूल, 139 पुलिस रिजर्व एलपी स्कूल (दायां विंग), 140 पुलिस रिजर्व एलपी स्कूल (बायां विंग), 148 डिफू टाउन बेसिक स्कूल (दायां विंग), 149 डिफू टाउन बेसिक स्कूल (बायां विंग), 150 मॉटेसरी स्कूल, 155 आदर्श हिंदी एमई स्कूल, 159 डिफू गलर्स कॉलेज (दायां विंग), 160 डिफू गलर्स कॉलेज (मध्य), 161 डिफू गलर्स कॉलेज (बायां विंग), 162 बिनापानी हाई स्कूल (दायां विंग), 163 बिनापानी हाई स्कूल (बायां विंग), 169 शीतलावारी एलपी स्कूल (दायां विंग), 170 शीतलावारी एलपी स्कूल (बायां विंग), और 175 चंद्रशेखर टैटोन स्कूल (दायां विंग)। ये मतदान केंद्र पूरी तरह से महिला अधिकारियों द्वारा संचालित किए जाएंगे, जो समावेशी शासन और महिला सशक्तिकरण के प्रति प्रशासन की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। इस पहल से महिला मतदाताओं में आत्मविश्वास बढ़ने और महत्वपूर्ण लोकतांत्रिक जिम्मेदारियों के प्रबंधन में महिला कर्मियों की क्षमता और नेतृत्व कौशल को प्रदर्शित करने की उम्मीद है।

शिवसागर में अखबारों के बंडल जलाने पर राजनीतिक एवं मीडिया संगठनों ने की निंदा

गुवाहाटी (हिस)। शिवसागर में बुधवार को दिन-दहाड़े कुछ बदमाशों ने कथित तौर पर एक प्रमुख असमिया दैनिक अखबार के बंडलों में आग लगा दी। इस घटना की राजनीतिक पार्टियां, पत्रकार संगठनों और नागरिक समाज ने कड़ी निंदा की और इसे प्रेस की आजादी पर सीधा हमला बताया है। उल्लेखनीय है कि, शिवसागर विधानसभा क्षेत्र में किसी राजनीतिक दल से कथित तौर पर जुड़े कुछ लोगों पर इस घटना को अंजाम देने के गंभीर आरोप लगे हैं। इससे यह चिंता बढ़ गई है कि कहीं राजनीतिक प्रचार का दुरुपयोग हिंसा और डराने-धमकाने को सही ठहराने के लिए तो नहीं किया जा रहा है। शिवसागर पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। जानकारी के अनुसार, दो व्यक्तियों द्वारा कथित तौर पर दिन-दहाड़े एक प्रमुख असमिया दैनिक अखबार के बंडलों में आग लगाने के इस कृत्य की, जिसे प्रेस की आजादी पर हमला बताकर व्यापक रूप से निंदा की गई है। आरोपियों पर यह भी आरोप है कि उन्होंने *रायजोर दल* के एक कार्यकर्ता पर हमला किया, जिससे इस विधानसभा क्षेत्र में तनाव और बढ़ गया है। बताया जा रहा है कि यह घटना चुनावी प्रचार की आड़ में हुई, जिससे मौजूदा चुनावी मौसम के दौरान राजनीतिक मर्यादा के गिरते स्तर को लक्ष्य आंशिक और गहरी हो गई है। इस घटना की भाजपा, अगप, कांग्रेस के साथ ही मीडिया संगठनों ने घटना पर कड़ी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने इस कृत्य की निंदा करते हुए इसमें शामिल लोगों के खिलाफ तत्काल और कड़ी कार्रवाई की मांग की है। पार्टी प्रतिनिधियों ने जोर देकर कहा कि चुनावी प्रचार के नाम पर होने वाली हिंसा और गुंडागर्दी को किसी भी हाल में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हालांकि, अंतिम सूचना मिलने तक किसी को भी गिरफ्तार नहीं किया गया है।

जुबीन गर्ग मामले में सिंगापुर के फैसले पर गौरव गोगोई ने जताई नाराजगी

गुवाहाटी (हिस)। असम प्रदेश कांग्रेस कमेटी (एपीसीसी) के अध्यक्ष गौरव गोगोई ने बुधवार को जुबीन गर्ग की मौत के मामले में सिंगापुर कोर्ट के फैसले पर कड़ी नाराजगी जताते हुए कहा कि इससे मुख्य आरोपियों को कानूनी राहत मिली है। खानापड़ा में आयोजित संबाददाता सम्मेलन में गोगोई ने कहा कि यह फैसला पहले किए गए दावों के विपरीत है और इससे कई सवाल खड़े हो गए हैं। उन्होंने कहा कि ऐसे फैसले पर विश्वास करना मुश्किल है। उन्होंने आरोप लगाया कि न्याय दिलाने के बजाए भाजपा और मुख्यमंत्री डॉ. हिमंत विश्व शर्मा चरित्र हनन में लगे हैं, जबकि इस फैसले से आरोपियों को फायदा हुआ है।

राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ पर्यवेक्षक और जिला निर्वाचन अधिकारी की बैठक आयोजित

गुवाहाटी (हिस)। आसम विधानसभा चुनाव 2026 में भारत के निर्वाचन आयोग द्वारा नियुक्त कामरूप (मेट्रो) जिले के सामान्य पर्यवेक्षक प्रदीप कुमार कृष्णराव डोंगे एवं हिम शेखर गुप्ता, व्यय पर्यवेक्षक रंजन प्रकाश एवं रजत सेन तथा पुलिस पर्यवेक्षक असलाम खान की उपस्थिति में, जिला निर्वाचन अधिकारी एवं जिला आयुक्त सपना पल की अध्यक्षता में बुधवार को स्वीकृत राष्ट्रीय एवं राज्यस्तरीय राजनीतिक दलों के कामरूप (मेट्रो) जिला समितियों के प्रतिनिधियों के साथ एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। जिला निर्वाचन अधिकारी एवं जिला आयुक्त के कार्यालय सभाकक्ष में आयोजित बैठक में आगामी चुनाव प्रक्रिया को स्वतंत्र और पारदर्शी रूप से सम्पन्न कराने

की लिए निर्वाचन आचार संहिता, मतदान केंद्र और स्ट्रॉग रूम की तैयारी, मतदान, निर्वाचन खर्च आदि प्रत्येक पहलू को समीक्षा की गयी। जिला निर्वाचन अधिकारी प्रत्येक राजनीतिक दल को निर्वाचन आचार संहिता का पालन करने के साथ-साथ निर्वाचन आयोग की नीतियों और निर्देशों का पालन करने का आह्वान किया। इसके अतिरिक्त, 26 मार्च को शाम चार बजे मतदान अधिकारियों के साथ आयोजित की जाने वाली बैठक में उपस्थित रहने के लिए जिला निर्वाचन अधिकारी राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों को आमंत्रित किया। बैठक में गुवाहाटी (मेट्रो) पुलिस आयुक्त डॉ. पार्थ साठ्वी महत् सहित निर्वाचन प्रक्रिया से जुड़े उच्च पदस्थ अधिकारी उपस्थित रहे।

तीन करोड़ रुपए मूल्य की हेरोइन जब्त, दो गिरफ्तार कामरूप (हिस)। असम में नशीले पदार्थों की तस्करी पर एक बड़ी कार्रवाई करते हुए पुलिस की स्पेशल टास्क फोर्स (एसटीएफ) और कामरूप पुलिस के एक संयुक्त अभियान में अमीनगांव में हेरोइन की एक बड़ी खेप जब्त की गई। पुलिस सूत्रों ने बुधवार को बताया कि विशिष्ट खुफिया जानकारी पर कार्रवाई करते हुए, संयुक्त टीम ने बीती रात एक लक्षित अभियान के दौरान एक मारुति अट्टांगा (एएस-01बीक्यू-5651) को रोका। वाहन की गहन तलाशी लेने पर दरवाजों के पैल के अंदर चालाकी से छिपाई गई नशीली दवाएं बरामद हुईं, जिससे पता चलता है कि पकड़े जाने से बचने की एक सुनियोजित कोशिश की गई थी। अधिकारियों ने हेरोइन से भरे 25 साबुनदानी बरामद किए, जिनका वजन लगभग 350 ग्राम (पैकेजिंग को छोड़कर) था। जब किए गए इस प्रतिबंधित सामान की बाजार में कीमत लगभग तीन रूढ़ए आंकी गई है। इस मामले में पुलिस ने मणिपुर के चुराचंदपुर जिले के रहने वाले दो लोगों को गिरफ्तार किया गया है।

संपादकीय

पीएम संबोधन, 'ट्रंपी युद्धविराम'

प्रधानमंत्री मोदी ने लोकसभा में वक्तव्य देकर पश्चिम एशिया के संकट और संघर्ष को कोरोना महामारी जैसी गंभीर और अभूतपूर्व चुनौती माना है। उन्होंने देश को एकजुटता का आह्वान किया और इस आर्थिक, सुरक्षा संबंधी, मानवीय चुनौती को 'चुनौती' देने का होसला दिया। प्रधानमंत्री ने देश को आखिरवर्त भी किया और जानकारी भी साझा की कि पहले हम 27 देशों से आयात करते थे, लेकिन अब 41 देशों से विविध सामान ले रहे हैं। देश में 53 लाख मीट्रिक टन कच्चे तेल का 'रणनीतिक भंडार' है। उसे बढ़ा कर 65 लाख मीट्रिक टन करने पर काम किया जा रहा है। अब हम पेट्रोल में 20 फीसदी ईथेनॉल का मिश्रण करते हैं, लिहाजा 4.5 करोड़ बैरल कम तेल आयात करना पड़ रहा है। यह प्रयोग सफल रहा है। रेलवे का लगभग 100 फीसदी बिजलीकरण किया जा चुका है, लिहाजा डीजल और कोयले की खपत नगण्य हो गई है। देश में खाद्यान्न के पर्याप्त भंडार हैं और खरीफ की बुवाई के लिए उर्वरकों की पूरी व्यवस्था है। देश में यूरिया के 6 प्लांट लगाए गए हैं, जो 76 लाख मीट्रिक टन यूरिया का उत्पादन कर रहे हैं। किसानों को 22 लाख सोलर पंप दिए गए हैं। देश में बिजली उत्पादन की पर्याप्त मात्रा है और 1500 मेगावाट पनबिजली जोड़ी जा रही है। वैकल्पिक ऊर्जा के तौर पर 250 गीगावाट का उत्पादन किया जा रहा है। मानवीय स्तर पर देखें, तो ईरान युद्ध शुरू होने के बाद 3.75 लाख भारतीयों को वापस लाए हैं। ईरान से भी करीब 1000 भारतीय सुरक्षित लौटे हैं। मीडिकल के 700 छात्रों को भी वापस लाने में हम सफल रहे हैं। भारतीय दूतावास 24 घंटे काम कर रहे हैं और भारतीयों के संपर्क में हैं। बहरहाल यह संसद में प्रधानमंत्री मोदी के वक्तव्य का सारांश है। यह उनका दायित्व भी था कि देश को यथासंभव तैयार 'राष्ट्र' के नाम संबोधन' हो नहीं, बल्कि वैश्विक संदेश मानते हैं। प्रधानमंत्री ने बार-बार मानवता की रक्षा और उसके हित में तनाव, युद्ध को अतिरंजित खत्म करने की अपील की है। भारत संयम, संवाद, शांति, स्थिरता और कूटनीतिक का पक्षधर रहा है। प्रधानमंत्री के वक्तव्य के दो-अर्धों घंटे बाद ही अमरीकी राष्ट्रपति ट्रंप ने, अज्ञानकारी, एकांतव्य और पांच दिनों का युद्धविराम घोषित कर दिया। उन्होंने दावा किया कि ईरान के साथ बातचीत सार्थक और सकारात्मक रही है। ईरान अमरीकी के साथ डील क्लमक चाहता है। ईरान कैसी डील...! अमरीका ने तो ईरान के पाँच प्लांट तबाह करने के लिए 48 घंटे की धमकी दी थी, लेकिन 12 घंटे शेष रहते ही युद्धविराम का ऐलान कर दिया। क्या यह ट्रंप का नया छलावा, षड्यंत्र है अथवा वह युद्ध से बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं? राष्ट्रपति ट्रंप ने यह भी दावा किया कि अब ईरान परमाणु हथियार नहीं बनाएगा। हम कई मुद्दों पर सहमत हैं, लिहाजा तय किया गया है कि अमरीका पांच दिन तक कोई भी हमला नहीं करेगा। युद्ध विनाश को भी निरोध दे दिए गए हैं, लेकिन ईरान ने ट्रंप के बातचीत के दावे को सिरे से ही खारिज कर दिया है। न कोई बातचीत हुई है और न ही किसी डील की अपेक्षा है। अमरीका ने बातचीत का संदेश भेजा जरूर था, जिसे ईरान ने खारिज दिया था। ईरान का मानना है कि ट्रंप ईरान के पलटवार तबाही वाले हमलों की चेतावनी से डर गए हैं, लिहाजा युद्ध में पीछे हटे हैं। अमरीका एक बार फिर आग गया है। वैश्विक राष्ट्रपति ट्रंप की घोषणा से ही कच्चे तेल की कीमतें 15-16 फीसदी लुढ़क कर 96 डॉलर पर आ गईं। शेयर बाजारों में भी उछाल देखा गया। सवाल यह है कि क्या अब राष्ट्रपति ट्रंप ईरान के साथ 'स्वस्थी युद्धविराम' के मुद्द में हैं? अमरीका में ही चोतरफा विरोध जाँच है। संसद और सीनेट के मध्यवर्ती चुनाव इसी साल हैं। यदि ट्रंप की 'रिपब्लिकन पार्टी' का संसद में बहुमत समाप्त होगा, तो राष्ट्रपति के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव भी लाया जा सकता है। अमरीका में आर्थिक स्थितियों बेहतर खराब हैं। क्या उन्हें सैन्य विरोध होकर राष्ट्रपति की घोषणा की गई है? बहरहाल इजरायल इससे सहमत नहीं है, लिहाजा ईरान पर लगातार हमले कर रहा है। ईरान भी आक्रमक जवाब दे रहा है। युद्धविराम के मायने क्या है फिर? दोनों ओर से हमले किए जा रहे हैं, खूब बारूद फूँका जा रहा है।

कुछ

अलग

मोहल्ला हैप्पीनेस रिपोर्ट मुर्दाबाद...

वैसे

तो हमारे मोहल्ले में आवारा कुत्तों को छोड़कर कोई भी हैप्पी नहीं, पति अपनी बाँवों से परेशान है तो बीवी अपने पति से। बेटा अपने बाप से परेशान है तो बाप अपने बेटे से। बहन अपने भाई से परेशान है तो भाई अपनी बहन से। ये पड़ोसी अपने बगल के पड़ोसी से परेशान है तो वो पड़ोसी अपने अगल के पड़ोसी से। कोई अपनी टंकी में हर रोज पानी न आने से परेशान है तो कोई दूसरों की टंकी अतिरंजित होने से। कोई अपनी कमीज उसकी कमीज से अधिक सफेद होने से परेशान है तो कोई...मोहल्ले में जीव एक तो परेशानियाँ अनक। इतनी परेशानियों के बीच फिर भी हम हर साल किसी भी पड़ावेट एजेंसी से अपने मोहल्ले का रस्म अदायगी के लिए सालाना हैप्पीनेस सर्वे करा लेते हैं ताकि पता होतु हूँ भी पता चल जाए कि किस बेटे का हैप्पीनेस रैंक पिछले साल की अपेक्षा इस साल कितना गिरा है। असल में क्या है कि ज्यों ज्यों हमारा जीवन स्तर ऊंचा होता जा रहा है त्यों त्यों पता नहीं हम क्यों और भी अहर्निष होते जा रहे हैं। इसी परंपरा को जीवित रखते हुए हमने अपने मोहल्ले के जीवों का इस बार भी सालाना हैप्पीनेस स्तर मापने के लिए एक प्राइवेट एजेंसी से हैप्पीनेस सर्वे करवाया ताकि सर्वे के बाद सालाना हैप्पीनेस रिपोर्ट जनरल हाउस में पेश की जाए। और मित्रो! कल हमारे मोहल्ले के मोहल्ला विकास समिति के लाफ टाइम अध्यक्ष ने मोहल्ले की वार्षिक हैप्पीनेस रिपोर्ट जनरल हाउस में सर्वजनिक की तो तथ्यकीथत हैप्पीनेस परेशान हो उठे। वे भी जिन्हें पता था कि वे पक्का हैप्पीनेस रिपोर्ट में सबसे नीचे होंगे।

दृष्टि

कोण

कालेज छात्रों का मानसिक स्वास्थ्य

देश में उच्च शिक्षा की रेगुलेटरी संस्था, यूजीसी ने एक नई पहल करते हुए कालेज और यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले छात्रों को मेटल हेल्थ, फिटनेस, यौनि कि मानसिक स्वास्थ्य और खुशनुमा जिंदगी को लेकर खास गाइडलाइंस जारी की हैं। अब सिर्फ पढ़ाई ही नहीं, बल्कि छात्रों की मानसिक स्थिति, तनाव और जीवनशैली पर भी खास ध्यान दिया जाएगा। भारत ही नहीं, यहाँ तक कि पूरे संयुक्त राज्य अमेरिका में, इस समय 45 फीसदी से अधिक कालेज छात्र मानसिक स्वास्थ्य समस्याओं से जूझ रहे हैं, जिसके कारण डिग्री पूरी न कर पाने की दर 39 फीसदी तक पहुँच गई है। यूजीसी का मानना है कि उच्च शिक्षा केवल किताबी तक सीमित नहीं होनी चाहिए। यह छात्रों के जीवन को बेहतर बनाने और उन्हें समाज के लिए तैयार करने का जरिया है। ऐसे में संस्थानों को जिम्मेदारी बनती है कि वे छात्रों को एक सुरक्षित, सकारात्मक और सपोर्टिव माहौल दें, जहाँ वे बिना डर और दबाव के आगे बढ़ सकें। इन गाइडलाइंस में खासतौर पर उन समस्याओं को ध्यान में रखा गया है

जिनसे आज के छात्र जूझ रहे हैं। पढ़ाई का दबाव, करियर की चिंता, दोस्तों का दबाव, तनाव, डिप्रेशन और व्यवहार से जुड़ी दिक्कतें आज आम हो गई हैं। यूजीसी ने संस्थानों से कहा है कि वे इन समस्याओं को गंभीरता से लें और समय रहते समाधान निकालें। यूजीसी ने यह भी कहा है कि कालेज और यूनिवर्सिटी का माहौल सिर्फ क्लासरूम तक सीमित नहीं होना चाहिए। कैम्पस में ऐसी गतिविधियाँ होनी चाहिए जो छात्रों के शैक्षणिक, सामाजिक और व्यक्तिगत विकास में मदद करें। क्या देश के सभी कालेज ऐसा कर रहे हैं? इसके लिए इंटरनेट, ग्रुप एक्टिविटी, सांस्कृतिक कार्यक्रम और समुदायिक कार्यों को बढ़ावा देने की बात कही गई है। गाइडलाइंस के अनुसार हर संस्थान में स्टूडेंट सल्विसेटर्स बनाया जाना चाहिए। यह एक ऐसा सेटर होगा जहाँ छात्रों को काउंसिलिंग, मानसिक स्वास्थ्य से जुड़ी मदद और अन्य समस्याओं का समाधान मिल सकेगा। यहाँ प्रशिक्षित एक्सपर्ट्स मौजूद रहेंगे, जो छात्रों की बात सुनेंगे और उन्हें सही दिशा में मार्गदर्शन देंगे। इसके साथ ही आचरण की शारिरिक फिटनेस भी उत्तनी ही जरूरी है



जितनी पढ़ाई। इसलिए कालेजों को खेल के मैदान, जिम, योग और फिटनेस प्रोग्राम जैसी सुविधाएँ देनी होंगी, जहाँ छात्रों को नियमित रूप से फिजिकल एक्टिविटी करने के लिए प्रेरित किया जाएगा, ताकि वे शारीरिक और मानसिक रूप से फिट रह सकें। जरूरी है कि छात्रों के साथ बहुत ज्यादा सखी या सजा देने से बचा जाए। अगर किसी छात्र में व्यवहार से जुड़ी समस्या है, तो उसे सजा देने के बजाय काउंसिलिंग और सुधार के जरिए मदद की जाए। इससे छात्र खुद को सुरक्षित महसूस करेंगे और खुलकर अपनी बात रख पाएँगे। क्यों न कालेज और यूनिवर्सिटी

में मदक संस्थानों के साथ मिलकर काम करें। इससे जरूरत पड़ने पर छात्रों को बेहतर इलाज और मानसिक स्वास्थ्य सेवाएँ मिल सकेंगी, साथ ही परिवार के लिए ज्यादा से ज्यादा मेंटल हेल्थ एक्सपर्ट्स तैयार करने पर भी जोर दिया जाना चाहिए। कालेज छात्रों का गिरता मानसिक स्वास्थ्य एक गंभीर मुद्दा है, जिसमें लगभग 40 फीसदी छात्र अवसाद या चिंता से जूझ रहे हैं। शैक्षणिक दबाव, वित्तीय तनाव और भविष्य की अनिश्चितता प्रमुख कारण हैं। भारत के कालेज छात्र एक खाामोश मानसिक स्वास्थ्य संकट से गुजर रहे हैं। ऑन-प्रैक्टिस की एक निजी यूनिवर्सिटी के किए गए एक मल्टी-स्टेडी अध्ययन में यह चिंताजनक तस्वीर सामने आई थी। जुलाई से नवंबर 2023 के बीच किए गए इस सर्वे में देश के 8 टियर-1 शहरों दिल्ली, मुंबई, हैदराबाद, चेन्नई, बंगलुरु, पुणे, अहमदाबाद और कोलकाता के 1628 छात्रों (उम्र 18-29 वर्ष) को शामिल किया गया। सर्वे के अनुसार करीब 70 फीसदी छात्र परनाइट और 60 फीसदी से ज्यादा डिप्रेशन से जूझ रहे हैं।

भारत में विदेशी आक्रांताओं द्वारा भारतीय जाति व्यवस्था को षड्यंत्रपूर्वक छिन्न-भिन्न किया गया था

अनुसूचित जाति आरक्षण- जनजातीय बिना अधूरा है पर अच्छा है सुप्रीम कोर्ट का यह निर्णय

प्रवीण गुगनानी

भारतीय सर्वोच्च न्यायालय ने अत्यंत ही महत्वपूर्ण निर्णय दिया है। इस निर्णय से धर्मांतरण के अवैध व असामाजिक कृत्यों से देश को अंशतः मुक्ति मिलेगी। यद्यपि यह निर्णय अभी अधूरा है, जनजातीय समाज को भी इस निर्णय में सम्मिलित करने से ही देश आरक्षण के दुरुपयोग को रोक पायेगा, तथापि, इस निर्णय से भारत में आरक्षण कानून की आत्मा की अंशतः रक्षा तो होगी ही। यद्यपि यह निर्णय समय की मँग के अनुसार जनजातीय वर्ग को अपने प्रभाव में नहीं ले रहा है तथापि इस प्रकार के निर्णय की प्रतीक्षा देश का अनुसूचित जनजातीय समाज बड़ी आतुरता से कर रहा है। शीर्ष न्यायालय ने स्पष्ट किया है कि अनुसूचित जाति (SC) के अंतर्गत मिलने वाले आरक्षण का लाभ केवल उन्हीं को मिलेगा जो मूल रूप से उस सामाजिक-धार्मिक श्रेणी में बने रहते हैं। यदि कोई व्यक्ति धर्म परिवर्तन कर लेता है, तो वह स्वतः उस आरक्षण के अधिकार से वंचित हो सकता है, क्योंकि यह आरक्षण ऐतिहासिक सामाजिक वर्गीकरण के आधार पर दिया गया है। यह निर्णय केवल एक कानूनी व्याख्या नहीं, बल्कि सामाजिक समरसता को, सामाजिक संरचना को व हिंदुत्व के विरुद्ध चल रहे कुचक्र को रोकने वाला महत्वपूर्ण कदम है। स्वामी विवेकानंद ने धर्मांतरण की आगे की ओर को भीषण कर ही कहा था - "एक धर्मांतरण एक देशद्रोही को जन्म देता है।" भारत में विदेशी आक्रांताओं द्वारा भारतीय जाति व्यवस्था को षड्यंत्रपूर्वक छिन्न-भिन्न किया गया था। विदेशी आक्रमणकारी चाहे वे मुस्लिम ही या अंग्रेज अपने के आधारे पर मगभेद के बीज बोते रहे हैं और सत्ता की फसल काटते रहे हैं। विदेशी आक्रमणों के षड्यंत्रों के परिणाम स्वरूप ही पराधीन भारत में कई जातियों या अन्य सुविधाओं के माध्यम से प्रभावित कर धर्म परिवर्तन के लिए प्रेरित किया जाता है। मतांतरण के पीछे केवल और केवल दुराशय ही होता है। यह और कुछ नहीं अपितु भारत में जनसांख्यिकीय संतुलन को बिगाड़ कर अपनी

दुनिया से

देश

धर्म और जाति को लेकर आए 'सुप्रीम आदेश' के राजनीतिक-सामाजिक मायने

सुप्रीम

कोर्ट ने अपने एक अहम फैसले में यह स्पष्ट कर दिया है कि यदि कोई व्यक्ति हिंदू, सिख और बौद्ध धर्म से बाहर जाकर धर्म परिवर्तन करता है, तो उसे अनुसूचित जाति का संरक्षण नहीं माना जा सकता। दरअसल, ओंध प्रदेश के एक धर्मांतरित ईसाई पादरी से जुड़े मामले में आए इस नवीनतम फैसले के व्यापक राजनीतिक और सामाजिक मायने हैं। इससे हिन्दू समुदाय के दलितों और पिछड़ों को निशाना बनाकर धर्मांतरित करवाये जाने का पूरा खेल ही अब हतोत्साहित हो जाएगा। हालांकि, कांग्रेस व समाजवादी मूल की श्रेणीय पार्टियाँ यदि चाहे तो इस मुद्दे पर अपनी राजनीति भी शुरू कर सकती हैं कि जब हिन्दू, बौद्ध या सिख बनने तो उनका एससी/ओबीसी स्टेटस बरकरार रहेगा, लेकिन जै, ईसाई, मुसलमान, पारसी आदि बनने पर नहीं, यह कौन सा खिचड़ी न्यायिक दर्शन है। कहने का तात्पर्य यह कि ज्यूडिशियल एंटीबायोटिक पाँवर बढ़ाये बिना सम्बन्धित व्यक्ति या समूह का कल्याण नहीं होने वाला है। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने गत 23-24 मार्च 2026 को एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाया, जिसमें कहा गया कि हिंदू, सिख या बौद्ध धर्म के अलावा किसी अन्य धर्म (जैसे ईसाई, इस्लाम आदि) में परिवर्तन करने पर अनुसूचित जाति (एससी) का दर्जा सुरक्षित रहता है। इस आदेश से एससी/एसटी आरक्षण लाभ और अत्याचार निवारण अधिनियम का संरक्षण खत्म हो जाता है। दरअसल, यह फैसला ओंध प्रदेश हाईकोर्ट के मई 2025 के आदेश पर आधारित है, जहाँ एक ईसाई पादरी को एससी/एसटी एक्ट के तहत संरक्षण से वंचित किया गया। क्योंकि कोर्ट ने स्पष्ट किया कि संविधान के अनुसूचित जाति आदेश 1950 के अनुसार केवल निर्दिष्ट धर्मों के अनुयायी ही एससी/एसटी हो सकते हैं। ईसाई या इस्लाम अपनाने पर जातिगत पहचान और लाभ दोनों समाप्त हो जाते हैं। इस फैसले के अहम राजनीतिक मायने हैं। यह फैसला धर्मांतरण पर आधारित आरक्षण दावों को रोक सकता है, जो दक्षिणपंथी दलों के लिए समर्थन बढ़ाएगा। वहीं, अल्पसंख्यक आरक्षण बहस (जैसे दलित ईसाई/मुस्लिम) को प्रभावित कर चुनावी राजनीति में

हिंदू एकता पर जोर देगा। राज्य सरकारें ओबीसी/एससी सूचियों की समीक्षा के दबाव में आ सकती हैं। वहीं, इस फैसले के बाद धर्म परिवर्तन और आरक्षण से जुड़ी बहस जोर पकड़ सकती है। चूंकि सुप्रीम कोर्ट ने संविधान के आलोक में फैसला दिया है, लेकिन कुछ मसलें ऐसे होते हैं जहाँ कानून और जमीनी हकीकत आमने-सामने आ जाते हैं। भारत में जाति एक सच्चाई है, जिसे नहीं बदला जा सकता, लेकिन इससे जुड़ी बुराईयों को खत्म करने की तमाम कोशिश होनी चाहिए। जो राजनीतिक और न्यायिक अदृष्टिगत वश नहीं हो पा रही है और तरह तरह के संवैधानिक विवाद जन्म ले रहे हैं, जिससे राष्ट्रीय हितों को लगातार धक्का लग रहा है। जहाँ तक इस फैसले के सामाजिक प्रभाव की बात है तो धर्म परिवर्तन के बाद एससी/ओबीसी का लाभ न मिलने से सामाजिक न्याय की नीति मजबूत होगी, लेकिन धार्मिक रूपान्तरण रोकने या जातिगत अस्मिता पर बहस तेज हो सकती है। चूंकि दलित समुदायों में हिंदू/सिख/बौद्ध रहने का दावा बढ़ेगा, जबकि ईसाई/मुस्लिम समुदायों में असंतोष उत्पन्न हो सकता है। फिर भी कुलमिलाकर देखा जाए तो यह आरक्षण को ऐतिहासिक अन्याय सुधार तक सीमित रखने की दिशा में उठाया गया निर्णायक फैसला है। इस पर मौजूदा मोदी सरकार के वैचारिक असर से भी इनकार नहीं किया जा सकता है, क्योंकि यह सरकार परिवर्तन करने पर अनुसूचित जाति (एससी) का दर्जा सुरक्षित रहता है। इस आदेश से एससी/एसटी आरक्षण लाभ और अत्याचार निवारण अधिनियम का संरक्षण खत्म हो जाता है। दरअसल, यह फैसला ओंध प्रदेश हाईकोर्ट के मई 2025 के आदेश पर आधारित है, जहाँ एक ईसाई पादरी को एससी/एसटी एक्ट के तहत संरक्षण से वंचित किया गया। क्योंकि कोर्ट ने स्पष्ट किया कि संविधान के अनुसूचित जाति आदेश 1950 के अनुसार केवल निर्दिष्ट धर्मों के अनुयायी ही एससी/एसटी हो सकते हैं। ईसाई या इस्लाम अपनाने पर जातिगत पहचान और लाभ दोनों समाप्त हो जाते हैं। इस फैसले के अहम राजनीतिक मायने हैं। यह फैसला धर्मांतरण पर आधारित आरक्षण दावों को रोक सकता है, जो दक्षिणपंथी दलों के लिए समर्थन बढ़ाएगा। वहीं, अल्पसंख्यक आरक्षण बहस (जैसे दलित ईसाई/मुस्लिम) को प्रभावित कर चुनावी राजनीति में

ही एससी श्रेणी में आ सकते हैं। धर्म परिवर्तन और जाति से जुड़ी यह बहस बहुत पुरानी है। इसके दो पहलू हैं। एक, जिन धर्मों में जाति व्यवस्था नहीं है, उन्हें अपनाकर फिर जाति से जुड़े लाभ कैसे लिए जा सकते हैं। पिछले साल दिसंबर में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इस सरकार को यह सुनिश्चित करने का आदेश दिया था कि जिन्होंने ईसाई धर्म अपना लिया है, उन्होंने अनुसूचित जाति से जुड़े लाभ छोड़ दिए हों। तब हाईकोर्ट ने कहा था कि धर्म परिवर्तन के बाद भी अनुसूचित जाति समुदाय को मिलने वाले फायदे लेते रहना संविधान के साथ धोखा है। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के पास इस तरह की कई शिकायतें हैं और उसने पिछले साल देशभर में जांच भी शुरू की थी। कुलमिलाकर उद्देश्य यह है कि संविधान के तहत मिले अधिकार का दुरुपयोग न होने पाए। क्योंकि जाति और धर्म का दुरुपयोग होने की चिंता शुरू से ही न्यायिक विमर्श का मुद्दा बन ही हुई है। लिहाजा ब्रेक के बाद न्यायिक समितें रहते हैं।

इंद्रा साहनी केस (1992) से इस फैसले का सम्बन्ध इंद्रा साहनी केस (1992) मुख्य रूप से ओबीसी आरक्षण पर केंद्रित था, लेकिन हालिया सुप्रीम कोर्ट फैसले (धर्म परिवर्तन पर SC दल संर्मापित) से इसका अप्रत्यक्ष संबंध है। दोनों आरक्षण को जाति-आधारित ऐतिहासिक अन्याय सुधार तक सीमित रखने के सिद्धांत साझा करते हैं। इंद्रा साहनी का सार: इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने ओबीसी को 27% आरक्षण माना किया, लेकिन 50% कुल सीमा तय की और स्पष्ट किया कि आरक्षण का आधार धर्म या जाति अकेला नहीं हो सकता। क्रोमी लेयर बहिष्कार और पिछड़ापन के सामाजिक-शैक्षिक मापदंड निर्धारित किए गए। हालिया फैसले से संबंध 2026 के एससी/एसटी फैसले में संविधान के अनुसूचित जाति आदेश 1950 का हवाला दिया गया, जो इंद्रा साहनी के सिद्धांतों से मेल खाता है कि आरक्षण धर्म पर आधारित नहीं। ओबीसी मामलों में (जैसे मुस्लिम आरक्षण रद्द), कोर्ट ने इंद्रा साहनी का जिक्र कर धर्म को आधार बनाने से रोक, जो एससी केस की भावना से जुड़ता है। हालांकि, सीधा उल्लेख नहीं मिला, लेकिन सामान्य आरक्षण दर्शन समान है, जिसका सर्वकालिक महत्व जगजाहिर है।

बड़े

दांचे के बड़े इतिहास, अब इन्मीनान से देने पड़ेंगे। विधानसभा के बजट सत्र में विधायक प्रकाश राणा ने इमारती की बेकरी का हिस्सा लगाते हुए जो कहा है, उसे सुनना होगा। उन्होंने जिक्र किया कि किस तरह आती-जाती सरकारों की पाजेब पहन कर सरकारी धन को बेकार किया जाता है। इमारतें सत्ता की निशानियाँ नहीं, राज्य की मिलकीयत में इजाफा होना चाहिए, लेकिन होता यही है कि बदलती सरकारें, राज्य की प्राथमिकताओं में पिछली परियोजनाओं और भवनों के निर्माण की कार्रवाई रोक देती हैं। कुछ इसी तरह की खोज खबर सत्ता और विपक्ष के बीच भी हो रही है, यहाँ कहा यह जा रहा है कि पिछली सरकार ने फिजूलखर्ची में हजार के करीब धन खड़े कर दिए। हमारी दीर्घकालीन योजनाएँ आखिर हैं क्या और द्वांचगत उपलब्धियों का मूल्यांकन होता कैसे। व्यवस्था के परे विंगड रहे हैं। पीठियों में निराशा, फिर भी शिक्षा के दरबार खड़े किए जा रहे हैं। इमारतें सदन की बहस में गुस्सा है, पक्ष-विपक्ष हैं, लेकिन प्रदेश की हकीकत पर ताज्जुब नहीं है। एक लाख करोड़ के ऋण के नीचे कितनी जमीन और ऊपर कितना आसमान बचा है। इस पर चर्चा न होकर सभी दल एक-दूसरे की कमीज पहन रहे हैं। कमीजें तो पुलिस सरकारी की पाजेब पहनकर सरकारी धन को बेकार किया जाता है। इमारतें सत्ता की निशानियाँ नहीं, राज्य की मिलकीयत में इजाफा होना चाहिए, लेकिन होता यही है कि बदलती सरकारें, राज्य की प्राथमिकताओं में पिछली परियोजनाओं और भवनों के निर्माण की कार्रवाई रोक देती हैं। कुछ इसी तरह की खोज खबर सत्ता और विपक्ष के बीच भी हो रही है, जहाँ कहा यह जा रहा है कि पिछली भवन खड़े कर दिए। हमारी दीर्घकालीन योजनाएँ आखिर हैं क्या और द्वांचगत उपलब्धियों का मूल्यांकन होता कैसे। व्यवस्था के परे विंगड रहे हैं। पीठियों में निराशा, फिर भी शिक्षा के दरबार खड़े किए जा रहे हैं। इमारतें सदन की बहस में गुस्सा है, पक्ष-विपक्ष हैं, लेकिन प्रदेश की हकीकत पर ताज्जुब नहीं है। एक लाख करोड़ के ऋण के नीचे कितनी जमीन और ऊपर कितना आसमान बचा है। इस पर चर्चा न होकर सभी दल एक-दूसरे की कमीज पहन रहे हैं। कमीजें तो पुलिस सरकारी की पाजेब पहनकर सरकारी धन को बेकार किया जाता है। इमारतें सत्ता की निशानियाँ नहीं, राज्य की मिलकीयत में इजाफा होना चाहिए, लेकिन होता यही है कि बदलती सरकारें, राज्य की प्राथमिकताओं में पिछली परियोजनाओं और भवनों के निर्माण की कार्रवाई रोक देती हैं। कुछ इसी तरह की खोज खबर सत्ता और विपक्ष के बीच भी हो रही है, जहाँ कहा यह जा रहा है कि पिछली भवन खड़े कर दिए। हमारी दीर्घकालीन योजनाएँ आखिर हैं क्या और द्वांचगत उपलब्धियों का मूल्यांकन होता कैसे। व्यवस्था के परे विंगड रहे हैं। पीठियों में निराशा, फिर भी शिक्षा के दरबार खड़े किए जा रहे हैं। इमारतें सदन की बहस में गुस्सा है, पक्ष-विपक्ष हैं, लेकिन प्रदेश की हकीकत पर ताज्जुब नहीं है। एक लाख करोड़ के ऋण के नीचे कितनी जमीन और ऊपर कितना आसमान बचा है। इस पर चर्चा न होकर सभी दल एक-दूसरे की कमीज पहन रहे हैं। कमीजें तो पुलिस सरकारी की पाजेब पहनकर सरकारी धन को बेकार किया जाता है। इमारतें सत्ता की निशानियाँ नहीं, राज्य की मिलकीयत में इजाफा होना चाहिए, लेकिन होता यही है कि बदलती सरकारें, राज्य की प्राथमिकताओं में पिछली परियोजनाओं और भवनों के निर्माण की कार्रवाई रोक देती हैं। कुछ इसी तरह की खोज खबर सत्ता और विपक्ष के बीच भी हो रही है, जहाँ कहा यह जा रहा है कि पिछली भवन खड़े कर दिए। हमारी दीर्घकालीन योजनाएँ आखिर हैं क्या और द्वांचगत उपलब्धियों का मूल्यांकन होता कैसे। व्यवस्था के परे विंगड रहे हैं। पीठियों में निराशा, फिर भी शिक्षा के दरबार खड़े किए जा रहे हैं। इमारतें सदन की बहस में गुस्सा है, पक्ष-विपक्ष हैं, लेकिन प्रदेश की हकीकत पर ताज्जुब नहीं है। एक लाख करोड़ के ऋण के नीचे कितनी जमीन और ऊपर कितना आसमान बचा है। इस पर चर्चा न होकर सभी दल एक-दूसरे की कमीज पहन रहे हैं। कमीजें तो पुलिस सरकारी की पाजेब पहनकर सरकारी धन को बेकार किया जाता है। इमारतें सत्ता की निशानियाँ नहीं, राज्य की मिलकीयत में इजाफा होना चाहिए, लेकिन होता यही है कि बदलती सरकारें, राज्य की प्राथमिकताओं में पिछली परियोजनाओं और भवनों के निर्माण की कार्रवाई रोक देती हैं। कुछ इसी तरह की खोज खबर सत्ता और विपक्ष के बीच भी हो रही है, जहाँ कहा यह जा रहा है कि पिछली भवन खड़े कर दिए। हमारी दीर्घकालीन योजनाएँ आखिर हैं क्या और द्वांचगत उपलब्धियों का मूल्यांकन होता कैसे। व्यवस्था के परे विंगड रहे हैं। पीठियों में निराशा, फिर भी शिक्षा के दरबार खड़े किए जा रहे हैं। इमारतें सदन की बहस में गुस्सा है, पक्ष-विपक्ष हैं, लेकिन प्रदेश की हकीकत पर ताज्जुब नहीं है। एक लाख करोड़ के ऋण के नीचे कितनी जमीन और ऊपर कितना आसमान बचा है। इस पर चर्चा न होकर सभी दल एक-दूसरे की कमीज पहन रहे हैं। कमीजें तो पुलिस सरकारी की पाजेब पहनकर सरकारी धन को बेकार किया जाता है। इमारतें सत्ता की निशानियाँ नहीं, राज्य की मिलकीयत में इजाफा होना चाहिए, लेकिन होता यही है कि बदलती सरकारें, राज्य की प्राथमिकताओं में पिछली परियोजनाओं और भवनों के निर्माण की कार्रवाई रोक देती हैं। कुछ इसी तरह की खोज खबर सत्ता और विपक्ष के बीच भी हो रही है, जहाँ कहा यह जा रहा है कि पिछली भवन खड़े कर दिए। हमारी दीर्घकालीन योजनाएँ आखिर हैं क्या और द्वांचगत उपलब्धियों का मूल्यांकन होता कैसे। व्यवस्था के परे विंगड रहे हैं। पीठियों में निराशा, फिर भी शिक्षा के दरबार खड़े किए जा रहे हैं। इमारतें सदन की बहस में गुस्सा है, पक्ष-विपक्ष हैं, लेकिन प्रदेश की हकीकत पर ताज्जुब नहीं है। एक लाख करोड़ के ऋण के नीचे कितनी जमीन और ऊपर कितना आसमान बचा है। इस पर चर्चा न होकर सभी दल एक-दूसरे की कमीज पहन रहे हैं। कमीजें तो पुलिस सरकारी की पाजेब पहनकर सरकारी धन को बेकार किया जाता है। इमारतें सत्ता की निशानियाँ नहीं, राज्य की मिलकीयत में इजाफा होना चाहिए, लेकिन होता यही है कि बदलती सरकारें, राज्य की प्राथमिकताओं में पिछली परियोजनाओं और भवनों के निर्माण की कार्रवाई रोक देती हैं। कुछ इसी तरह की खोज खबर सत्ता और विपक्ष के बीच भी हो रही है, जहाँ कहा यह जा रहा है कि पिछली भवन खड़े कर दिए। हमारी दीर्घकालीन योजनाएँ आखिर हैं क्या और द्वांचगत उपलब्धियों का मूल्यांकन होता कैसे। व्यवस्था के परे विंगड रहे हैं। पीठियों में निराशा, फिर भी शिक्षा के दरबार खड़े किए जा रहे हैं। इमारतें सदन की बहस में गुस्सा है, पक्ष-विपक्ष हैं, लेकिन प्रदेश की हकीकत पर ताज्जुब नहीं है। एक लाख करोड़ के ऋण के नीचे कितनी जमीन और ऊपर कितना आसमान बचा है। इस पर चर्चा न होकर सभी दल एक-दूसरे की कमीज पहन रहे हैं। कमीजें तो पुलिस सरकारी की पाजेब पहनकर सरकारी धन को बेकार किया जाता है। इमारतें सत्ता की निशानियाँ नहीं, राज्य की मिलकीयत में इजाफा होना चाहिए, लेकिन होता यही है कि बदलती सरकारें, राज्य की प्राथमिकताओं में पिछली परियोजनाओं और भवनों के निर्माण की कार्रवाई रोक देती हैं। कुछ इसी तरह की खोज खबर सत्ता और विपक्ष के बीच भी हो रही है, जहाँ कहा यह जा रहा है कि पिछली भवन खड़े कर दिए। हमारी दीर्घकालीन योजनाएँ आखिर हैं क्या और द्वांचगत उपलब्धियों का मूल्यांकन होता कैसे। व्यवस्था के परे विंगड रहे हैं। पीठियों में निराशा, फिर भी शिक्षा के दरबार खड़े किए जा रहे हैं। इमारतें सदन की बहस में गुस्सा है, पक्ष-विपक्ष हैं, लेकिन प्रदेश की हकीकत पर ताज्जुब नहीं है। एक लाख करोड़ के ऋण के नीचे कितनी जमीन और ऊपर कितना आसमान बचा है। इस पर चर्चा न होकर सभी दल एक-दूसरे की कमीज पहन रहे हैं। कमीजें तो पुलिस सरकारी की पाजेब पहनकर सरकारी धन को बेकार किया जाता है। इमारतें सत्ता की निशानियाँ नहीं, राज्य की मिलकीयत में इजाफा होना चाहिए, लेकिन होता यही है कि बदलती सरकारें, राज्य की प्राथमिकताओं में पिछली परियोजनाओं और भवनों के निर्माण की कार्रवाई रोक देती हैं। कुछ इसी तरह की खोज खबर सत्ता और विपक्ष के बीच भी हो रही है, जहाँ कहा यह जा रहा है कि पिछली भवन खड़े कर दिए। हमारी दीर्घकालीन योजनाएँ आखिर हैं क्या और द्वांचगत उपलब्धियों का मूल्यांकन होता कैसे। व्यवस्था के परे विंगड रहे हैं। पीठियों में निराशा, फिर भी शिक्षा के दरबार खड़े किए जा रहे हैं। इमारतें सदन की बहस में गुस्सा है, पक्ष-विपक्ष हैं, लेकिन प्रदेश की हकीकत पर ताज्जुब नहीं है। एक लाख करोड़ के ऋण के नीचे कितनी जमीन और ऊपर कितना आसमान बचा है। इस पर चर्चा न होकर सभी दल एक-दूसरे की कमीज पहन रहे हैं। कमीजें तो पुलिस सरकारी की पाजेब पहनकर सरकारी धन को बेकार किया जाता है। इमारतें सत्ता की निशानियाँ नहीं, राज्य की मिलकीयत में इजाफा होना चाहिए, लेकिन होता यही है कि बदलती सरकारें, राज्य की प्राथमिकताओं में पिछली परियोजनाओं और भवनों के निर्माण की कार्रवाई रोक देती हैं। कुछ इसी तरह की खोज खबर सत्ता और विपक्ष के बीच भी हो रही है, जहाँ कहा यह जा रहा है कि पिछली भवन खड़े कर दिए। हमारी दीर्घकालीन योजनाएँ आखिर हैं क्या और द्वांचगत उपलब्धियों का मूल्यांकन होता कैसे। व्यवस्था के परे विंगड रहे हैं। पीठियों में निराशा, फिर भी शिक्षा के दरबार खड़े किए जा रहे हैं। इमारतें सदन की बहस में गुस्सा है, पक्ष-विपक्ष हैं, लेकिन प्रदेश की हकीकत पर ताज्जुब नहीं है। एक लाख करोड़ के ऋण के नीचे कितनी जमीन और ऊपर कितना आसमान बचा है। इस पर चर्चा न होकर सभी दल एक-दूसरे की कमीज पहन रहे हैं। कमीजें तो पुलिस सरकारी की पाजेब पहनकर सरकारी धन को बेकार किया जाता है। इमारतें सत्ता की निशानियाँ नहीं, राज्य की मिलकीयत में इजाफा होना चाहिए, लेकिन होता यही है कि बदलती सरकारें, राज्य की प्राथमिकताओं में पिछली परियोजनाओं और भवनों के निर्माण की कार्रवाई रोक देती हैं। कुछ इसी तरह की खोज खबर सत्ता और विपक्ष के बीच भी हो रही है, जहाँ कहा यह जा रहा है कि पिछली भवन खड़े कर दिए। हमारी दीर्घकालीन योजनाएँ आखिर हैं क्या और द्वांचगत उपलब्धियों का मूल्यांकन होता कैसे। व्यवस्था के परे विंगड रहे हैं। पीठियों में निराशा, फिर भी शिक्षा के दरबार खड़े किए जा रहे हैं। इमारतें सदन की बहस में गुस्सा है, पक्ष-विपक्ष हैं, लेकिन प्रदेश की हकीकत पर ताज्जुब नहीं है। एक लाख करोड़ के ऋण के नीचे कितनी जमीन और ऊपर कितना आसमान बचा है। इस पर चर्चा न होकर सभी दल एक-दूसरे की कमीज पहन रहे हैं। कमीजें तो पुलिस सरकारी की पाजेब पहनकर सरकारी धन को बेकार किया जाता है। इमारतें सत्ता की निशानियाँ नहीं, राज्य की मिलकीयत में इजाफा होना चाहिए, लेकिन होता यही है कि बदलती सरकारें, राज्य की प्राथमिकताओं में पिछली परियोजनाओं और भवनों के निर्माण की कार्रवाई रोक देती हैं। कुछ इसी तरह की खोज खबर सत्ता और विपक्ष के बीच भी हो रही है, जहाँ कहा यह जा रहा है कि पिछली भवन खड़े कर दिए। हमारी दीर्घकालीन योजनाएँ आखिर हैं क्या और द्वांचगत उपलब्धियों का मूल्यांकन होता कैसे। व्यवस्था के परे विंगड रहे हैं। पीठियों में निराशा, फिर भी शिक्षा के दरबार खड़े किए जा रहे हैं। इमारतें सदन की बहस में गुस्सा है, पक्ष-विपक्ष हैं, लेकिन प्रदेश की हकीकत पर ताज्जुब नहीं है। एक लाख करोड़ के ऋण के नीचे कितनी जमीन और ऊपर कितना आसमान बचा है। इस पर चर्चा न होकर सभी दल एक-दूसरे की कमीज पहन रहे हैं। कमीजें तो पुलिस सरकारी की पाजेब पहनकर सरकारी धन को बेकार किया जाता है। इमारतें सत्ता की निशानियाँ नहीं, राज्य की मिलकीयत में इजाफा होना चाहिए, लेकिन होता यही है कि बदलती सरकारें, राज्य की प्राथमिकताओं में पिछली परियोजनाओं और भवनों के निर्माण की कार्रवाई रोक देती हैं। कुछ इसी तरह की खोज खबर सत्ता और विपक्ष के बीच भी हो रही है, जहाँ कहा यह जा रहा है कि पिछली भवन खड़े कर दिए। हमारी दीर्घकालीन योजनाएँ आखिर हैं क्या और द्वांचगत उपलब्धियों का मूल्यांकन होता कैसे। व्यवस्था के परे विंगड रहे हैं। पीठियों में निराशा, फिर भी शिक्षा के दरबार खड़े किए जा रहे हैं। इमारतें सदन की बहस में गुस्सा है, पक्ष-विपक्ष हैं, लेकिन प्रदेश की हकीकत पर ताज्जुब नहीं है। एक लाख करोड़ के ऋण के नीचे कितनी जमीन और ऊपर कितना आसमान बचा है। इस पर चर्चा न होकर सभी दल एक-दूसरे की कमीज पहन रहे हैं। कमीजें तो पुलिस सरकारी की पाजेब पहनकर सरकारी धन को बेकार किया जाता है। इमारतें सत्ता की निशानियाँ नहीं, राज्य की मिलकीयत में इजाफा होना चाहिए, लेकिन होता यही है कि बदलती सरकारें, राज्य की प्राथमिकताओं में पिछली परियोजनाओं और भवनों के निर्माण की कार्रवाई रोक देती हैं। कुछ इसी तरह की खोज खबर सत्ता और विपक्ष के बीच भी हो रही है, जहाँ कहा यह जा रहा है कि पिछली भवन खड़े कर दिए। हमारी दीर्घकालीन योजनाएँ आखिर हैं क्या और द्वांचगत उपलब्धियों का मूल्यांकन होता कैसे। व्यवस्था के परे विंगड रहे हैं। पीठियों में निराशा, फिर भी शिक्षा के दरबार खड़े किए जा रहे हैं। इमारतें सदन की बहस में गुस्सा है, पक्ष-विपक्ष हैं, लेकिन प्रदेश की हकीकत पर ताज्जुब नहीं है। एक लाख करोड़ के ऋण के नीचे कितनी जमीन और ऊपर कितना आसमान बचा है। इस पर चर्चा न होकर सभी दल एक-दूसरे की कमीज पहन रहे हैं। कमीजें तो पुलिस सरकारी की पाजेब पहनकर सरकारी धन को बेकार किया जाता है। इमारतें सत्ता की निशानियाँ नहीं, राज्य की मिलकीयत में इजाफा होना चाहिए, लेकिन होता यही है कि बदलती सरकारें, राज्य की प्राथमिकताओं में पिछली परियोजनाओं और भवनों के निर्माण की कार्रवाई रोक देती हैं। कुछ इसी तरह की खोज खबर सत्ता और विपक्ष के बीच भी हो रही है, जहाँ कहा यह जा रहा है कि पिछली भवन खड़े कर दिए। हमारी दीर्घकालीन योजनाएँ आखिर हैं क्या और द्वांचगत उपलब्धियों का मूल्यांकन होता कैसे। व्यवस्था के परे विंगड रहे हैं। पीठियों में निराशा, फिर भी शिक्षा के दरबार खड़े किए जा रहे हैं। इमारतें सदन की बहस में गुस्सा है, पक्ष-विपक्ष हैं, लेकिन प्रदेश की हकीकत पर ताज्जुब नहीं है। एक लाख करोड़ के ऋण के नीचे कितनी जमीन और ऊपर कितना आसमान बचा है। इस पर चर्चा न होकर सभी दल एक-दूसरे की कमीज पहन रहे हैं। कमीजें तो पुलिस सरकारी की पाजेब पहनकर सरकारी धन को बेकार किया जाता है। इमारतें सत्ता की निशानियाँ नहीं, राज्य की मिलकीयत में इजाफा होना चाहिए, लेकिन होता यही है कि बदलती सरकारें, राज्य की प्राथमिकताओं में पिछली परियोजनाओं और भवनों के निर्माण की कार्रवाई रोक देती हैं। कुछ इसी तरह की खोज खबर सत्ता और विपक्ष के बीच भी हो रही है, जहाँ कहा यह जा रहा है कि पिछली भवन खड़े कर दिए। हमारी दीर्घकालीन योजनाएँ आखिर हैं क्या और द्वांचगत उपलब्धियों का मूल्यांकन होता कैसे। व्यवस्था के परे विंगड रहे हैं। पीठियों में निराशा, फिर भी शिक्षा के दरबार खड़े किए जा रहे हैं। इमारतें सदन की बहस में गुस्सा है, पक्ष-विपक्ष हैं, लेकिन प्रदेश की हकीकत पर ताज्जुब नहीं है। एक लाख करोड़ के ऋण के नीचे कितनी जमीन और ऊपर कित

सरकार हर परिवार को पक्का घर उपलब्ध करवाने के लिए प्रतिबद्ध : पटेल

जोधपुर (हिस)। मुख्यमंत्री जन आवास योजना के तहत गृह गौरव खुशियों की चाबी कार्यक्रम बुधवार को जोधपुर विकास प्राधिकरण के प्रांगण में संसदीय कार्य, विधि एवं विधिक कार्य मंत्री जोगाराम पटेल के मुख्य आतिथ्य में आयोजित हुआ। कार्यक्रम में 38 आवंटियों को आवास की चाबी सौंपी गई। इस दौरान पटेल ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा के विजन के अनुरूप डबल इंजन की सरकार प्रत्येक छत विहीन परिवार को पक्का घर उपलब्ध करवाने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा राजस्थान में प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) 2.0 के तहत नवीन 48 हजार आवास स्वीकृत किए गए हैं। वहीं प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के अंतर्गत दो वर्षों में 7.16 लाख आवास स्वीकृत किए गए हैं। विधि मंत्री ने कहा अपना घर होना हर व्यक्ति का सबसे बड़ा सपना होता है। मुख्यमंत्री जन आवास योजना के माध्यम से हम न केवल ईट-पत्थर का मकान दे रहे हैं, बल्कि सम्मानजनक जीवन जीने का आधार प्रदान कर रहे हैं। उन्होंने कहा ग्राम बड़ली में निर्मित यह प्रोजेक्ट आधुनिक शहरी सुविधाओं से युक्त है, जहां निवासियों को गुणवत्तापूर्ण बुनियादी ढांचा उपलब्ध कराया गया है। जोधपुर विकास प्राधिकरण द्वारा विकसित इस योजना में सड़क, बिजली, पानी और सार्वजनिक पार्क जैसी समस्त मूलभूत सुविधाओं का विशेष ध्यान रखा गया है। उन्होंने आवंटियों को बधाई देते हुए उनके सुखद भविष्य की मंगलकामना की। मुख्यमंत्री जन आवास योजना के तहत ग्राम बड़ली के खसरा संख्या 88 में आर्थिक दृष्टि से कमजोर आर्य वर्ग के लिए 768 एवं अल्प आय वर्ग के लिए 448 कुल 1216 आवंटियों के लिए प्लेट निर्माण का कार्य 2018 में आरम्भ किया गया। अभी तक 320 आवासों का निर्माण हो चुका है। कार्यक्रम में जोधपुर विकास प्राधिकरण के आयुक्त उस्ताह चौधरी, सचिव चंचल वर्मा, उपायुक्त वीरेंद्र सिंह भाटी निदेशक अभियांत्रिकी महेंद्र सिंह पंवार, पूर्व प्रधान तुलसीराम मेघवाल सहित जनप्रतिनिधि एवं अधिकारी उपस्थित रहे।

पंजाब पुलिस ने दुष्कर्म व अन्य आरोपों से घिरे आपा विधायक को मध्य प्रदेश से गिरफ्तार किया

चंडीगढ़ (हिस)। पंजाब पुलिस ने दुष्कर्म व अन्य आरोपों से घिरे सनौर हलके से आम आदमी पार्टी (आआपा) विधायक हर्षमोत सिंह पठानमाजरा को मध्य प्रदेश में गिरफ्तार कर लिया है। पठानमाजरा कई माह से फरार थे। एक सितंबर 2025 को पंजाब के पटियाला के सिविल लाइंस थाने में एक महिला द्वारा बलात्कार, धोखाधड़ी व अन्य आरोपों के तहत हर्षमोत सिंह पठानमाजरा के खिलाफ मामला दर्ज कवाया गया था। महिला ने आरोप लगाया था कि 2013-2014 से लेकर 2024 तक (विशेष रूप से 12 फरवरी 2014 से 12 जून 2024 तक) पठानमाजरा ने शादी का झंसा देकर, खुद को तलाक़शुदा बताकर शारीरिक संबंध बनाए। 2021 में लुधियाना के एक गुददारे में उनकी शादी भी हुई, लेकिन पठानमाजरा पहले से शादीशुदा थे। इसके बाद 2 सितंबर को हरियाणा के करनाल में पठानमाजरा को गिरफ्तार किया गया।

2027 में बदलाव का मन बना चुकी है जनता : शिवपाल सिंह यादव



प्रयागराज (हिस)। भाजपा पर निशाना साधते हुए समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव एवं पूर्व कैबिनेट मंत्री शिवपाल सिंह यादव ने बुधवार को प्रयागराज में कार्यकर्ताओं से कहा कि वर्ष 2027 में उत्तर प्रदेश में बदलाव के लिए जनता मन बना चुकी है। भाजपा सरकार में किसान बदलाव हैं। नौजवान बेरोजगार हैं और महिलाएं असुरक्षा की भावना में जी रही हैं। उन्होंने कहा कि अल्पसंख्यक समाज में भी भय का माहौल है। समय-समय पर भाजपा नेताओं के विभेदकारी बयानों से समाज में भाईचारे की बजाए कटुता का

अनुसूचित जाति पर शीर्ष अदालत का फैसला

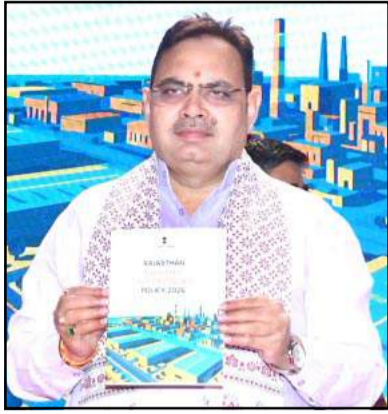
स्वागतयोग्य : लखेंद्र पासवान पटना (हिस)। उच्चतम न्यायालय के केवल हिंदूओं, सिखों और बौद्धों को ही अनुसूचित जाति के रूप में मान्यता देने के फैसले का बिहार के अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण मंत्री सह एससी मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष लखेंद्र पासवान ने स्वागत किया है। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया है कि हिंदू, बौद्ध या सिख धर्म के अलावा किसी अन्य धर्म को अपनाने वाले व्यक्ति को अनुसूचित जाति (एससी) का सदस्य नहीं माना जा सकता है। उन्होंने कहा कि शीर्ष कोर्ट ने कहा कि ईसाई या मुस्लिम धर्म अपनाने पर व्यक्ति का अनुसूचित जाति का दर्जा खत्म हो जाता है। उन्होंने कहा कि इस फैसले से ऐसे लोगों पर अंकुश लगेगा जो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति (एसटी) और अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) समुदाय के लोग जो इस्लाम या ईसाई धर्म में परिवर्तित होने के बाद भी आरक्षण का लाभ उठाते रहते हैं।

हरियाणा में नहीं बढ़ेगी बिजली दरें, एचईआरसी ने यथावत रखा टैरिफ

हिसार (हिस)। हरियाणा के लाखों बिजली उपभोक्ताओं के लिए राहत भरी खबर है। हरियाणा विद्युत विनियामक आयोग (एचईआरसी) ने वित्त वर्ष 2026-27 के लिए बिजली दरों को यथावत रखने का निर्णय लिया है। इस फैसले से प्रदेश के 83 हजार 79 हजार 739 उपभोक्ताओं को सीधा लाभ मिलेगा। नया टैरिफ एक अप्रैल 2026 से लागू होगा। आयोग ने यह निर्णय उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम (यूएचबीवीएनएल) और दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम (डीएचबीवीएनएल) द्वारा दायर वार्षिक राजस्व आवश्यक्ता (एआरआर) याचिकाओं पर विस्तृत सुनवाई के बाद लिया उल्लेखनीय है कि दोनों डिस्कॉम्स ने लगभग 4484.71 करोड़ रुपये के राजस्व घाटे का अनुमान प्रस्तुत किया था, इसके बावजूद आयोग ने उपभोक्ताओं पर किसी भी प्रकार का अतिरिक्त बोझ नहीं डालने का फैसला किया। जनसुनवाई के दौरान सभी श्रेणियों के उपभोक्ताओं ने एक स्वर में बिजली दरों में किसी प्रकार की वृद्धि नहीं करने की बात कही। इसी के मद्देनजर आयोग ने राजस्व संग्रह में सुधार, बकाया प्रबंधन, बिजली खरीद के अनुकूलन तथा हानियों में कमी पर जोर देते हुए एआरआर को राजस्व-न्यूट्रल रखा है। एचईआरसी के अध्यक्ष नंदलाल लाल शर्मा, सदस्य मुकेश गर्ग व शिव कुमार ने

औद्योगिक पार्क प्रोत्साहन नीति-2026 राजस्थान बनेगा निवेश का हब, बढ़ेगा रोजगार

जयपुर (हिस)। राजस्थान में औद्योगिक विकास को नई गति देने के लिए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राज्य सरकार ने औद्योगिक पार्क प्रोत्साहन नीति-2026 लागू की है। इस नीति का उद्देश्य प्रदेश में विश्वस्तरीय औद्योगिक पार्क विकसित कर बेहतर निवेश वातावरण तैयार करना और रोजगार के अवसर बढ़ाना है। सरकार द्वारा अब तक 34 से अधिक औद्योगिक नीतियां लागू की जा चुकी हैं, जिससे ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, अनुमोदन प्रक्रिया के सरलीकरण और पारदर्शी व्यवस्था के माध्यम से प्रदेश का औद्योगिक परिदृश्य तेजी से बदल रहा है। नई नीति के तहत निजी क्षेत्र में औद्योगिक पार्कों का विकास चार अलग-अलग मॉडल ए, बी, सी और ड पर किया जाएगा। मॉडल-ए में रीको द्वारा आर्बिट्ररी भूमि पर निजी डेवलपर द्वारा विकास, मॉडल-बी में 80 प्रतिशत भूमि डेवलपर और 20 प्रतिशत रीको द्वारा, मॉडल-सी में संपूर्ण भूमि डेवलपर द्वारा उपलब्ध और मॉडल-डी में पीपीपी (पब्लिक-प्राइवेट पार्टनरशिप) मॉडल होगा। इन पार्कों के लिए न्यूनतम 50 एकड़ क्षेत्र और कम से कम 10 औद्योगिक इकाइयों का स्थापना अनिवार्य होगी। नीति में



पर्यावरण संरक्षण को प्राथमिकता दी गई है। कॉमन एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट (सीईटीपी) पर होने वाले खर्च का 50 प्रतिशत (अधिकतम 12.5 करोड़ रुपये प्रति पार्क) तक प्रतिपूर्ति का प्रावधान किया गया है। साथ ही पहले 10 औद्योगिक पार्क डेवलपमेंट को 20 प्रतिशत पूंजीगत अनुदान भी दिया जाएगा, जिसकी अधिकतम सीमा 40 करोड़ रुपये तक

निर्धारित की गई है। औद्योगिक पार्कों तक सड़क, जल और बिजली जैसी मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। संपर्क मार्गों के निर्माण में 60 प्रतिशत खर्च राज्य सरकार और 40 प्रतिशत डेवलपर द्वारा वहन किया जाएगा, जिसमें सरकार का अधिकतम योगदान तीन करोड़ रुपये तक होगा। नीति के तहत राज निवेश पोर्टल के माध्यम से सिंगल विंडो क्लियरेंस की सुविधा दी जाएगी, जिससे आवेदनों का समयबद्ध निस्तारण संभव होगा। इसके अलावा कैप्टिव नवीकरणीय ऊर्जा पर 7 वर्षों तक 100% विद्युत शुल्क छूट, स्ट्याम्प शुल्क व कन्वर्जन शुल्क में 25% छूट और प्लग-एंड-प्ले ऑफिस कॉम्प्लेक्स के लिए अतिरिक्त प्रोत्साहन भी दिए जाएंगे। यह नीति नरेंद्र मोदी के *मेक इन इंडिया* और *आत्मनिर्भर भारत* विजन के अनुरूप है। इसके माध्यम से प्रदेश में निवेश को बढ़ावा मिलेगा, औद्योगिक गतिविधियां तेज होंगी और बड़े स्तर पर रोजगार सृजन के अवसर पैदा होंगे। राज्य सरकार का मानना है कि इस नीति से राजस्थान देश-विदेश में एक भरोसेमंद और भविष्य के लिए तैयार औद्योगिक गंतव्य (इंडस्ट्रियल डेस्टिनेशन) के रूप में स्थापित होगा।

ईंधन-गैस को लेकर विपक्ष फैला रहा भ्रम : राठौड़



जयपुर (हिस)। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने ईंधन और गैस की उपलब्धता को लेकर विपक्ष पर भ्रम फैलाने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि सरकार ने कहीं भी ईंधन और गैस की कमी की बात नहीं कही है और वैश्विक परिस्थितियों के बावजूद आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति सुचारू रखने के लिए प्रतिबद्ध है। राठौड़ ने कहा कि विपक्ष अनावश्यक भय और अफरा-तफरी फैलाकर जनता को गुमराह कर रहा है, जबकि सभी दलों को सहयोग की भावना से काम करना चाहिए। उन्होंने संसद में विपक्ष की भूमिका को अलोकतांत्रिक बताया है और कहा कि बहस के लिए निर्धारित संसदीय प्रक्रिया का पालन किया जाना चाहिए, केवल हंगामा करना उचित नहीं है। समान नागरिक संहिता (यूसीसी) पर उन्होंने कहा कि यह देशहित और सामाजिक समानता से जुड़ा विषय है, जिससे सभी नागरिकों को समान अधिकार मिलेंगे और विशेष रूप से महिलाओं को न्याय मिलेगा। उन्होंने कहा कि कुछ राज्यों में यूजीसी लागू करने की पहल सराहनीय है और भविष्य में पूरे देश में इसके लागू होने से एक देश, एक कानून की भावना मजबूत होगी तथा भेदभाव समाप्त होगा। राठौड़ ने केंद्र सरकार के कार्यों का उल्लेख करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में तीन तलाक समाप्त करने, अनुच्छेद 370 हटाने और महिला आरक्षण जैसे महत्वपूर्ण फैसले लिए गए हैं। उन्होंने विश्वास जताया कि महिला आरक्षण भी लागू होगा और भाजपा आगे भी विकास व जनहित के मुद्दों पर कार्य करती रहेगी।

पुलिस केस डायरी में जज के व्यवहार की शिकायत अवमानना नहीं

जोधपुर (हिस)। राजस्थान हाईकोर्ट ने एक मामले में स्पष्ट किया है कि पुलिस जांच के दौरान केस डायरी में पीठासीन अधिकारी (जज) के व्यक्तिगत व्यवहार को लेकर दिए गए बयान आपराधिक अवमानना नहीं हैं। जस्टिस फरजंद अली और जस्टिस योगेंद्र कुमार पुरोहित की खंडपीठ ने भीलवाड़ा के मांडलगढ़ के तत्कालीन सीनियर सिविल जज एवं एसीजेएम की ओर से भेजे गए संदर्भ पर दर्ज क्रिमिनल कंटेंट पीठासीन की पूरी तरह से खारिज कर दिया है। खंडपीठ ने इस रिपोर्टबल फैसले के माध्यम से सात पुलिस अधिकारियों तत्कालीन एएसपी दिलीप कुमार सैनी, एएसएओ भूराम खिलेरी, गेधाराम, नाथूसिंह, रामसिंह, गोपाललाल और सरोज के खिलाफ चल रही अवमानना कार्यावाही को समाप्त कर दिया है। यह पूरा विवाद मांडलगढ़ थाने में दर्ज एक एफआईआर से जुड़ा है। इसमें रेप, धोखाधड़ी और विशेष रूप से लोक सेवक द्वारा कानून की अवहेलना व महिला का अपमान जैसे गंभीर धाराओं में जांच चल रही थी। वादी पक्ष का आरोप था कि तत्कालीन थानाधिकारी भूराम खिलेरी ने उनकी शिकायत दर्ज करने में आनाकानी की। इस पर तत्कालीन पीठासीन अधिकारी ने इस्तगामा के जरिए मामला दर्ज कर जांच का आदेश दिया था। इसके बाद जांच की प्रोग्रेस से असंतुष्ट होकर कोर्ट ने अक्ट जुलाई 2019 को अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक

क्षेत्र के लिए 7, 870.32 करोड़ रुपये की राज्य सरकार सस्मिडी का प्रावधान रखा है। इसके तहत किसानों को 7.48 रुपये प्रति यूनिट की वास्तविक लागत के मुकाबले केवल 0.10 रुपये प्रति यूनिट का भुगतान करना होगा, जिससे कृषि उपभोक्ताओं को बड़ी राहत मिलेगी। इसके अलावा, 31 दिसंबर 2023 तक 10 बीएचपी तक के ट्यूबवेल कनेक्शन के लिए आवेदन करने वाले किसानों को बिना वरिष्ठता प्रभावित किए अपने लोड में वृद्धि करने की अनुमति दी गई है। यह सुविधा 31 मई 2026 तक एकमुश्त अवसर के रूप में उपलब्ध रहेगी। हालांकि, जिन उपभोक्ताओं ने पहले ही सोलर ट्यूबवेल कनेक्शन ले लिया है, वे इसके पात्र नहीं होंगे। इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए पंचकूला, फरीदाबाद, पानीपत, करनाल और गुरुग्राम में ईवी चार्जिंग स्टेशन स्थापित करने के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही, यूएचबीवीएनएल को अपने मौजूदा चार्जिंग स्टेशन को दो माह के भीतर चालू करने के लिए कहा गया है। आयोग ने पाया कि वर्तमान इडम ऑफ डे (टीओडी) टैरिफ प्रभावी नहीं है, इसलिए डिस्कॉम्स को नया और विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए हैं। वहीं, प्रीपेड स्मार्ट मीटर उपयोग करने वाले उपभोक्ताओं को ऊर्जा शुल्क और फिक्स्ड चार्ज दोनों पर 5 प्रतिशत की छूट दी जाएगी।

जोधपुर (हिस)। राजस्थान हाईकोर्ट ने एक मामले में स्पष्ट किया है कि पुलिस जांच के दौरान केस डायरी में पीठासीन अधिकारी (जज) के व्यक्तिगत व्यवहार को लेकर दिए गए बयान आपराधिक अवमानना नहीं हैं। जस्टिस फरजंद अली और जस्टिस योगेंद्र कुमार पुरोहित की खंडपीठ ने भीलवाड़ा के मांडलगढ़ के तत्कालीन सीनियर सिविल जज एवं एसीजेएम की ओर से भेजे गए संदर्भ पर दर्ज क्रिमिनल कंटेंट पीठासीन की पूरी तरह से खारिज कर दिया है। खंडपीठ ने इस रिपोर्टबल फैसले के माध्यम से सात पुलिस अधिकारियों तत्कालीन एएसपी दिलीप कुमार सैनी, एएसएओ भूराम खिलेरी, गेधाराम, नाथूसिंह, रामसिंह, गोपाललाल और सरोज के खिलाफ चल रही अवमानना कार्यावाही को समाप्त कर दिया है। यह पूरा विवाद मांडलगढ़ थाने में दर्ज एक एफआईआर से जुड़ा है। इसमें रेप, धोखाधड़ी और विशेष रूप से लोक सेवक द्वारा कानून की अवहेलना व महिला का अपमान जैसे गंभीर धाराओं में जांच चल रही थी। वादी पक्ष का आरोप था कि तत्कालीन थानाधिकारी भूराम खिलेरी ने उनकी शिकायत दर्ज करने में आनाकानी की। इस पर तत्कालीन पीठासीन अधिकारी ने इस्तगामा के जरिए मामला दर्ज कर जांच का आदेश दिया था। इसके बाद जांच की प्रोग्रेस से असंतुष्ट होकर कोर्ट ने अक्ट जुलाई 2019 को अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक

(एएसपी) को एएसएओ की भूमिका की जांच कर विस्तृत रिपोर्ट पेश करने का निर्देश दिया था। मजिस्ट्रेट के आदेश की पालना में जब एएसपी ने सीनियर पुलिस अधिकारी के तौर पर जांच शुरू की तो एएसएओ सहित अन्य पुलिसकर्मियों ने केस डायरी में अपने बयान दर्ज करवाए। इन बयानों में पुलिसकर्मियों ने आरोप लगाया कि पीठासीन अधिकारी उनसे व्यक्तिगत रूप से नाराज हैं और अक्सर दुर्व्यवहार करते हैं। इन्हीं सीमित बयानों को पीठासीन अधिकारी ने संस्था का अपमान मानते हुए हाईकोर्ट में अवमानना का संदर्भ भेज दिया था। हाईकोर्ट ने न्यायालय अवमानना अधिनियम की धारा 2(सी) और धारा 6 की बहुत सूक्ष्म व विस्तृत व्याख्या की। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि आपराधिक अवमानना तब बनती है जब किसी कृत्य से न्याय प्रशासन में बाधा डालने की वास्तविक प्रवृत्ति या मंशा हो। अधिनियम की धारा 6 के तहत, यदि किसी निचली अदालत के पीठासीन अधिकारी के खिलाफ सद्भावना में वरिष्ठ फोरम को शिकायत की जाती है, तो वह अवमानना के दायरे में नहीं आता है। हालांकि, हाईकोर्ट ने यह कड़ी चेतावनी भी दी कि दुर्भावनापूर्ण या बेवुनियाद आरोपों को यह कानूनी सुरक्षा प्राप्त नहीं होगी। कोर्ट ने अपनी टिप्पणी में साफ कर दिया कि वह पीठासीन अधिकारी पर लगे आरोपों के सच या झूठ होने पर कोई निष्कर्ष नहीं दे रहा है।

राज्यपाल आनंदी बेन पटेल ने रामनवमी की प्रदेशवासियों को दी शुभकामनाएं

लखनऊ (हिस)। उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने बुधवार को रामनवमी के अवसर पर प्रदेश एवं देशवासियों को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। अपने बधाई संदेश में राज्यपाल ने कहा कि भगवान श्रीराम का जीवन सत्य, धर्म और आदर्शों का उदाहरण है। उन्होंने समाज में मर्यादा, त्याग, कर्तव्यपरायणता और नैतिक मूल्यों की स्थापना की, जो आज भी हम सभी के लिए प्रेरणास्रोत हैं। उन्होंने कहा कि हमें भगवान श्रीराम के आदर्शों को अपने जीवन में अपनाकर एक समरस, सशक्त और आदर्श समाज के निर्माण के लिए प्रयास करना चाहिए। राज्यपाल ने कामना की, कि यह पावन पर्व सभी के जीवन में सुख, शांति, समृद्धि एवं सद्भाव लेकर आए।

वर्ष 2017 से पहले सिर्फ 2 फॉरेंसिक लैब थीं, अब राज्य में 12 हैं : मुख्यमंत्री योगी

गोरखपुर (हिस)। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बुधवार को गोरखपुर में मदन मोहन मालवीय प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय में पार्व गिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के सीएसआर फंड से 144 छात्राओं के लिए छात्रावास निर्माण हेतु भूमि पूजन एवं शिलान्यास तथा साइबर फॉरेंसिक रिसर्च सेंटर का उद्घाटन किया। उन्होंने कहा कि वर्ष 2017 से पहले उत्तर प्रदेश में सिर्फ 2 फॉरेंसिक लैब थीं, लेकिन आज राज्य में 12 फॉरेंसिक लैब काम कर रही हैं और लखनऊ में एक विश्व स्तरीय फॉरेंसिक इंस्टीट्यूट भी स्थापित किया गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बुधवार को तीन जिलों का दौरा कर विभिन्न कार्यक्रमों में हिस्सा लिया। उन्होंने सुबह बहराइच जिले में 136 परिवारों को मुख्यमंत्री आवास, शौचालय और आवास के सौंपने के लिए भूमि के पट्टों का वितरण किया। इसके बाद बलरामपुर के देवीपाटन मंदिर पहुंचे और मां पाटेश्वरी की पूजा अर्चना की और इसके बाद गोरखपुर पहुंचे। यहां उन्होंने मदन मोहन मालवीय प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय परिसर में अत्याधुनिक साइबर फॉरेंसिक रिसर्च लैब का उद्घाटन किया। छात्राओं के लिए हास्टल की भी नींव रखी। इस समारोह में



मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने नौ साल के कार्यकाल की उपलब्धियों का विस्तार से उल्लेख किया। यह हाई-टेक लैब एआई, डिजिटल फॉरेंसिक और डीएनए जांच की सुविधाओं से लैस है जो अपराधों की त्वरित जांच में पुलिस और छात्रों की मदद करेगी, जिससे प्रदेश में अपराध अनुसंधान को मजबूती मिलेगी। गोरखपुर में लैब फॉरेंसिक लैब को मुख्य विशेषताओं में इस साइट पर महिला फॉरेंसिक, मैलवेयर डिटेक्शन, और एआई-आधारित सांफ्टवेयर की सुविधा है। इस लैब के माध्यम से स्मार्टफोन, टैबलेट और क्लाउड (गूगल

ड्राइव/ड्रॉपबॉक्स) से डेटा रिकवरी संभव होगी। यह फॉरेंसिक रिसर्च लैब अब बी-श्रेणी से अपग्रेड होकर ए-श्रेणी की बन गई है, जहां डीएनए, बैलैस्टिक, और वॉयस एनालिसिस जैसी जांच हो सकेगी। यह फॉरेंसिक रिसर्च लैब आपराधिक मामलों के अनुसंधान में तेजी लाएगी और अपराधियों को समय पर सजा दिलाने में अहम भूमिका निभाएगी। मदन मोहन मालवीय प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय परिसर के छात्र भी इस लैब का उपयोग फॉरेंसिक अनुसंधान के लिए कर सकेंगे, जिससे उन्हें व्यवहारिक ज्ञान मिलेगा। समारोह में भाजपा नेताओं के अलावा स्थानीय अधिकारी और विश्वविद्यालय प्रशासन के जुड़े उपस्थित रहे। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की एक हल्की-फुल्की टिप्पणी ने राजनीतिक हलकों में नई चर्चा छेड़ दी है। कार्यक्रम में मौजूद जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों के बीच मुख्यमंत्री ने गोरखपुर के सांसद रवि किशन को लेकर चुटकी लेते हुए इशारों में कहा कि भविष्य में इस साइट पर महिला प्रत्याशी भी दावेदारी कर सकती है। मुख्यमंत्री की इस टिप्पणी के बाद राजनीतिक गतिधाराओं में तरह-तरह की अटकलें लगाई जा रही हैं।

ध्वजारोहण के साथ भगवान महावीर स्वामी का 2625वां जन्म कल्याणक महोत्सव शुरू



जोधपुर (हिस)। श्री महावीर जैन नवयुवक मण्डल एवं भगवान महावीर जन्म कल्याणक महोत्सव समिति की ओर से अहिंसा के अवतार श्रमण भगवान महावीर स्वामी का 2625वां जन्म कल्याणक महोत्सव बुधवार को पावटा स्थित भगवान महावीर उद्यान में ध्वजारोहण के साथ शुरू हुआ। महोत्सव पांच अप्रैल तक धूमधाम से मनाया जाएगा। समिति अध्यक्ष बलवंत खिंवरसा, सचिव धीरज कुमार रांका व मॉडिया प्रभारी प्रवीण सुरपणा ने बताया कि आज

सुबह समिति के पदाधिकारियों ने पावटा स्थित भगवान महावीर उद्यान में ध्वजारोहण कर कार्यक्रमों का आगач किया। उन्होंने बताया कि कार्यक्रमों की कड़ी में 27 मार्च को मानव सेवा दिवस मनाया जाएगा जिसके तहत वात्सल्यपुरम, अपनाघर, उद्यानहॉल, कुओ आश्रम, वृद्धाश्रम, सेवाभारती आदि स्थानों पर ध्वज वितरण एवं अन्य जनसेवा कार्य किए जाएंगे। फिर 28 मार्च को जीव दया दिवस समिति, श्री वीर प्रभु संस्थान व श्री वीर प्रभु महिला

मंडल के संयुक्त तत्वावधान में मनाया जाएगा। कार्यक्रम के तहत सुबह 9 बजे अरणा झरणा मोकलावास स्थित श्री ओसवाल सिंह सभा धर्मपुरा गोशाला में गायों, बकरों, खरगोश व अन्य मुक्त पशु पक्षियों को हरा चारा व लापसी वितरण व कुत्तों के बाड़े में दूध, रोटी, सोगरा आदि खिलाकर सेवा कार्य किया जाएगा। इसके बाद 29 मार्च को सांय 7.15 बजे से एक शाम प्रभु महावीर के नाम भजन संस्था सरदारपुरा स्थित गांधी मैदान में आयोजित होगी जिसमें रायपुर अधिकारिणी निकाली जाएगी। शोभायात्रा में शामिल अधिकारिणी इको फ्रेंडली होगी। वहीं पांच अप्रैल को कार्यक्रमों का समापन व सम्मान समारोह पाल रोड उद्यान अपार्टमेंट के पास स्थित खरतरागछ जैन सेवा ट्रस्ट प्रांगण में आयोजित किया जाएगा जिसमें शोभा यात्रा में भाग लेने वाली सभी संस्थाओं को स्मृति चिन्ह प्रदान कर सम्मानित किया जाएगा।

उदीयमान सूर्य को अर्घ्य देने ही चार दिवसीय चैती छठ संपन्न

भागलपुर (हिस)। जिले भर में बुधवार को उदीयमान सूर्य को अर्घ्य देने ही चार दिवसीय चैती छठ संपन्न हो गया। भागलपुर और नवगछिया, कहलगांव, पोरेली और सुल्तानगंज के गंगा घाटों पर हजारों श्रद्धालुओं ने पूजा की और सुबह-समृद्धि की कामना की। गंगा घाटों पर छठी मइया की गीतों के बीच श्रद्धालुओं में काफी उत्साह रहा। भागलपुर के बरारी घाट, कुप्पाघाट, सोढ़ी घाट सहित अन्य स्थानों पर प्रशासन ने पूजा के लिए व्यवस्था कर रखी थी। इसके अलावा सफाई, सुरक्षा के भी इंतजाम रहे। गंगा घाटों पर भारी भीड़ थी, लेकिन कई श्रद्धालुओं ने अपने घरों में ही छठ पूजा की। कुछ लोगों ने अपने आंगन या छत पर कुत्रिम तालाब बनाने, तो कुछ ने जमीन में गड्ढा खोदकर उसमें पानी भरकर सूर्य को अर्घ्य अर्पित किया। यह परंपरा विशेष रूप से उन लोगों के बीच प्रचलित है, जो किसी कारणवश घाट तक नहीं पहुंच पाते। सुबह के अर्घ्य के साथ त्रितियों का कठिन निर्जला व्रत समाप्त हुआ। छत्रतियों ने व्रताया कि बांस के बने सूप और दउरा में ठेकुआ, फल, गन्ना और अन्य प्रसाद चढ़ाए।



उधर सबौर प्रखंड के मीराचक, बाबूपुर सहित विभिन्न गंगा घाटों पर हजारों श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ पड़ी। गंगा घाटों पर प्रशासन द्वारा भी व्यापक व्यवस्था की गई थी। सफा-सफाई, सुरक्षा और प्रकाश की बेहतरीन व्यवस्था सुरक्षित की गई, ताकि श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की असुविधा न हो और वे सुरक्षित माहौल में पूजा-अर्चना कर सकें। उल्लेखनीय है कि चैती छठ का पर्व अपनी शुद्धता और अनुशासन के लिए जाना जाता है। इसमें ब्रती 36 घंटे का निर्जला उपवास रखते हैं और पूरी श्रद्धा से सूर्य देव तथा छठी मइया की पूजा करते हैं। यह पर्व सादगी और प्रकृति के प्रति गहरी आस्था को दर्शाता है, जिसमें बांस के सूप और दउरा में ठेकुआ, फल, गन्ना और अन्य प्रसाद चढ़ाए जाते हैं। गंगा घाटों पर भारी भीड़ के बावजूद, कई श्रद्धालुओं ने अपने घरों में ही छठ पूजा की परंपरा निभाई। सूर्योदय के अर्घ्य के साथ ही चैती का कठिन निर्जला व्रत समाप्त हुआ, जिसे पारण कहा जाता है। व्रती पहले भगवान को प्रसाद अर्पित करते हैं और फिर स्वयं ग्रहण करते हैं। इस दौरान परिवार के सभी सदस्य और आसपास के लोग भी प्रसाद ग्रहण कर इस पावन पर्व का हिस्सा बनते हैं।



जल्द आ रहा महिंद्रा की थार और स्कार्पियो-एन का नया फेसलिफ्ट अवतार

नई दिल्ली
अगर आप महिंद्रा थार या महिंद्रा स्कार्पियो-एन खरीदने का विचार कर रहे हैं, तो थोड़ा इंतजार करना फायदेमंद हो सकता है, क्योंकि जल्द ही इनके फेसलिफ्ट माडल बाजार में आने वाले हैं। जानकारी के अनुसार, स्कार्पियो-एन को सबसे पहले अपडेट मिलने की संभावना है। 2022 में लॉन्च हुई इस एसयूवी को अब नए डिजाइन के साथ पेश किया जाएगा, जिसमें फ्रंट में नई रेडिएटर ग्रिल, अपडेटेड बंपर और नया एयर इन्टैक शामिल हो सकता है। इसके साथ ही नई डिजाइन की हेडलाइट्स, 18-इंच के नए अलाय व्हील्स और रियर में अपडेटेड टेललैम्प भी देखने को मिल सकते हैं। केबिन में नया कलर

थीम और बड़ी टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम दिए जाने की उम्मीद है, जबकि इंजन और गियरबॉक्स में कोई बड़ा बदलाव नहीं होगा। दूसरी ओर थार को भी नया रूप दिया जाएगा, जिसमें सबसे ज्यादा बदलाव इसके एक्सटिरीर डिजाइन में देखने को मिलेंगे। इसमें थार राक्स से प्रेरित नई 6-स्लाट ग्रिल, सी-शेप एलईडी डीआरएलएस और अपडेटेड एलईडी हेडलाइट्स शामिल हो सकती हैं। साथ ही बड़े अलाय व्हील्स का विकल्प भी मिल सकता है, जो इसके मस्कूलर लुक को और आकर्षक बनाएगा। इंटीरियर में भी कुछ नए फीचर्स जैसे वायरलेस चार्जर, वॉटलेटेड सीटें और पुश-बटन स्टार्ट जैसे आधुनिक फीचर्स जोड़े जा सकते हैं।

इलेक्ट्रिक एसयूवी आईकार वी 23 मचाएगी हलचल

नई दिल्ली। जेएसडब्ल्यू ग्रुप और चीन की कंपनी वेरी आटोमोबाइल की साझेदारी से बनी इलेक्ट्रिक एसयूवी आईकार वी 23 की लॉन्चिंग की तैयारी तेज हो गई है। इस एसयूवी को हाल ही में मध्य प्रदेश के उज्जैन के पास टैरिंग के दौरान देखा गया है। टैरिंग के दौरान सामने आई तस्वीरों में इसकी रोड प्रेजेंस और रियर डिजाइन झलकता है, हालांकि वाहन पूरी तरह कैमोफ्लाज से ढका हुआ था। इस अपकमिंग एसयूवी का डिजाइन लाइफटाइल एसयूवी कैटेगरी को ध्यान में रखकर तैयार किया जा रहा है। इसका बावसी और चौकोर रियर डिजाइन इसे रफ-एंड-टफ अपील देता है। टैरर मूल में स्टील व्हील्स देखने को मिले, जिससे संकेत मिलता है कि यह शुरुआती प्रोटोटाइप है और कंपनी फिलहाल बेस वैरिएंट्स पर फोकस कर रही है। इसके बावजूद इसकी मस्कूलर बाडी और ऊंचा स्टॉन इसे एक मजबूत रोड प्रेजेंस प्रदान करते हैं। मैनुफैचरिंग की बात करें तो इस एसयूवी को भारत में ही असेंबल किया जाएगा। जेएसडब्ल्यू मोटर महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजीनगर में अपना नया प्लांट स्थापित कर रही है, जहां अगस्त 2026 तक उत्पादन शुरू होने की उम्मीद है।

न्यूज़ ब्रीफ

अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमत 100 डालर प्रति बैरल के स्तर से नीचे



नई दिल्ली। पश्चिम एशिया में शांति होने की उम्मीद के कारण अंतरराष्ट्रीय बाजार में कूच आयल (कच्चे तेल) की कीमत एक बार फिर 100 डालर प्रति बैरल के स्तर से नीचे आ गई है। भारतीय समय के मुताबिक सुबह 10:15 बजे ब्रेट कूच 99.17 डालर प्रति बैरल के स्तर पर और वेस्ट टेक्सस इंटरमीडिएट (डब्ल्यूटीआई) कूच 88.51 डालर प्रति बैरल के स्तर पर कारोबार कर रहे थे। इसके पहले ब्रेट कूच पिछले कारोबारी दिन यानी मंगलवार को 104.49 डालर प्रति बैरल के स्तर पर बंद हुआ था। वहीं डब्ल्यूटीआई कूच ने 92.35 डालर प्रति बैरल के स्तर पर मंगलवार के कारोबार का अंत किया था। कारोबार की शुरुआत में ब्रेट कूच लगभग छह प्रतिशत की कमजोरी के साथ 99.83 डालर प्रति बैरल के स्तर पर खुला। ट्रेडिंग शुरू होने के थोड़ी देर बाद ही ब्रेट कूच की कीमत घट कर 97.18 डालर प्रति बैरल के स्तर तक आ गई। इस गिरावट के बाद ब्रेट कूच की कीमत में इजाफा हुआ, जिससे थोड़ी देर के लिए ब्रेट कूच उछल कर 100.03 डालर प्रति बैरल के स्तर तक पहुंच गया। हालांकि थोड़ी देर बाद इसकी कीमत एक बार फिर 100 डालर के स्तर से नीचे आ गई। सुबह 10:15 बजे तक का कारोबार होने के बाद ब्रेट कूच 5.11 प्रतिशत की गिरावट के साथ 99.17 डालर प्रति बैरल के स्तर पर कारोबार कर रहा था। ब्रेट कूच की तरह ही वेस्ट टेक्सस इंटरमीडिएट (डब्ल्यूटीआई) कूच में भी पांच प्रतिशत से अधिक की गिरावट दर्ज की गई। डब्ल्यूटीआई कूच ने 88.53 डालर प्रति बैरल के स्तर से कारोबार की शुरुआत की। थोड़ी ही देर में इसकी कीमत टूट कर 86.72 डालर प्रति बैरल के स्तर तक आ गई। इसके बाद कुछ देर के लिए डब्ल्यूटीआई कूच उछल कर 89.36 डालर प्रति बैरल के स्तर तक पहुंचा।

पुणे के आटोमोबाइल हब पर कच्चे माल और जरूरी पुर्जों की कमी, उत्पादन टप



पुणे। देश के प्रमुख औद्योगिक केंद्र पुणे के आटोमोबाइल हब पर कच्चे माल और जरूरी पुर्जों की कमी का असर पड़ रहा है। एलपीजी, कच्चे माल और आटो पार्ट्स की आपूर्ति बाधित होने से कई कंपनियों के सामने उत्पादन बंद करने की स्थिति बन गई है। उद्योग से जुड़े स्रोतों के मुताबिक आटो मैनुफैचरिंग कंपनियां केवल एक सप्ताह का स्टॉक रखती हैं। मौजूदा आपूर्ति संकट के चलते यह स्टॉक खत्म हो रहा है, जिससे बड़ी कंपनियों को भी उत्पादन घटाने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। यदि स्थिति जल्द नहीं सुधरी, तो कई इकाइयों में पूरी तरह उत्पादन टप हो सकता है। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए विकास आयुक्त ने वीथीयो कान्फ्रेंसिंग के जरिए संबंधित अधिकारियों और उद्योग प्रतिनिधियों के साथ बैठक कर हालात का मूल्यांकन करने के निर्देश दिए।

टोयोटा लैंड क्रूजर एफजे थाइलैंड में लॉन्च



नई दिल्ली। टोयोटा मोटर कारपोरेशन ने अपनी नई टोयोटा लैंड क्रूजर एफजे को थाइलैंड में लॉन्च कर दिया है। भारतीय एसयूवी बाजार में एक और बड़ा नाम जुड़ गया है। इसे फार्च्यूनर का किफायती विकल्प माना जा रहा था, लेकिन थाइलैंड में इसकी कीमत ने इस धारणा को बदल दिया है। वहां यह एसयूवी टोयोटा फार्च्यूनर के डीजल वैरिएंट से भी महंगी है, जिससे इसकी प्राइसिंग को लेकर चर्चाएं तेज हो गई हैं। थाइलैंड में लैंड क्रूजर एफजे के पेट्रोल वैरिएंट की कीमत करीब 1.269 मिलियन रखी गई है, जो भारतीय मुद्रा में लगभग 36 लाख रुपये के आसपास बैठती है। वहीं फार्च्यूनर लीडर डीजल वैरिएंट की कीमत इससे थोड़ी कम है। ऐसे में यह साफ संकेत मिलता है कि यह माडल वैश्विक बाजार में एक प्रीमियम पोजिशनिंग के साथ पेश किया गया है। भारत में इसके लॉन्च को लेकर भी संभावनाएं जताई जा रही हैं और उम्मीद है कि यह एसयूवी इसी साल भारतीय बाजार में दस्तक दे सकती है। डिजाइन की बात करें तो लैंड क्रूजर एफजे में रेट्रो और माडर्न एलिमेंट्स का शानदार मिश्रण देखने को मिलता है। इसका बावसी लुक, सीधा स्टॉन, राउंड हेडलाइट्स और प्लैट बोर्ड इसे क्लासिक लैंड क्रूजर की झलक देते हैं, जबकि एलईडी लाइटिंग और बड़े अलाय व्हील्स इसे आधुनिक अपील प्रदान करते हैं।

सब्सक्रिप्शन के लिए लॉन्च हुआ विविड इलेक्ट्रोमेक का आईपीओ, 30 मार्च तक लगा सकते हैं बोली

नई दिल्ली

लो और मीडियम वोल्टेज इलेक्ट्रिकल पैनेल तथा आटोमेशन सिस्टम बनाने वाली कंपनी विविड इलेक्ट्रोमेक का 130.54 करोड़ रुपये का आईपीओ सब्सक्रिप्शन के लिए लॉन्च कर दिया गया। इस आईपीओ में 30 मार्च तक बोली लगाई जा सकती है। इश्यु की क्लोजिंग के बाद दो अप्रैल को शेयरों का अलॉटमेंट किया जाएगा, जबकि छह अप्रैल को अलॉटमेंट शेयर डीमैट अकाउंट में क्रेडिट कर दिए जाएंगे। कंपनी के शेयर सात अप्रैल को एनएसई के एसएमई प्लेटफॉर्म पर लिस्ट हो सकते हैं।

इस आईपीओ में बोली लगाने के लिए 528 रुपये से लेकर 555 रुपये प्रति शेयर का प्राइस बैंड तय किया गया है, जबकि लॉट साइज 240 शेयर का है। विविड इलेक्ट्रोमेक के इस आईपीओ में रिटेल इनवेस्टर्स को दो लॉट यानी 480 शेयरों के लिए बोली लगाना होगा, जिसके लिए उन्हें 2,66,400 रुपये का निवेश करना होगा। इस आईपीओ के तहत 10 रुपये फेस वैल्यू वाले कुल 23.52 लाख शेयर जारी किए जा रहे हैं। इनमें 98 करोड़ रुपये के 17,65,200 नए शेयर और 4.68 लाख शेयर आफर फार सेल विंडो के जरिये बेचे जा रहे हैं।

इस आईपीओ में क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशन बायर्स (क्यूआईबी) के लिए 47.42 प्रतिशत हिस्सा रिजर्व किया गया है। इसके अलावा रिटेल इनवेस्टर्स के लिए 33.27 प्रतिशत हिस्सा और नान इंस्टीट्यूशन इनवेस्टर्स (एनआईआई) के लिए 14.27 प्रतिशत हिस्सा रिजर्व है। इसके अलावा कंपनी के मार्केट मेकर्स के लिए 5.05 प्रतिशत हिस्सा रिजर्व किया गया है। इस इश्यु के लिए हेम सिन्धोसिटी लिमिटेड को बुक रनिंग लीड मैनेजर बनाया गया है, जबकि एमयूजीएफ इन्टाइव इंडिया प्राइवेट लिमिटेड को रजिस्ट्रार बनाया गया है। वहीं हेम फिनलोज प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का मार्केट मेकर है।

कंपनी की वित्तीय स्थिति की बात करें तो कैपिटल मार्केट रेगुलेटर सेबी के पास जमा करिए गए ड्राफ्ट रेड हेरिंग प्रॉस्पेक्टस (डीआरएचपी) में किए गए दावों के मुताबिक इसकी वित्तीय सेहत लगातार मजबूत हुई है। वित्त वर्ष 2022-23 में कंपनी को छह लाख रुपये का शुद्ध लाभ हुआ था, जो अगले वित्त वर्ष 2023-24 में बढ़ कर 4.28 करोड़ रुपये और वित्त वर्ष 2024-25 में उछल



Vivid Electromech IPO GMP

कर 20.24 करोड़ रुपये के स्तर पर पहुंच गया। मौजूदा वित्त वर्ष की पहली छमाही यानी अप्रैल से 30 सितंबर 2025 तक कंपनी को 9.44 करोड़ रुपये का शुद्ध लाभ हो चुका है। इस दौरान कंपनी की राजस्व प्राप्ति में भी लगातार बढ़ोतरी हुई। वित्त वर्ष 2022-23 में इसे 59.63 करोड़ का कुल राजस्व प्राप्त हुआ, जो वित्त वर्ष 2023-24 में बढ़ कर 89.55 करोड़ और वित्त वर्ष 2024-25 में उछल कर 155.77 करोड़ रुपये के स्तर पर आ गया। मौजूदा वित्त वर्ष की पहली छमाही यानी अप्रैल से 30 सितंबर 2025 तक कंपनी को 70.89 करोड़ रुपये का राजस्व प्राप्त हो चुका है। इस अवधि में कंपनी पर लदे कर्ज के बोझ में उतार चढ़ाव होता रहा। वित्त वर्ष 2022-23 के अंत में कंपनी पर 6.47 करोड़ रुपये के कर्ज का बोझ था, जो वित्त वर्ष 2023-24 में घट कर 4.77 करोड़ रुपये और वित्त वर्ष 2024-25 में और कम होकर 4.23 करोड़ रुपये के स्तर पर आ गया। मौजूदा वित्त वर्ष की पहली छमाही यानी अप्रैल से 30 सितंबर 2025 तक को बात करें, तो इस दौरान कंपनी पर लदे कर्ज का बोझ बढ़ कर 14.17 करोड़ रुपये के स्तर पर आ गया। इस अवधि में कंपनी के नेटवर्थ में भी बढ़ोतरी

हुई। वित्त वर्ष 2022-23 में ये 2.38 करोड़ रुपये के स्तर पर था, जो 2023-24 में बढ़ कर 6.98 करोड़ रुपये हो गया। इसी तरह 2024-25 में कंपनी का नेटवर्थ 27.45 करोड़ रुपये के स्तर पर आ गया। वहीं मौजूदा वित्त वर्ष की पहली छमाही यानी अप्रैल से 30 सितंबर 2025 तक ये 37.03 करोड़ रुपये के स्तर पर पहुंच गया। इस अवधि में कंपनी के रिजर्व और सपरप्लस में भी बढ़ोतरी हुई। वित्त वर्ष 2022-23 में ये 14.94 करोड़ रुपये के स्तर पर था, जो 2023-24 में बढ़ कर 18.05 करोड़ रुपये हो गया। इसी तरह 2024-25 में कंपनी का नेटवर्थ 38.29 करोड़ रुपये के स्तर पर आ गया। वहीं मौजूदा वित्त वर्ष की पहली छमाही यानी अप्रैल से 30 सितंबर 2025 तक ये 44.23 करोड़ रुपये के स्तर पर पहुंच गया। इसी तरह ईवीआईटीडीए (अनिंग बिफोर इंटेस्ट, टैक्ससेज, डिप्रेशिएशंस एंड एमाटाइजेशन) 2022-23 में 1.76 करोड़ रुपये के स्तर पर था, जो 2023-24 में बढ़ कर 7.18 करोड़ रुपये और 2024-25 में 28.39 करोड़ रुपये के स्तर पर आ गया। वहीं मौजूदा वित्त वर्ष की पहली छमाही यानी अप्रैल से 30 सितंबर 2025 तक ये 13.50 करोड़ रुपये के स्तर पर था।

दस वर्षों में करीब 80 प्रतिशत कारें हो जाएंगी आटोमैटिक : गुला



नई दिल्ली। कार खरीदने वाले लोग आजकल गियर बदलने और वलव दबाने की पारंपरिक प्रक्रिया से तेजी से दूर होते जा रहे हैं। आने वाले लगभग दस वर्षों में देश की करीब 80 प्रतिशत कारें आटोमैटिक हो जाएंगी। यह कहना है स्कॉड आटो इंडिया के ब्रांड डायरेक्टर आशीष गुला को। उनका मानना है कि इसका स्पष्ट संकेत है कि अब उपभोक्ता ड्राइविंग में मेहनत की बजाय सुविधा और आराम को अधिक प्राथमिकता दे रहे हैं। इसी कारण मैनुअल गियरबाक्स की लोकप्रियता में लगातार गिरावट दर्ज की जा रही है। वर्तमान समय में आटोमैटिक कारों की हिस्सेदारी लगभग 40 प्रतिशत तक पहुंच चुकी है, जबकि स्कॉड जैसी प्रीमियम कंपनियों के पोर्टफोलियो में यह आंकड़ा और भी अधिक है। कंपनी की लगभग 65 प्रतिशत कारें अब आटोमैटिक ट्रांसमिशन के साथ बिक रही हैं। इसका प्रमुख कारण महानगरीय और बड़े शहरों में बढ़ता ट्रैफिक है, जहां बार-बार वलव और गियर बदलना ड्राइविंग को थकाऊ बना देता है। पहले ग्राहक माइलेज और कम मेंटेनेंस को ध्यान में रखकर मैनुअल कारों को प्राथमिकता देते थे, लेकिन अब प्राथमिकताएं बदल चुकी हैं। नई तकनीक के चलते आटोमैटिक गियरबाक्स अब माइलेज के मामले में भी मैनुअल के बराबर या कई बार उससे बेहतर प्रदर्शन कर रहे हैं।

वायदा बाजार में बड़ी सोना और चांदी की कीमत, अंतरराष्ट्रीय बाजार में भी आई तेजी

नई दिल्ली

पिछले कई दिनों से लगातार गिरावट का सामना कर रहे सोने और चांदी के भाव में अंतरराष्ट्रीय बाजार से लेकर वायदा बाजार तक तेजी का रुख बना हुआ नजर आ रहा है। घरेलू सरफा बाजार में भी सोना और चांदी दोनों चमकीली धातुओं ने जबरदस्त तेजी दिखाई है। मल्टी कर्मांडी एक्सचेंज (एमसीएक्स) में सोना तीन प्रतिशत से अधिक और चांदी पांच प्रतिशत से अधिक उछल गया है। मल्टी कर्मांडी एक्सचेंज (एमसीएक्स) पर अप्रैल की छिल्लीबरी बाला सोना 3.63 प्रतिशत उछल कर 1,43,960 रुपये प्रति 10 ग्राम के स्तर पर पहुंचा हुआ है। इसी तरह मई में छिल्लीबरी बाला चांदी 5.52 प्रतिशत की छलांग लगा कर 2,36,300 रुपये प्रति किलोग्राम के स्तर पर कारोबार कर रही है। अंतरराष्ट्रीय बाजार की बात करें तो, सोना और चांदी के भाव में यहाँ भी तेजी का रुख बना हुआ है। सिंगापुर गोल्ड एक्सचेंज में हाफिर सोना 3.76 प्रतिशत की उछाल के साथ 4567.30 डालर प्रति औंस के स्तर पर कारोबार कर रहा है। इसी तरह लंदन सिस्ल्वर मार्केट में हाहरी चांदी की कीमत 5.75 प्रतिशत की बढ़ोतरी के साथ 73.57 डालर प्रति औंस के स्तर पर



पहुंची हुई है। मार्केट एक्सपर्ट्स का मानना है कि पश्चिम एशिया में जंग धमने की उम्मीद बनने के कारण निवेशकों का रुझान एक बार फिर सोना और चांदी जैसे सेफ इन्वेस्टमेंट इस्ट्रुमेंट की ओर बढ़ने लगा है। पश्चिम एशिया में शांति होने की उम्मीद बनने के कारण डालर के प्रति भी आकर्षण कम हुआ है। इसका असर भी सोने और चांदी की

कीमत पर सकारात्मक रूप से पड़ा है। कैपेक्स गोल्ड एंड इन्वेस्टमेंट्स के सीईओ राजीव दाता का कहना है कि पश्चिम एशिया में जैसे-जैसे लड़ाई धमने की उम्मीद बढ़ेगी, वैसे-वैसे सोना और चांदी दोनों चमकीली धातुओं की कीमत में भी तेजी आएगी। खासकर, चांदी की कीमत में तुलनात्मक तौर पर अधिक तेजी आ सकती है।

पश्चिम एशिया में शांति की उम्मीद के कारण ग्लोबल मार्केट से पाजिटिव संकेत, एशिया में भी तेजी का रुख

नई दिल्ली

पश्चिम एशिया में शांति होने की उम्मीद के कारण ग्लोबल मार्केट से मजबूती के संकेत मिल रहे हैं। इसके पहले पिछले सत्र के दौरान अमेरिका और ईरान के बीच जारी जंग को लेकर जारी असमंजस की स्थिति की वजह से अमेरिकी बाजार कमजोरी के साथ बंद हुए थे। हालांकि डाउ जॉन्स पच्यूस मजबूती के साथ कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है। यूरोपीय बाजार में पिछले सत्र के दौरान मिला-जुला कारोबार होता



पश्चिम एशिया में जारी युद्ध में सीजफायर को लेकर अमेरिका और ईरान को से अलग-अलग बयान आने की वजह से पिछले सत्र के दौरान अमेरिकी बाजार में असमंजस की स्थिति

184.87 अंक 0.84 प्रतिशत की गिरावट के साथ 21,761.89 अंक के स्तर पर पिछले सत्र के कारोबार का अंत किया। वहीं डाउ जॉन्स पच्यूस फिलहाल 379.77 अंक यानी 0.82 प्रतिशत उछल कर 46,503.83 अंक के स्तर पर पहुंचा हुआ है। यूरोपीय बाजार पिछले सत्र के कारोबार के बाद मिले-जुले परिणाम के साथ बंद हुए। एफटीएसई इंडेक्स 0.71 प्रतिशत की मजबूती के साथ 9,965.16 अंक के स्तर पर बंद हुआ। इसी तरह सीएसई इंडेक्स ने 0.23 प्रतिशत की तेजी के साथ 7,743.92 अंक के स्तर पर पिछले सत्र के कारोबार का अंत किया। इसके विपरीत डीएक्स इंडेक्स 0.07 प्रतिशत की कमजोरी के साथ 22,636.91 अंक के स्तर पर बंद हुआ। एशियाई बाजार में चौतरफा तेजी का रुख बना हुआ है। एशिया के सभी नौ बाजार मजबूती के साथ हरे निशान में कारोबार कर रहे हैं। गिफ्ट निफ्टी 265.50 अंक यानी 1.16 प्रतिशत की तेजी के साथ 23,212 अंक के स्तर पर कारोबार कर

रहा है। इसी तरह स्ट्रेंस टाइम्स इंडेक्स 0.37 प्रतिशत उछल कर 4,880.19 अंक के स्तर पर पहुंचा हुआ है। ताइवान नेटड इंडेक्स ने बड़ी छलांग लगाई है। फिलहाल यह सूचकांक 870.61 यानी 2.67 प्रतिशत की बढ़त के साथ 33,482.85 अंक के स्तर पर पहुंचा हुआ है। इसी तरह निक्केई इंडेक्स 1,372.72 अंक यानी 2.63 प्रतिशत की मजबूती के साथ 53,625 अंक के स्तर तक आ गया है। इसके अलावा सेट कंपोजिट इंडेक्स 2.16 प्रतिशत की तेजी के साथ 1,440.79 अंक के स्तर पर, कोसॉ इंडेक्स 98.99 अंक यानी 1.78 प्रतिशत उछल कर 5,652.91 अंक के स्तर पर, शंघाई कंपोजिट इंडेक्स 0.88 प्रतिशत की छलांग लगा कर 3,915.49 अंक के स्तर पर, जकार्ता कंपोजिट इंडेक्स 0.64 प्रतिशत की बढ़त के साथ 7,152.21 अंक के स्तर पर और हेंग सैंग इंडेक्स 0.06 प्रतिशत की मामूली मजबूती के साथ 25,078 अंक के स्तर पर कारोबार कर रहे हैं।



लैक्रास टीमों से लास एंजेलिस ओलंपिक के लिए क्वालिफाई कर इतिहास रचने का आह्वान

नई दिल्ली

केंद्रीय युवा मामलों एवं खेल मंत्री मनसूख मंडाविया ने बुधवार को भारतीय पुरुष और महिला लैक्रास टीमों को रियाद में आयोजित एशियन लैक्रास गेम्स में स्वर्ण पदक जीतने पर सम्मानित किया। इस दौरान उन्होंने खिलाड़ियों से कड़ी मेहनत जारी रखने और लास एंजेलिस 2028 ओलंपिक के लिए क्वालिफाई कर इतिहास रचने का लक्ष्य रखने का आह्वान किया। खिलाड़ियों से बातचीत करते हुए खेल मंत्री ने कहा कि लैक्रास जैसे उभरते खेलों में सफलता के लिए दृढ़ संकल्प, अंतरराष्ट्रीय अनुभव और

निरंतर मेहनत बेहद जरूरी है। उन्होंने कहा, लैक्रास भारत के लिए एक उभरता हुआ बड़ा खेल है। यह आपका पहला बड़ा अंतरराष्ट्रीय अनुभव था और आपने पहले ही देश के लिए पदक जीत लिए हैं। अब आपको और मेहनत करनी है, अधिक अनुभव हासिल करना है और ओलंपिक के लिए क्वालिफाई कर देश का नाम रोशन करना है।

उन्होंने यह भी कहा कि सरकार खेलों इंडिया जैसी योजनाओं के माध्यम से खिलाड़ियों को लगातार समर्थन देती रहेगी, लेकिन सफलता के लिए खूनून और निरंतर प्रयास सबसे महत्वपूर्ण हैं। भारत ने इस साल फरवरी में सऊदी अरब के रियाद में आयोजित एशियन लैक्रास गेम्स में शानदार प्रदर्शन करते हुए सिक्सेस फाउंट पदक जीत लिए हैं। अरब आपकी और मेहनत करनी है, अधिक अनुभव हासिल करना है और ओलंपिक के लिए क्वालिफाई कर देश का नाम रोशन करना है।

गौरतलब है कि भारतीय महिला लैक्रास टीम ने 2024 में और पुरुष टीम ने 2025 में अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पदार्पण किया था, ऐसे में यह उपलब्धि और भी खास मानी जा रही है।

टीमों में देश के विभिन्न राज्यों—राजस्थान, महाराष्ट्र, हरियाणा, गुजरात, तमिलनाडु, ओडिशा, असम, जम्मू-कश्मीर, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और उत्तर प्रदेश—के खिलाड़ियों ने प्रतिनिधित्व किया।

भारत की अगली बड़ी प्रतियोगिताएं अप्रैल में चीन के चेंगदू में होने वाले एशियन लैक्रास गेम्स और अक्टूबर में आस्ट्रेलिया में होने वाली एशिया-पैसिफिक सिक्सेस लैक्रास चैंपियनशिप हैं, जो लास एंजेलिस 2028 ओलंपिक क्वालिफिकेशन का अहम हिस्सा होंगी।

न्यूज़ ब्रीफ

पंजाब किंग्स के साथ जुड़े आस्ट्रेलियाई खिलाड़ी मार्कस स्टोडिनिस और कूपर कोनोली



चंडीगढ़। पंजाब किंग्स के आस्ट्रेलियाई खिलाड़ी मार्कस स्टोडिनिस और कूपर कोनोली आधिकारिक तौर पर मोहाली में टीम के साथ जुड़ गए हैं। दोनों खिलाड़ी आज सुबह टीम कैम्प में शामिल हुए, जहां उनका जोरदार स्वागत किया गया। न्यू इंटर्नेशनल क्रिकेट स्टैडियम पहुंचने पर दोनों खिलाड़ी काफी उत्साहित नजर आए। उनकी मौजूदगी से पंजाब किंग्स की टीम को बड़ी मजबूती मिली है, जिसमें अनुभव और युवा जोश का शानदार मिश्रण देखने को मिलेगा। पिछले सीजन में उपविजेता रही पंजाब किंग्स की टीम पिछले कुछ हफ्तों से कड़ी ट्रेनिंग कर रही है और अब आईपीएल 2026 के लिए अपनी तैयारियों को अंतिम रूप दे रही है। टीम अपना पहला मुकाबला 31 मार्च को घरेलू मैदान पर गुजरात टाइटंस के खिलाफ खेलेगी, जिसे लेकर टीम और फैंस दोनों में काफी उत्साह देखने को मिल रहा है।

महिला क्रिकेट: न्यूजीलैंड ने पांचवें टी-20 में दक्षिण अफ्रीका को हराकर 4-1 से जीती सीरीज

क्राइस्टचर्च। अमेरिका के शानदार आंतरराष्ट्रीय प्रदर्शन की बदौलत न्यूजीलैंड ने बुधवार को पांचवें टी-20 मैच में दक्षिण अफ्रीका को 92 रनों से हराकर सीरीज 4-1 से अपने नाम कर ली। हेमले ओवल में खेले गए इस मुकाबले में केर ने 55 गेंदों पर 105 रनों की तुफानी

पारी खेलने के साथ गेंदबाजी में भी दो विकेट झटकें। इस शानदार प्रदर्शन के लिए अमेरिका के गेंदबाज आफ द मैच और प्लेयर ऑफ द सीरीज चुना गया। टास हारकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी न्यूजीलैंड की शुरुआत अच्छी नहीं रही और इसाबेला गेज जल्दी आउट हो गई। इसके बाद अमेरिका केर और जार्जिया टिनर ने पारी को संभालते हुए दूसरे विकेट के लिए 45 रनों की साझेदारी की। हालांकि तुमी सेखुखुने ने लगातार दो गेंदों पर विकेट लेकर न्यूजीलैंड को झटका दिया, लेकिन केर ने आक्रामक अंदाज जारी रखा। अमेरिका केर ने सुने लूस और तुमी सेखुखुने पर लगातार चौके जड़ते हुए रन गति तेज की। इसके बाद कुल हाउसिंग के साथ मिलकर 73 रनों की अहम साझेदारी की। अंतिम ओवरों में केर ने तेज रन बटोरते हुए टीम का स्कोर 20 ओवर में 194/6 तक पहुंचाया। दक्षिण अफ्रीका की ओर से अयाबोगा खाका और तुमी सेखुखुने ने तीन-तीन विकेट लिए। लक्ष्य का पीछा करने उतरी दक्षिण अफ्रीका की शुरुआत बेहद खराब रही। लिया ताहुडू और सोफी डिवाने ने पावरप्ले में ही शीर्ष क्रम को झकझोर दिया और टीम 40 रन पर 4 विकेट गंवा बैठी। पुनेरी डर्कसन ने 23 रन बनाकर संघर्ष करने की कोशिश की, लेकिन उन्हें भी अमेरिका केर ने आउट कर दिया। इसके बाद कोई भी बल्लेबाज टिक नहीं सका और पूरी टीम 20 ओवर में 102/9 तक ही पहुंच सकी। संक्षिप्त स्कोरकार्ड: न्यूजीलैंड - 20 ओवर में 194/6 (अमेरिका केर 105, जार्जिया टिनर 27; अयाबोगा खाका 3/32, तुमी सेखुखुने 3/32), रही।

आईपीएल 2026 में संजु सैमसन के पास बड़ा मौका, धोनी के खास वलब में शामिल होने की दहलीज पर



नई दिल्ली। संजु सैमसन ने टी20 विश्व कप 2026 में शानदार प्रदर्शन करते हुए भारतीय टीम को चैंपियन बनाने में अहम भूमिका निभाई और अब उनकी नजर आईपीएल 2026 में एक बड़ी उपलब्धि हासिल करने पर टिकी है। सैमसन ने वेस्टइंडीज के खिलाफ क्वार्टर फाइनल में नाबाद 97, इंग्लैंड के खिलाफ सेमीफाइनल में 89 और न्यूजीलैंड के खिलाफ फाइनल में 89 रन की अहम पारियां खेलकर अपनी बल्लेबाजी का लोहा मनवाया। अब आईपीएल में भी अगर वह इसी फार्म को बरकरार रखते हैं, तो एक खास रिकार्ड अपने नाम कर सकते हैं। दरअसल, विकेटकीपर बल्लेबाज के तौर पर 5000 या उससे ज्यादा रन बनाने का कारनामा अभी तक सिर्फ एमएस धोनी ने किया है। धोनी ने 2008 से 2025 के बीच 278 मैचों की 242 पारियों में 5439 रन बनाए हैं, जिसमें 24 अर्धशतक शामिल हैं। हालांकि केएल राहुल के नाम भी 5000 से ज्यादा रन हैं, लेकिन उन्होंने अपने पूरे करियर में हर मैच विकेटकीपर के रूप में नहीं खेला है। संजु सैमसन इस खास वलब में शामिल होने के बेहद करीब हैं। उन्होंने 2013 से 2025 के बीच 177 मैचों की 172 पारियों में 3 शतक और 26 अर्धशतक की मदद से 4704 रन बनाए हैं।

हाकी इंडिया वार्षिक पुरस्कार में डबल नामिनेशन से आत्मविश्वास से भरे प्रिंस दीप ने कहा- इससे मेरे मन के कई संदेह दूर हुए

नई दिल्ली

हाकी इंडिया के 8वें वार्षिक पुरस्कार 2025 में गोलकीपर आफ द ईयर और अफेक्टिव प्लेयर आफ द ईयर (अंडर-21 पुरुष) के लिए नामित होने वाले प्रिंस दीप सिंह के लिए यह उपलब्धि सिर्फ एक सम्मान नहीं, बल्कि आत्मविश्वास बढ़ाने वाला बड़ा मोड़ है। प्रिंस ने हाकी इंडिया के हवाले से कहा, मैं बहुत खुश और गौरव महसूस कर रहा हूँ। आमतौर पर ऐसे अवार्ड के लिए समय लगता है, लेकिन मुझे जल्दी मौका मिला। इससे मेरे मन के कई संदेह दूर हुए और अब लगता है कि मैं सही दिशा में हूँ। युवा गोलकीपर ने अपने अब तक के सफर को याद करते हुए कहा कि उन्होंने हमेशा दबाव में खुद को साबित करने की कोशिश की है। जूनियर वर्ल्ड कप में अहम मुकाबलों को याद करते हुए उन्होंने कहा, ऐसे मैचों में टीम का भरोसा बहुत मायने रखता है। जब साथियों ने मुझ पर विश्वास जताया, तो मेरा आत्मविश्वास और बढ़ गया और मैं टीम के लिए बेहतर प्रदर्शन कर सका। प्रिंस ने बताया कि उनका करियर गोलकीपर के रूप में शुरू नहीं हुआ था। उन्होंने कहा, मैं शुरूआत में डिफेंडर था, लेकिन फुटबाल खेलते समय गोलकीपिंग करता था। वहीं मेरे कोच ने मेरी कान्फिडेंस पहचानी और मुझे हाकी में गोलकीपर बनने के लिए कहा। वहीं से मेरी असली यात्रा शुरू हुई। गोलकीपिंग को मानसिक रूप से चुनौतीपूर्ण बताते हुए प्रिंस ने कहा, इस पोजीशन पर हमेशा दबाव रहता है—चाहे दर्शकों का हो या मैच की स्थिति का। मैं मैच से एक दिन पहले ही मानसिक तैयारी शुरू कर देता हूँ। मैदान पर लगातार संवाद बनाए रखना मुझे नियंत्रण में रखता है। सीनियर टीम में अभी तक पदार्पण नहीं करने के बावजूद दिग्गज गोलकीपरों के साथ नामांकन पर उन्होंने कहा, भारत में गोलकीपरों को मजबूत प्रतिस्पर्धा है। ऐसे खिलाड़ियों के बीच नाम आना मेरे लिए बहुत खास है और इससे मुझे आगे बढ़ने की प्रेरणा मिलती है। अंत में उन्होंने अपने लक्ष्य को स्पष्ट करते हुए कहा, मेरा सपना भारतीय सीनियर टीम का मुख्य गोलकीपर बनना और देश के लिए ओलंपिक स्वर्ण पदक जीतना है। अगर मुझे यह अवार्ड मिलता है, तो मैं इसे अपने परिवार को समर्पित करूंगा, क्योंकि उनका समर्थन ही मेरी सबसे बड़ी ताकत है।



केकेआर ने आंद्रे रसेल के सम्मान में रिटायर की जर्सी नंबर 12

कोलकाता। आईपीएल फ्रेंचाइजी कोलकाता नाइट राइडर्स ने अपने दिग्गज आलराउंडर आंद्रे रसेल को खास सम्मान देते हुए उनकी जर्सी नंबर 12 को रिटायर करने का ऐलान किया है। यह घोषणा टीम के प्री-सीजन इवेंट नाइट अनलैप्ड 3.0 के दौरान की गई। रसेल, जिन्हें फ्रेंचाइजी ने इंटर्नल नाइट का दर्जा दिया है, 2014 से 2025 तक केकेआर के लिए खेलते रहे और इस दौरान उन्होंने टीम को कई यादगार जीत दिलाईं। उन्होंने 140 आईपीएल मैचों में 2651 रन बनाए और 123 विकेट लिए। वह लीग के चुनिंदा खिलाड़ियों में शामिल हैं, जिन्होंने 2000 से ज्यादा रन और 100 से अधिक विकेट का दोहरा आंकड़ा हासिल किया है। रसेल केकेआर की 2014 और 2024 की खिताबी जीत में अहम भूमिका निभा चुके हैं। 2019 सीजन में उनके शानदार प्रदर्शन के लिए उन्हें मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर भी चुना गया था। इसके अलावा, 2021 में मुंबई इंडियंस के खिलाफ 5/15 का उनका प्रदर्शन केकेआर के इतिहास का सर्वश्रेष्ठ गेंदबाजी आंकड़ा है। केकेआर के सीईओ वेकी मैसूर ने कहा कि रसेल का टीम के साथ लंबा और भावनात्मक रिश्ता रहा है और जर्सी नंबर 12 उनके साथ खास पहचान बन चुका है। इसलिए इसे रिटायर कर उन्हें सम्मान दिया गया। वहीं, रसेल ने इस मौके पर भावुक होते हुए कहा कि केकेआर के साथ उनका सफर बेहद खास रहा है और फ्रेंचाइजी ने इस यात्रा को यादगार बना दिया।



वैभव के पास अच्छे बल्लेबाजी कौशल : जितेश



मुम्बई। विकेटकीपर बल्लेबाज जितेश शर्मा ने उभरते हुए युवा बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी की जमकर प्रशंसा की है। जितेश के अनुसार वैभव एक ऐसे बल्लेबाज हैं जो हमेशा आक्रामक बल्लेबाजी प्रसंद करते हैं। उनके पास अच्छे कौशल है और वह आने वाले समय में विश्व क्रिकेट में छा सकते हैं। वैभव ने केवल 15 साल की उम्र में ही काफी कुछ हासिल कर लिया है। पहले आईपीएल में ही उन्होंने 35 गेंदों में शतक लगाकर सबको हैरान कर दिया था। इसके बाद उन्होंने आस्ट्रेलिया, दक्षिण अफ्रीका और इंग्लैंड में भी शानदार प्रदर्शन किया। उन्होंने अंडर-19 विश्व कप में भी शानदार प्रदर्शन किया और फाइनल में इंग्लैंड के खिलाफ 175 रन की मैच जिताऊ पारी खेली। इसके बाद भी इस बार आईपीएल में उनकी राह आसान नहीं रहेगी। इस बार उनकी कड़ी परीक्षा होगी। पिछले सीजन में शानदार प्रदर्शन के बाद अब सभी टीमों के गेंदबाज उनकी बल्लेबाजी का आकलन कर उनका कमजोर पक्ष निकालने का प्रयास कर रहे हैं और उन सभी का लक्ष्य उस क्षेत्र में गेंदबाजी करना रहेगा जिसमें वह कमजोर हैं। इस बार टीम में संजु सैमसन के नही होने से भी वैभव को बड़ी जिम्मेदारी निभानी होगी। ये भी हो सकता है कि उन्हें यशरवी जायसवाल के साथ पारी शुरू करने का अवसर मिल सकता है।

आईपीएल 2026 से पहले टीमों को झटका, 9 विदेशी खिलाड़ी शुरुआती मैचों से बाहर

नई दिल्ली

इंडियन प्रीमियर लीग 2026 की शुरुआत 28 मार्च से होने जा रही है, लेकिन सीजन के आगाज से पहले ही कई टीमों को बड़ा झटका लगा है। फिटनेस और अन्य कारणों के चलते कुल 9 विदेशी खिलाड़ी शुरुआती मुकाबलों में हिस्सा नहीं ले पाएंगे, जिससे टीम संयोजन पर असर पड़ना तय है। खास बात यह है कि इनमें चार खिलाड़ी आस्ट्रेलिया के हैं, जो अपनी-अपनी टीमों के लिए अहम भूमिका निभाते हैं। सनराइजर्स हैदराबाद के कप्तान पैट कमिंस पूरी तरह फिट नहीं हैं और शुरुआती मैचों से बाहर रहेंगे। उनकी गैरमौजूदगी में टीम की कप्तान इशान किशन को सौंपी गई है। वहीं रायल चैलेंजर्स बेंगलुरु के तेज गेंदबाज जोशा हेजलवुड भी चोट से उबर रहे हैं और संभावना है कि वह 12 अप्रैल को मुंबई



इंडियंस के खिलाफ मैच से पहले टीम से जुड़ेंगे। दिल्ली कैपिटल्स को भी बड़ा झटका लगा है, क्योंकि उनके स्टार तेज रायल चैलेंजर्स बेंगलुरु के तेज गेंदबाज जोशा हेजलवुड भी चोट से उबर रहे हैं और संभावना है कि वह 12 अप्रैल को मुंबई

है। इसके अलावा चेन्नई सुपरकिंग्स के खिलाड़ी मैथ्यू शार्ट अंगुठे में फ्रैक्चर के कारण शुरुआती मुकाबलों से बाहर रहेंगे। पंजाब किंग्स के तेज गेंदबाज लाकी फर्ग्यूसन भी शुरुआती सात मैचों में उपलब्ध नहीं रहेंगे, क्योंकि वह

परिवारिक कारणों से अपने देश में हैं। कोलकाता नाइट राइडर्स के श्रीलंकाई गेंदबाज मथीशा पथिराना भी सीजन के पहले दो हफ्तों के लिए बाहर रहेंगे। लखनऊ सुपर जायंट्स के स्मिथर वॉन्डरिंग हस्रंगा चोटिल हैं और उनके शुरुआती मैचों में खेलने पर संशय बना हुआ है। सनराइजर्स हैदराबाद के ही इशान मल्लिंगा कंधे की चोट के चलते श्रीलंका में हैं और फिटनेस टेस्ट पास करने के बाद ही टीम से जुड़ पाएंगे। वहीं रायल चैलेंजर्स बेंगलुरु के नुवान तुषारा को भी फिटनेस क्वीरेंस मिलने के बाद ही खेलने की अनुमति मिलेगी। इन खिलाड़ियों की अनुपस्थिति से आईपीएल 2026 के शुरुआती मुकाबलों में टीमों को अपने संयोजन में बदलाव करना पड़ेगा, जिससे टूर्नामेंट को शुरुआत और भी दिलचस्प होने की उम्मीद है।

भारतीय महिला क्रिकेट टीम में शामिल अनुष्का को मुख्यमंत्री मोहन यादव ने शुभकामनाएं भी

ग्यालियर। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने ग्यालियर की अनुष्का शर्मा को दक्षिण अफ्रीका दौरे के लिए भारतीय महिला क्रिकेट टीम में शामिल किये जाने पर खुशी जतायी है। मुख्यमंत्री ने मंगलवार शाम ग्यालियर परामर्श पर अनुष्का का स्वागत कर उन्हें भविष्य के लिए शुभकामनाएं भी दीं। भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच 17 अप्रैल से पांच मैचों की टी20 सीरीज खेली जाएगी। 22 वर्षीय बैटिंग आल राउंडर अनुष्का ने महिला प्रीमियर लीग (डब्ल्यूपीएल) में जगह मिली महिला टी20 विश्वकप से पहले भारतीय टीम हरमनप्रीत कौर की कप्तानी में दक्षिण अफ्रीका और इंग्लैंड का दौरा करेगी। इसमें बेहतर प्रदर्शन करने वाली को ही विश्वकप में जगह मिलेगी। भारतीय टीम का दक्षिण अफ्रीका दौरा 17 अप्रैल से शुरू हो रहा है, जहां उसे मेजबान टीम से पांच मैचों की टी20 सीरीज खेनी है। इस सीरीज के लिए अनुष्का को पहली बार शामिल किया गया है। अनुष्का शर्मा दाएं हाथ की बल्लेबाज होने के साथ ही ऑफ स्पिन गेंदबाजी भी करती हैं इससे पहले डब्ल्यूपीएल में उन्हें गुजरात जायंट्स ने 45 लाख रुपये में खरीदा था। उन्होंने अपनी टीम की ओर से 7 मैचों में 129.19 के स्ट्राइक रेट से कुल 177 रन बनाए थे।

सीजन के अंत में लिवरपूल छोड़ेंगे मोहम्मद सालाह, भावुक संदेश में किया ऐलान



नई दिल्ली

मोहम्मद सालाह ने मंगलवार को बड़ा ऐलान करते हुए कहा कि वह मौजूदा सत्र के अंत में लिवरपूल फुटबाल क्लब को छोड़ देंगे। सालाह ने सोशल मीडिया पर साझा किए गए एक वीडियो में अपने विदाई संदेश की शुरुआत करते हुए इस फैसले की पुष्टि की।

33 वर्षीय सालाह ने कहा, दुर्भाग्य से यह दिन आ गया है। यह मेरी विदाई का पहला हिस्सा है। मैं इस सत्र के अंत में लिवरपूल छोड़ दूंगा। उन्होंने क्लब, शहर और प्रशंसकों के साथ अपने गहरे जुड़ाव को याद करते हुए इसे अपने जीवन का अहम हिस्सा बताया। सालाह लिवरपूल के इतिहास में तीसरे सबसे ज्यादा गोल करने वाले खिलाड़ी हैं। उन्होंने 435 मैचों में 255 गोल किए हैं और इस सूची में केवल इयान राश और रोजर हंट उनसे आगे हैं। 2017 में क्लब से जुड़ने के बाद उन्होंने दो प्रीमियर लीग खिताब, चैंपियंस लीग, एफए कप, सुपर कप, क्लब विश्व कप और लीग कप जैसे कई

बड़े खिताब जीते। उन्होंने अपने संदेश में कहा कि उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि यह क्लब और यहां के लोग उनके जीवन का इतना बड़ा हिस्सा बन जाएंगे। उन्होंने अपने साथियों और प्रशंसकों का धन्यवाद करते हुए कहा कि उनके करियर के सबसे अच्छे और कठिन समय में मिले समर्थन को वह कभी नहीं भूलेंगे।

मोहम्मद सालाह ने यह भी कहा कि लिवरपूल हमेशा उनके दिल में रहेगा और यह क्लब उनके लिए घर जैसा रहेगा।

उन्होंने भावुक शब्दों में कहा, यहां से जाना आसान नहीं है, लेकिन मैं हमेशा इस क्लब का हिस्सा रहूंगा। गौरतलब है कि सालाह ने 2019-20 सत्र में लिवरपूल को 30 साल बाद लीग खिताब दिलाते में अहम भूमिका निभाई थी। हालांकि, पिछले साल नवंबर में क्लब के कोच आर्न स्लॉट के साथ मतभेदों की खबरों भी सामने आई थीं, जिसने उनके भविष्य को लेकर अटकलों को और तेज कर दिया था।

न्यूजीलैंड क्रिकेट हाल आफ फेम में जेरेमी कोनी और हैडी टिफेन शामिल

वेलिंगटन

न्यूजीलैंड क्रिकेट ने अपने हाल आफ फेम में पूर्व आलराउंडर जेरेमी कोनी और हैडी टिफेन को शामिल किया है। यह पिछले साल घोषित फर्स्ट इलेवन के बाद पहली बार नए नाम जोड़े गए हैं।



जेरेमी कोनी ने 1974 से 1987 के बीच अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट खेला और 1980 के दशक में न्यूजीलैंड टीम के स्वर्णिम दौर में अहम भूमिका निभाई। उनकी कप्तानी में टीम ने 1985 और 1986 में तीन ऐतिहासिक टेस्ट सीरीज जीत दर्ज की, जिसमें आस्ट्रेलिया को हराकर और न्यूजीलैंड में तथा इंग्लैंड को इंग्लैंड में हराकर शामिल था। कोनी ने 52 टेस्ट मैचों में 2668 रन बनाए, जिसमें तीन शतक और 115 अर्धशतक शामिल हैं, जबकि गेंदबाजी में 27 विकेट लिए। वनडे क्रिकेट में उन्होंने 88 मैचों में 1874

रन और 54 विकेट हासिल किए। संन्यास के बाद वे सफल कमेंटरेटर और प्रस्तुतकर्ता बने। वहीं, हैडी टिफेन को न्यूजीलैंड की सर्वश्रेष्ठ महिला क्रिकेटर्स में गिना जाता है। उन्होंने 1999 में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ 19 साल की उम्र में अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में पदार्पण किया। टिफेन ने 117 वनडे मैचों में 2919 रन बनाए, जिसमें एक शतक और 18 अर्धशतक शामिल हैं, साथ ही 49 विकेट भी लिए। उन्होंने दो टीस्ट और नौ टी20 अंतरराष्ट्रीय मैच भी खेले। कप्तान के रूप में उन्होंने टीम को 2009 विश्व कप के फाइनल तक

पहुंचाया। संन्यास के बाद उन्होंने न्यूजीलैंड महिला टीम को कोचिंग भी दी। टिफेन ने इस सम्मान पर खुशी जताते हुए कहा कि यह उनके लिए बहुत बड़ा गौरव है और वह उन दिग्गज खिलाड़ियों के साथ शामिल होकर सम्मानित महसूस कर रही हैं, जिन्होंने उन्हें प्रेरित किया। गौरतलब है कि पिछले साल हाल आफ फेम को शुरुआत के दौरान बर्ट स्टर्क्सलफ, जान आर. रोड, जैकी लार्ड, टिश मैककल्वी, ग्लेन टर्नर, सर रिचर्ड हैडली, डेबी हाकले, मार्टिन क्रो, एमिली ड्रूम, डेनियल विटोरी और ब्रेंडन मैककुलम जैसे दिग्गजों को शामिल किया गया था। हाल आफ फेम में शामिल होने के लिए खिलाड़ी का न्यूजीलैंड का प्रतिनिधित्व करना और कम से कम पांच साल पहले संन्यास लेना जरूरी है। चयन खिलाड़ियों के प्रदर्शन, नेतृत्व क्षमता और उनके प्रभाव को ध्यान में रखकर किया जाता है। कोनी और टिफेन को औपचारिक रूप से न्यूजीलैंड क्रिकेट अवार्ड्स के दौरान सम्मानित किया जाएगा।

बच्चा जानता है, क्या बड़े भी जानते हैं..

असम की नागरिक चेतना की परीक्षा



जाहद अहमद तापादार

एक ऐसा पल आता है जो चुपचाप असम के भविष्य में आपका विश्वास जगा देता है। गुवाहाटी की व्यस्त सड़कों से एक कार गुजर रही है। खिड़की से एक प्लास्टिक की बोतल बाहर फेंकी जाने वाली है। और तभी पीछे की सीट से एक छोटी सी आवाज आती है — पापा, इसे बाहर मत फेंको। इसे बैग में रख दो। पिता रुक जाते हैं। और बोतल को अंदर ही रख लेते हैं।

उस बच्चे ने यह बात किसी सरकारी अभियान से नहीं सीखी थी। किसी अधिकारी ने उसे ऐसा करने का आदेश नहीं दिया था। यह उसके अंदर से आया था — एक बढ़ती हुई, सच्ची जागरूकता से कि सार्वजनिक स्थान सभी के होते हैं और उनके साथ सम्मानजनक व्यवहार किया जाना चाहिए। पूरे गुवाहाटी और असम के कई हिस्सों में, यह चेतना चुपचाप लेकिन स्पष्ट रूप से बढ़ रही है। आप इसे नागरिकों में देखते हैं जो विनम्रता से, लेकिन दृढ़ता से, किसी ऐसे व्यक्ति से कूड़ा उठाने के लिए कहते हैं जिसे उसने अभी-अभी गिराया है। आप इसे उन यात्रियों में देखते हैं जो अपने बैग खुद उठाते हैं, कूड़ेदान का इस्तेमाल करते हैं, और एक शांत गरिमा के साथ यात्रा करते हैं जो बिना कुछ कहे ही एक मिसाल कायम करती है।

असम कोई नागरिक बंजर जमीन नहीं है। यहां के लोगों का एक बड़ा और बढ़ता हुआ तबका अपने आस-पास के माहौल पर सच्चा गर्व महसूस करता है। इस बात को स्वीकार किया जाना चाहिए, इसका जश्न मनाया जाना चाहिए, और इसे और आगे बढ़ाया जाना चाहिए।

लेकिन ईमानदारी की मांग यह भी है कि हम इस बात पर नजर डालें कि हमारे बीच का एक तबका क्या करता जा रहा है

— और वह तबका बाकी सभी को कितना नुकसान पहुंचा रहा है।

हर सुबह, गुवाहाटी में सड़क किनारे की नालियां प्लास्टिक की बोतलों और कूड़े-कचरे से अटी पड़ी होती हैं। अभी दिन आधा भी नहीं बीता होता कि ताजा साफ किए गए फुटपाथ थूक के दागों से भर जाते हैं। एनएच-37 पर, बाईपास पर, और पूरे शहर की सड़कों पर, कारों की खिड़कियों ताजी हवा के लिए नहीं, बल्कि रैपर और कचरा बाहर फेंकने के लिए नीचे की जाती हैं — और इस तरह, सफाई कर्मचारियों की थोर से पहले की गई सारी मेहनत कुछ ही सेकंड में बेकार हो जाती है। यह व्यवहार सभी का नहीं है। लेकिन यह काफी लोगों का व्यवहार है — इतना काफी कि शहर वैसा ही दिखता है जैसा वह आज है, और इतना काफी कि जिम्मेदार नागरिकों की मेहनत हमेशा अधूरी ही लगती है।

यह नागरिक लापरवाही सिर्फ सड़कों तक ही सीमित नहीं है। यह हमारे रहने की जगहों में भी घुस जाती है। गुवाहाटी के कई अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स में, कुछ लोग अपने पड़ोसियों और अपार्टमेंट कमेटीयों के बार-बार कहने के बाद भी कूड़े के बैग इस्तेमाल नहीं करते। वे अपने कूड़ेदान सीधे अपने फ्लैट से लाते हैं और उन्हें सीधे कामन कूड़ादान में खाली कर देते हैं — जिसमें किचन का सड़ा-गला कूड़ा, खाने के बचे हुए दुकड़े, और इससे भी बदतर चीजें होती हैं। इस बदबू से मच्छर और कीड़े-मकोड़े आते हैं। इससे भी ज्यादा परेशान करने वाली बात यह है कि अपार्टमेंट कैंपस की खुली जगहों पर सैनिटरी नैपकिन सीधे फेंक दिए जाते हैं — जो साथ रहने वाले लोगों की गरिमा और सेहत के प्रति पूरी तरह से लापरवाही दिखाता है। और फिर भी, उसी बिल्डिंग में, दूसरे लोग अपना कूड़ा सावधानी



से सीलबंद कूड़े के बैग में पैक करते हैं और जीएमसी के कूड़ा उठाने के लिए सही पड़ोसियों और अपार्टमेंट कमेटीयों के बार-बार कहने के बाद भी कूड़े के बैग इस्तेमाल नहीं करते। वे अपने फ्लैट से लाते हैं और उन्हें सीधे कामन कूड़ादान में खाली कर देते हैं — जिसमें किचन का सड़ा-गला कूड़ा, खाने के बचे हुए दुकड़े, और इससे भी बदतर चीजें होती हैं। इस बदबू से मच्छर और कीड़े-मकोड़े आते हैं। इससे भी ज्यादा परेशान करने वाली बात यह है कि अपार्टमेंट कैंपस की खुली जगहों पर सैनिटरी नैपकिन सीधे फेंक दिए जाते हैं — जो साथ रहने वाले लोगों की गरिमा और सेहत के प्रति पूरी तरह से लापरवाही दिखाता है। और फिर भी, उसी बिल्डिंग में, दूसरे लोग अपना कूड़ा सावधानी

लेकिन यह इतनी नियमितता से होता है कि एक पैटर्न बन गया है, और यह पैटर्न हर दिन असली लोगों को सच में तकलीफ पहुंचाता है।

असम की प्रीमियम ट्रेनों — वंदे भारत और जन शताब्दी — में भी यही सच है। ज्यादातर यात्री शांत, समझदार और अच्छे किचन का सड़ा-गला कूड़ा, खाने के बचे हुए दुकड़े, और इससे भी बदतर चीजें होती हैं। इस बदबू से मच्छर और कीड़े-मकोड़े आते हैं। इससे भी ज्यादा परेशान करने वाली बात यह है कि अपार्टमेंट कैंपस की खुली जगहों पर सैनिटरी नैपकिन सीधे फेंक दिए जाते हैं — जो साथ रहने वाले लोगों की गरिमा और सेहत के प्रति पूरी तरह से लापरवाही दिखाता है। और फिर भी, उसी बिल्डिंग में, दूसरे लोग अपना कूड़ा सावधानी

यात्री नहीं था। यह एक अंधे उम्र का, देखने में पढ़ा-लिखा आदमी था जो एजीक्यूटिव क्लास में सफर कर रहा था — और उसे अपने किए में कुछ भी गलत नहीं लगा।

यही वह विरोधाभास है जो इस समस्या को इतना ज्यादा निराशाजनक बना देता है। पीछे की सीट पर बैठा बच्चा, गाड़ी चला रहे बड़े से ज्यादा नागरिक जिम्मेदारी को समझता है। शिक्षा, आमदनी और उम्र ने उन लोगों में नागरिक बोध की गारंटी नहीं दी है जिनमें इसकी कमी है — और कोई भी कानून, अभियान या नारा वह चीज पैदा नहीं कर सकता जो आखिरकार इसान की अपनी अंतरात्मा से ही आनी चाहिए।

लेकिन जब तक हम उस अंतरात्मा के जागने का इंतजार कर रहे हैं, तब तक इसके नतीजों को असल बनाना होगा। कूड़ा न फैलाने के लिए लगाए जाने वाले जुमाने को साफ तौर पर और बिना किसी अपवाद के लागू किया जाना चाहिए। जिन गाड़ियों से कूड़ा फेंकते हुए पकड़ा जाए, उनका चालान किया जाना चाहिए। ट्रेनों में टीटीई को शोर-शराबे से जुड़े नियमों को सख्ती से लागू करने का अधिकार दिया जाना चाहिए — ठीक वैसे ही जैसे एयरलाइंस करती हैं, बिना किसी माफी के। हाउसिंग सोसाइटीयों में कूड़ा प्रबंधन के ऐसे नियम होने चाहिए जिन्हें सख्ती से लागू किया जा सके और जिनकी असली जवाबदेही तय

हो । और हम में से जो जिम्मेदार बहुमत हैं, उसे नागरिक नियमों के उल्लंघन को देखते समय बोलने की हिम्मत जुटानी चाहिए — आक्रामक होकर नहीं, बल्कि साफ-साफ। क्योंकि, गलत के सामने चुप रहना अपने आप में एक तरफ की इजाजत देना ही है।

असम एक ऐसा राज्य है जहां की प्राकृतिक सुंदरता सांस थाम देने वाली है, जहां गहरा सांस्कृतिक गौरव है और जहां अपार संभावनाएं हैं। लेकिन किसी शहर, किसी राज्य या किसी समाज का आकलन आखिरकार सिर्फ उसके सबसे अच्छे नागरिकों से ही नहीं होता — बल्कि इस बात से भी होता है कि वह अपने बाकी नागरिकों को कितनी सख्ती से जवाबदेह ठहराता है। पीछे की सीट पर बैठा बच्चा पहले से ही जानता है कि क्या सही है। सवाल यह है कि क्या गाड़ी चला रहा बड़ा उसकी बात सुनने के लिए तैयार है।

असम का रहस्यमयी विष्णु मंदिर, जहां मन्नत पूरी होने पर चढ़ाए जाते हैं जिंदा कछुए



भारत के असम राज्य में कामरूप जिले के हाजो में श्री हयग्रीव माधव मंदिर स्थित है। यह मंदिर न सिर्फ अपनी वास्तुकला बल्कि अनोखी परंपराओं के लिए भी फेमस है। मणिमूक पर्वत पर बना यह मंदिर सदियों से बौद्ध और हिंदू धर्म के लोगों के लिए बड़ा आस्था का केंद्र रहा है। इस मंदिर की खासियत यह है कि भक्त भगवान श्रीविष्णु को प्रसन्न करने के लिए कछुए का चढ़ावा करते हैं। ऐसे में आज इस आर्टिकल के जरिए हम आपको

इस मंदिर का महत्व, अनुठी परंपरा और बौद्ध धर्म से खास जुड़ाव के बारे में बताते जा रहे हैं। इस मंदिर का इतिहास काफी प्राचीन है। धार्मिक मान्यताओं के मुताबिक यहां भगवान श्रीविष्णु के हयग्रीव अवतार की पूजा की जाती है। माना जाता है कि श्रीविष्णु ने इसी स्थान पर मधु-कैतभ नामक दोनों राक्षसों का वध किया था। माना जाता है कि इस मंदिर का निर्माण 1583 में कोच राजा रघुदेव नारायण द्वारा कराया गया था। वहीं कुछ लोग

प्रजाति के कछुए रहते हैं। यहां की परंपरा है कि भक्त अपनी मनोकामना पूरी होने पर या फिर भगवान को श्रद्धा अर्पित करने के लिए कछुओं को खाना खिलाते हैं। या फिर तालाब में कछुए छोड़ते हैं। इन कछुओं को भगवान विष्णु का कूर्म अवतार माना जाता है। वहीं स्थानीय लोग इन कछुओं को सुरक्षा का खास ख्याल रखते हैं और इनको कभी नुकसान नहीं पहुंचाते हैं। हयग्रीव माधव मंदिर की खासियत यह भी है कि यहां पर सिर्फ हिंदू ही नहीं, बल्कि भारी संख्या में बौद्ध अनुयायी भी आते हैं। तिब्बती बौद्धों का मानना है कि यह वही स्थान है, जहां पर स्वयं भगवान बुद्ध ने निर्वाण प्राप्त किया था। इस कारण बौद्ध अनुयायी इस मंदिर को काफी पवित्र मानते हैं और इसको महामुनि का मंदिर कहते हैं। श्री हयग्रीव माधव मंदिर संस्कृति, धर्म और वन्यजीव संरक्षण का एक अनूठा उदाहरण है। यहां की शांति और सदियों पुरानी परंपराएं इसको भारत के अन्य मंदिरों से अलग बनाती हैं। वहीं अगर आप असम की यात्रा पर जा रहे हैं, तो हाजो के तालाब में सैकड़ों दुर्लभ



बॉलीवुड पर बरसीं अमीषा पटेल, फिल्म इंडस्ट्री में कास्टिंग को लेकर छेड़ी नई बहस

बॉलीवुड अभिनेत्री अमीषा पटेल ने फिल्म इंडस्ट्री में कास्टिंग को लेकर एक नई बहस छेड़ी दी है। उन्होंने हाल ही में रिलीज हुई फिल्म धुरंधर 2: द रिवेज को जमकर तारीफ करते हुए निर्देशक आदित्य धर की सराहना की। सोशल मीडिया पर किए गए अपने पोस्ट में अमीषा ने कहा कि आज के दौर में जहां कलाकारों का चयन इस्टाग्राम फॉलोअर्स के आधार पर किया जा रहा है, वहीं आदित्य धर ने सिर्फ प्रतिभाशाली कलाकारों को मौका देकर एक मिसाल पेश की है। अमीषा ने बॉलीवुड पर निशाना साधते हुए लिखा कि इंडस्ट्री को यह समझने की जरूरत है कि धुरंधर 2 एक फिल्म है, न कि सिर्फ एक



प्रोजेक्ट। उन्होंने कहा कि आदित्य धर ने असली कलाकारों को कास्ट किया है, न कि सोशल मीडिया पर ट्रेंड करने

भट्ट, कंगना रनौत, अल्लू अर्जुन, जूनियर एनटीआर, महेश बाबू और रजनीकांत जैसे कई बड़े सितारे भी फिल्म की तारीफ कर चुके हैं। फिल्म की स्टारकास्ट भी इन दिनों चर्चा का विषय बनी हुई है। मुकेश छाबड़ा द्वारा की गई कास्टिंग में रणवीर सिंह, आर माधवन, अर्जुन रामपाल और अक्षय खन्ना जैसे दिग्गज कलाकारों के साथ कई प्रतिभाशाली अभिनेताओं को भी अहम भूमिकाएं दी गई हैं। बॉक्स ऑफिस पर भी फिल्म शानदार प्रदर्शन कर रही है और भारतीय बाजार में 570 करोड़ रुपये से ज्यादा की कमाई कर चुकी है, जिससे यह साल की सबसे बड़ी हिट फिल्मों में शामिल हो गई है।

पेड़ी की शूटिंग में घायल हुए राम चरण

साउथ सुपरस्टार राम चरण अपनी आगामी फिल्म पेड़ी की शूटिंग के दौरान घायल हो गए हैं, जिससे उनके फैस चिंता में आ गए थे। हालांकि, अब उनकी टीम ने इस पूरे मामले पर सफाई देते हुए बताया है कि अभिनेता पूरी तरह सुरक्षित हैं और उनकी आंखों को कोई नुकसान नहीं पहुंचा है। यह हादसा 24 मार्च को एक एक्शन सीक्वेंस की शूटिंग के दौरान हुआ। रिपोर्ट के मुताबिक, राम चरण को एक आंख के ऊपर चोट लगी थी, जिसके चलते उन्हें चार टांके लगवाने पड़े। टीम के सूत्र ने स्पष्ट किया कि चोट आंख में नहीं, बल्कि उसके ऊपर लगी है और अभिनेता की आंख पूरी तरह सुरक्षित है। इस खबर के बाद फैंस ने राहत की सांस ली है। चोट लगने के बावजूद राम चरण ने शूटिंग से ब्रेक नहीं लिया और वह जल्द ही सेट पर लौट आए। पेड़ी एक स्पॉट्स-ड्रामा फिल्म है, जिसका निर्माण वृद्धि सिनेमाज के बैनर तले किया जा रहा है। गौरतलब है कि फिल्म का निर्देशन बुची बाबू सना कर रहे हैं और इसमें जाहवी कपूर भी मुख्य भूमिका में नजर आएंगी। फिल्म में ए.आर. रहमान का संगीत होगा और इसमें शिव राजकुमार, जगपति बाबू और दिव्येंदु भी अहम भूमिकाओं में दिखाई देंगे।



MEET OUR EXPERTS - APOLLO, CHENNAI

NEURO SURGERY CLINIC

CONDITIONS/SYMPTOMS:

- Fits
- Back pain
- Facial pain
- Seizures
- Neck pain
- Stiff back
- Brain tumors
- Cervical and lumbar
- Any neurological
- Cerebral stroke
- spondylitis
- problem

DR. SRINIVASAN PARAMASIVAM
M.Ch (Neurosurgery), MRCS (Ed), FINR(USA)
Consultant Neurosurgeon
Apollo Hospitals, Chennai

4th April 2026 9:00 am - 3:00 pm

APOLLO HOSPITALS, CHENNAI
REGIONAL OFFICE - GUWAHATI
Rajgarh Main Road, Opp-Bylane - 10, Guwahati - 781003

For appointments Call: 8404037649 / 0361-3102166